

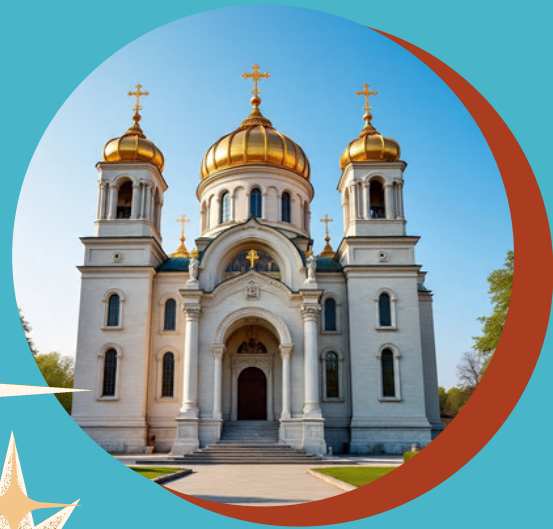


Exam Genius

India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK RAILWAY Exam



DECEMBER 2025 MONTH BANKING AND FINANCIAL AWARENESS



120+ MCQ
with detailed
explanation

- Banking & finance
- Banking Facilities
- Banking Appointment
- Banking Agreement



Ques: Which committee proposed the elevation of seven Chief General Managers to Executive Director positions in various Public Sector Banks?

कौन सी समिति ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सात चीफ जनरल मैनेजर को एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर पदोन्नत करने का प्रस्ताव दिया?

- A) Reserve Bank of India Committee / रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समिति
- B) Finance Ministry Advisory Committee / वित्त मंत्रालय सलाहकार समिति
- C) Appointments Committee of the Cabinet (ACC) / कैबिनेट नियुक्ति समिति
- D) Public Sector Bank Board / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बोर्ड
- E) Banking Regulatory Committee / बैंकिंग नियामक समिति

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Appointments Committee of the Cabinet (ACC) proposed elevating seven Chief General Managers (CGMs) to the position of Executive Director (ED) in various Public Sector Banks.
- कैबिनेट नियुक्ति समिति (ACC) ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सात चीफ जनरल मैनेजर (CGM) को एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (ED) के पद पर पदोन्नत करने का प्रस्ताव दिया।

Key appointments include:

- Amit Kumar Srivastava, Group Chief Risk Officer at PNB → ED of PNB (3-year term)
- Sunil Kumar Chugh, then CGM at PNB → ED of Canara Bank
- Amresh Prasad, CGM at PNB → ED of UBI
- Prabhat Kiran, CGM from Canara Bank → ED of BoM
- Mini T M, CGM at Bank of Baroda → ED of Indian Bank
- E. Ratan Kumar, CGM at CBI → ED of CBI
- Pramod Kumar Dwivedi, CGM at BoI → ED of BoI

Ques: What is the total deposit under PMJDY as of November 19, 2025?

19 नवंबर 2025 तक PMJDY के तहत कुल जमा राशि कितनी है?

- A) ₹1.95 lakh crore
- B) ₹2.50 lakh crore
- C) ₹2.75 lakh crore
- D) ₹3.10 lakh crore
- E) ₹4.00 lakh crore

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- As per the latest data (19 November 2025), deposits in PMJDY accounts have increased to ₹2.75 lakh crore.
- नवीनतम आंकड़ों (19 नवंबर 2025) के अनुसार, PMJDY खातों में जमा राशि बढ़कर ₹2.75 लाख करोड़ हो गई है।
- This reflects steady growth from ₹2.61 lakh crore on March 31, 2025.
- यह 31 मार्च 2025 के ₹2.61 लाख करोड़ से निरंतर बढ़ोतरी को दर्शाता है।
- The scheme remains one of the world's largest financial inclusion programmes with over 57 crore beneficiaries.
- यह योजना 57 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के साथ विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में से एक है।

Ques: As of September 2025, what share of new home loans by value is held by Public Sector Banks (PSBs) in India?

सितंबर 2025 तक, भारत में नए होम लोन बैंकों के क्षेत्र सार्वजनिक में (से हिसाब के मूल्य) (PSBs) की हिस्सेदारी कितनी है?

- A) 30%
- B) 40%
- C) 50%
- D) 60%
- E) 70%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Public Sector Banks now hold a 50% share in new home loans by value, surpassing private banks in the segment.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नए होम लोन में (पर आधार के मूल्य) 50% हिस्सा है, जिससे उन्होंने इस क्षेत्र में निजी बैंकों को पीछे छोड़ दिया है।
- Around 40% of home loans exceed ₹75 lakh, indicating a rise in high-value home borrowing.
- लगभग 40% होम लोन ₹75 लाख से अधिक हैं, जो उच्च को वृद्धि में लोन होम वाले मूल्य-है। दर्शाता
- Number of active home loans grew 3.3% to 2.29 crore, driven by larger loan sizes rather than volume.
- सक्रिय होम लोन की संख्या 3.3% बढ़कर 2.29 करोड़ हो गई, जो मात्रा नहीं बल्कि बड़े लोन आकार द्वारा संचालित है।
- Total home loan market size reached ₹42.1 lakh crore (11.1% YoY growth, 2.1% QoQ growth).
- कुल होम लोन बाजार का आकार ₹42.1 लाख करोड़ हो गया) 11.1% वार्षिक वृद्धि, 2.1% त्रैमासिक वृद्धि।(
- Asset quality improved with 31–180 days overdue loans falling to 3% from 3.1% in June and 3.3% last year.
- संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ, 31–180 दिन की बकाया लोन दर जून में 3.1% और पिछले साल 3.3% से घटकर 3% हो गई।

Ques: What grade has the IMF given to India's national accounts statistics in its annual review?

IMF ने अपनी वार्षिक समीक्षा में भारत के राष्ट्रीय लेखा आँकड़ों को कौन सा ग्रेड दिया है?

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D
- E. None of the above / उपरोक्त में से कोई नहीं

Answer: C.

Explanation / व्याख्या:

- The International Monetary Fund (IMF), in its annual Article IV review, assigned a 'C' grade to India's national accounts statistics, which include GDP, GVA, and related macroeconomic indicators.
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी वार्षिक आर्टिकल IV समीक्षा में भारत के राष्ट्रीय लेखा आँकड़ों—जिनमें GDP, GVA और अन्य आर्थिक संकेतक शामिल हैं—को 'C' ग्रेड दिया।
- 'C' is the second-lowest grade in IMF's rating system, reflecting methodological weaknesses and data limitations.
- 'C' IMF की रेटिंग में दूसरा सबसे कम ग्रेड है, जो कार्यप्रणाली संबंधी कमजोरियों और डेटा सीमाओं को दर्शाता है।
- IMF cited outdated base year (2011–12) and the use of wholesale price indices for deflators as major issues.
- IMF ने पुराने आधार वर्ष (2011–12) और डिफ्लेटर के लिए थोक मूल्य सूचकांक के उपयोग को प्रमुख समस्याओं के रूप में बताया।
- It also highlighted sizeable discrepancies between production and expenditure method GDP estimates.
- IMF ने उत्पादन और व्यय विधि से GDP के आँकड़ों में बड़ी विसंगतियों को रेखांकित किया।
- India uses both income and expenditure approaches for GDP calculation. Despite the issues, across all data categories, India received an overall 'B' grade.
- भारत GDP की गणना के लिए आय और व्यय दोनों पद्धतियों का उपयोग करता है। इन समस्याओं के बावजूद, सभी श्रेणियों में कुल मिलाकर भारत को 'B' ग्रेड मिला है।

**Ques: What new feature did the BHIM app introduce for UPI Circle?
BHIM ऐप ने UPI Circle के लिए कौनकिया लॉन्च फीचर नया सा-?**

- A) QR Code Payments / क्यूआर कोड भुगतान
- B) Full Delegation for Payments / भुगतानों के लिए पूर्ण प्रतिनिधित्व
- C) Contactless NFC Payments / कॉन्टैक्टलेस एनएफसी भुगतान
- D) Bill Splitting / बिल विभाजन
- E) Cross-Bank Transfers / बैंकस्थानांतरण बैंक-से-

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The BHIM app launched a full delegation feature for UPI Circle, allowing primary users to authorize trusted secondary contacts to make UPI payments from their account, with a maximum monthly limit of ₹15,000.
- BHIM ऐप ने UPI Circle के लिए पूर्ण प्रतिनिधित्व फीचर लॉन्च किया है, जो प्राथमिक उपयोगकर्ताओं को अपने भरोसेमंद द्वितीयक संपर्कों को उनके खाते से UPI भुगतान करने की अनुमति देता है, जिसकी अधिकतम मासिक सीमा ₹15,000 है।
- Each primary account can delegate payments to up to five secondary users, while each secondary user can be linked to only one primary account.
- प्रत्येक प्राथमिक खाता अधिकतम पांच द्वितीयक उपयोगकर्ताओं को भुगतान प्रतिनिधित्व दे सकता है, और प्रत्येक द्वितीयक उपयोगकर्ता केवल एक प्राथमिक खाते से जुड़ा हो सकता है।
- UPI Circle was launched in 2024 and allows partial and full delegation of payments.
- UPI Circle 2024 में लॉन्च किया गया था और यह भुगतान के आंशिक और पूर्ण प्रतिनिधित्व की सुविधा प्रदान करता है।

Ques: Which SBI-promoted entity plans to raise ₹2,000 crore for its third climate-focused fund to invest in startups?

कौन सी SBI-प्रोत्साहित संस्था स्टार्टअप्स में निवेश के लिए अपने तीसरे जलवायु फंड केंद्रित-लिए ₹2,000 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है?

- A) SBI Capital Markets / SBI कैपिटल मार्केट्स
- B) SBI Mutual Fund / SBI म्यूचुअल फंड
- C) SBI Ventures / SBI वेंचर्स
- D) SBI Life Insurance / SBI लाइफ इंश्योरेंस
- E) SBI Holdings / SBI होल्डिंग्स

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- SBI Ventures, promoted by State Bank of India, plans to raise ₹2,000 crore for

its third climate-focused fund to invest in startups.

- SBI वेंचर्स, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोत्साहित किया है, स्टार्टअप्स में निवेश के लिए अपने तीसरे जलवायु लिए फंड केंद्रित-₹2,000 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है।
- The fund will target early and growth-stage climate startups, especially those working on frontier climate technologies and AI-enabled climate innovations.
- यह फंड शुरुआती और ग्रोथकरेगा निवेश में स्टार्टअप्स जलवायु स्टेज-, खासकर उन स्टार्टअप्स में जो अग्रणी जलवायु तकनीकों और AI-सक्षम जलवायु नवाचारों पर काम कर रही हैं।
- Both domestic and global investors will be approached, with the roadshow starting early next year.
- इस फंड के लिए घरेलू और वैश्विक निवेशकों को शामिल किया जाएगा, और रोडशो अगले साल की शुरुआत में शुरू होगी।

Ques: India's Q2 GDP growth (July–September 2025-26) reached what level, marking the highest in six quarters?

2025-26 के Q2 (जुलाई–सितंबर की भारत में (GDP वृद्धि कितनी रही, जो छह तिमाहियों में सबसे अधिक है?

- A) 6.4%
- B) 7.8%
- C) 8.2%
- D) 7.0%
- E) 8.8%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- India's GDP growth for Q2 2025-26 surged to 8.2%, driven by strong performance in manufacturing and services, and supported by low inflation.
- 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की GDP वृद्धि 8.2% रही, जो विनिर्माण और सेवाओं के मजबूत प्रदर्शन तथा कम मुद्रास्फीति के कारण हुई।
- With two consecutive higher-than-expected quarters, the government raised the full-year GDP estimate to 7% or more.
- लगातार दो मजबूत तिमाहियों के बाद सरकार ने वार्षिक GDP अनुमान बढ़ाकर 7% या

उससे अधिक कर दिया।

- India outperformed all major economies in July–September growth, marking it the fastest-growing major economy.
- भारत ने जुलाई–सितंबर अवधि में सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे यह सबसे तेज़बना। अर्थव्यवस्था प्रमुख विकसित-

Ques: According to the Aventus Capital report, what is the projected total NBFC borrowings by FY27?

Aventus Capital रिपोर्ट के अनुसार FY27 तक NBFC की कुल उधारी कितनी होने का अनुमान है?

- A) USD 500 billion
- B) USD 620 billion
- C) USD 700 billion
- D) USD 750 billion
- E) USD 800 billion

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Non-Banking Financial Company (NBFC) borrowings are projected to grow at 13% CAGR through FY27.
- गैर) कंपनी वित्तीय बैंकिंग-NBFC) की उधारी FY27 तक 13% वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है।
- Total borrowings are expected to reach USD 750 billion by FY27.
- FY27 तक कुल उधारी 750 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
- Market-linked borrowings will rise to 64% of total NBFC borrowings by FY27, up from 43% in FY24.
- मार्केट हिस्सा का उधारी लिंकड-FY24 के 43% से बढ़कर FY27 में 64% होने की संभावना है।
- Share of bank credit is expected to decline (currently around 42%).
- बैंक क्रेडिट का हिस्सा घटने की संभावना है लगभग में वर्तमान)42%)।

Key funding instruments growing rapidly include:

- Non-Convertible Debentures (NCDs): ~25% CAGR; likely to exceed USD 330 billion by FY27
- External Commercial Borrowings (ECBs): 60% CAGR; expected to cross USD 120 billion by FY27
- Commercial Paper is also gaining preference

तेजी से बढ़ने वाले प्रमुख फंडिंग साधन:

- नॉन) डिबेंचर कन्वर्टिबल-NCDs): ~25% CAGR; FY27 तक 330 अरब डॉलर से अधिक
- एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग्स)ECBs): 60% CAGR; FY27 तक 120 अरब डॉलर पार
- कमर्शियल पेपर की मांग भी बढ़ रही है

Ques: Which bank signed an MoU with Financial Planning Standards Board India to promote financial planning excellence?

कौन सा बैंक वित्तीय योजना मानक बोर्ड इंडिया के साथ वित्तीय योजना में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु MoU पर हस्ताक्षरित हुआ?

- A) IDFC FIRST Bank / आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) SBI / एसबीआई

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- IDFC FIRST Bank signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Financial Planning Standards Board (FPSB) India, a subsidiary of FPSB Limited, to promote financial planning excellence.
- आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने वित्तीय योजना मानक बोर्ड)FPSB) इंडिया, जो FPSB लिमिटेड की सहायक कंपनी है, के साथ वित्तीय योजना में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु MoU पर हस्ताक्षर किए।

- The bank joins as an Approved Corporate Partner, with signatories Rahul Singh (Country Head, Private Banking, IDFC FIRST Bank) and Chandrakant Sureka (Interim CEO, FPSB India).
- बैंक ने अनुमोदित कॉर्पोरेट पार्टनर के रूप में भाग लिया, जिसके हस्ताक्षरकर्ता राहुल सिंह हेड कंट्री), प्राइवेट बैंकिंग, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अंतरिम) सुरेका चंद्रकांत और (CEO, FPSB इंडिया हैं। (
- The MoU aims to upskill Wealth Management Regional Managers through professional certification, strengthen hiring and career pathways for CFP professionals, and conduct joint programs to build a stronger financial planning ecosystem.
- यह MoU क्षेत्रीय वेल्थ मैनेजमेंट मैनेजर्स को पेशेवर प्रमाणन के माध्यम से कौशल बढ़ाने, CFP पेशेवरों के लिए भर्ती और करियर मार्ग मजबूत करने, और संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करके वित्तीय योजना पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखता है।

Ques: Which FPI received post-facto RBI approval to increase its stake in Suryoday Small Finance Bank in 2025?

किस FPI को 2025 में Suryoday Small Finance Bank में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए RBI की पश्चवर्ती मंजूरी मिली?

- A) 1729 Capital / 1729 कैपिटल
- B) BlackRock / ब्लैकरॉक
- C) Vanguard Group / वैनगार्ड ग्रुप
- D) Fidelity International / फिडेलिटी इंटरनेशनल
- E) T. Rowe Price / टीप्राइस रो .

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- Reserve Bank of India (RBI) granted post-facto approval to 1729 Capital, a SEBI-registered Foreign Portfolio Investor (FPI), to increase its stake in Suryoday Small Finance Bank (SSFB) from 3.81% (as of 30 September 2025) to 7.14%.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने SEBI-रजिस्टर्ड FPI 1729 Capital को Suryoday Small Finance Bank (SSFB) में अपनी हिस्सेदारी 3.81% (30 सितंबर 2025 तक बढ़ाकर से (

7.14% करने के लिए पञ्चवर्ती मंजूरी दी।

- The approval is conditional on compliance with the Banking Regulation Act, 1949, FEMA 1999, and applicable SEBI regulations.
- यह मंजूरी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949, FEMA 1999 और लागू SEBI नियमों के अनुपालन पर आधारित है।
- RBI removed the earlier restriction capping 1729 Capital's voting rights below 5%, but any future increase to 5% or more will require prior approval if the stake later falls below 5%.
- RBI ने पहले का प्रतिबंध हटाया, जो 1729 Capital के मतदान अधिकार को 5% से नीचे सीमित करता था, लेकिन भविष्य में 5% या उससे अधिक बढ़ोतरी के लिए पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी यदि हिस्सेदारी बाद में 5% से नीचे गिरती है।

About Suryoday Small Finance Bank :

- Established : 2017
- HQ : Navi Mumbai
- Tagline : A bank of smiles
- MD & CEO : Baskar Babu Ramachandran

Ques: How much penalty has RBI imposed on HDFC Bank for regulatory violations?

विनियामक उल्लंघनों के लिए RBI ने HDFC बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है?

- A) ₹50 lakh
- B) ₹75 lakh
- C) ₹91 lakh
- D) ₹1.5 crore
- E) ₹2 crore

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- RBI imposed a penalty of ₹91 lakh on HDFC Bank for violations related to the Banking Regulation Act and deficiencies in statutory and regulatory compliance, including KYC-related lapses.

- RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम और सांविधिक एवं नियामक अनुपालन में कमियों, विशेषकर KYC से संबंधित त्रुटियों के लिए HDFC बैंक पर ₹91 लाख का जुर्माना लगाया।
- The penalty was based on findings from the Statutory Inspection for Supervisory Evaluation conducted on the bank's financial position as of March 31, 2024.
- यह जुर्माना बैंक की 31 मार्च 2024 तक की वित्तीय स्थिति के आधार पर की गई वैधानिक निरीक्षण (Statutory Inspection for Supervisory Evaluation) के निष्कर्षों पर आधारित था।

Ques: What is India Ratings & Research's revised GDP growth forecast for FY26?

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का FY26 के लिए संशोधित GDP वृद्धि पूर्वानुमान क्या है?

- A) 6.0%
- B) 6.3%
- C) 6.8%
- D) 7.0%
- E) 7.5%

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- India Ratings & Research raised India's GDP forecast for FY26 to 7%, up from the earlier 6.3% projected in July 2025.
- इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने FY26 के लिए भारत की GDP वृद्धि पूर्वानुमान को 7% किया, जो जुलाई 2025 में अनुमानित 6.3% से बढ़ा है।
- The Reserve Bank of India projects growth at 6.8% for FY26, compared to 6.5% in FY25.
- भारतीय रिज़र्व बैंक FY26 के लिए 6.8% की वृद्धि का अनुमान लगाता है, जबकि FY25 में यह 6.5% थी।
- Growth drivers include strong Q1 FY26 growth of 7.8%, lower-than-expected impact of US tariff hikes, declining inflation leading to higher real wages, and GST rate changes boosting rural consumption.
- वृद्धि के प्रमुख कारकों में Q1 FY26 में 7.8% की मजबूत वृद्धि, अमेरिकी टैरिफ वृद्धि का अपेक्षा से कम प्रभाव, कम मुद्रास्फीति से उच्च वास्तविक वेतन, और ग्रामीण क्षेत्रों में GST दर

बदलाव के कारण बढ़ी हुई खपत शामिल हैं।

- Private Final Consumption Expenditure is expected to grow 7.4% in FY26, higher than 7.2% in FY25.
- निजी अंतिम खपत व्यय FY26 में 7.4% बढ़ने की उम्मीद है, जो FY25 के 7.2% से अधिक है।

Ques: As per the ICICI report, what is the projected GDP growth for India in FY26?

ICICI रिपोर्ट के अनुसार FY26 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी है?

- A) 6.0%
- B) 6.5%
- C) 7.0%
- D) 7.6%
- E) 8.0%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- H1 FY26 GDP growth is projected at 7.6%, higher than 6.1% in H1 FY25.
- FY26 की पहली छमाही की GDP वृद्धि 7.6% रहने का अनुमान है, जो H1 FY25 के 6.1% से अधिक है।
- Growth is supported by manufacturing, services, and government spending.
- विनिर्माण, सेवाओं और सरकारी खर्च से वृद्धि को समर्थन मिल रहा है।
- H2 FY26 growth may moderate to 6.4% due to lower exports and slower government capital expenditure.
- निर्यात में कमी और सरकारी पूंजीगत खर्च की धीमी गति के कारण FY26 की दूसरी छमाही में वृद्धि 6.4% तक कम हो सकती है।
- Consumption is expected to remain strong and resilient.
- उपभोग मजबूत और स्थिर रहने की संभावना है।
- The Centre has fiscal space to maintain spending if divestment and resource mobilisation improve.
- यदि विनिवेश और संसाधन जुटाव बेहतर होता है, तो केंद्र के पास खर्च बनाए रखने की क्षमता है।

• **For July–September FY26:**

- Real GDP growth expected at 7.5% YoY
- GVA growth expected at 7.3% YoY

• **Full-year forecasts:**

- FY26 GDP growth: 7.0%
- FY27 GDP growth: 6.5%

Ques: How many consolidated Master Directions were issued by the RBI after reviewing past regulatory instructions?

RBI ने पुराने नियामक निर्देशों की समीक्षा के बाद कितने समेकित मास्टर निर्देश जारी किए?

- A) 122
- B) 200
- C) 244
- D) 350
- E) 500

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) reviewed around 3,500 directions, circulars, and guidelines issued over several decades and consolidated them into 244 Master Directions.
- RBI ने कई दशकों में जारी लगभग 3,500 निर्देशों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों की समीक्षा की और उन्हें समेकित कर कुल 244 मास्टर निर्देश जारी किए।
- These Master Directions replace 9,446 old circulars, aiming to reduce the compliance burden on regulated entities.
- ये नए मास्टर निर्देश 9,446 पुराने परिपत्रों को भी निरस्त करते हैं, जिससे विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन का बोझ कम हुआ है।
- The instructions are organized based on regulatory areas and types of regulated entities, covering 11 types including commercial banks, NBFCs, cooperative banks, AIFs, and credit information companies.

- निर्देश अब नियामक क्षेत्रों और संस्थाओं के प्रकार के अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं, जिसमें वाणिज्यिक बैंक, NBFC, सहकारी बैंक, AIFI और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कम्पनियां सहित 11 प्रकार की संस्थाएं शामिल हैं।

Ques: Which state is receiving a USD 400 million loan from ADB for road connectivity upgrades?

किस राज्य को सड़क संपर्क सुधार के लिए ADB से 400 मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त हो रहा है?

- A) Gujarat / गुजरात
- B) Maharashtra / महाराष्ट्र
- C) Karnataka / कर्नाटक
- D) Tamil Nadu / तमिलनाडु
- E) Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Asian Development Bank (ADB) has provided a USD 400 million loan to Maharashtra to upgrade state highways and rural roads across 34 districts.
- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने महाराष्ट्र को 34 जिलों में राज्य राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए 400 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है।
- The project will support the upgradation of around 350 km of state highways and 2,577 km of rural roads.
- इस परियोजना से लगभग 350 किलोमीटर राज्य राजमार्गों और 2,577 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के उन्नयन में मदद मिलेगी।

Ques: Which two Indian states received a USD 776 million loan from the World Bank for education and climate-resilient agriculture projects?

शिक्षा और जलवायु से बैंक विश्व लिए के परियोजनाओं कृषि प्रतिरोधी-776 मिलियन USD का ऋण किस दो भारतीय राज्यों को मिला?

- A) Haryana and West Bengal / हरियाणा और पश्चिम बंगाल
- B) Gujarat and Rajasthan / गुजरात और राजस्थान
- C) Karnataka and Tamil Nadu / कर्नाटक और तमिलनाडु
- D) Uttar Pradesh and Bihar / उत्तर प्रदेश और बिहार
- E) Punjab and Maharashtra / पंजाब और महाराष्ट्र

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- The World Bank approved a loan of USD 776 million (around ₹6,467 crore) for two projects in India: improving education in Punjab and advancing climate-resilient agriculture in Maharashtra.
 - विश्व बैंक ने भारत में दो परियोजनाओं के लिए 776 मिलियन USD (लगभग ₹6,467 करोड़ में पंजाब :किया मंजूर ऋण का (शिक्षा सुधारने और महाराष्ट्र में जलवायु प्रतिरोधी-लिए) के देने बढ़ावा को कृषि
 - Punjab Projects: Punjab Outcomes-Acceleration in School Education Operation (POISE) – USD 286 million with a final maturity of 19 years plus a 5-year grace period.
 - पंजाब परियोजनाएं) ऑपरेशन एजुकेशन स्कूल इन एक्सलेरेशन-आउटकम्स पंजाब :POISE) – 286 मिलियन USD, जिसकी अंतिम परिपक्वता अवधि 19 वर्ष और 5 साल की ग्रेस पीरियड है।
 - Maharashtra Projects: Project on Climate Resilient Agriculture (POCRA) Phase II – USD 490 million with a final maturity of 24 years plus a 6-year grace period.
 - महाराष्ट्र परियोजनाएं) प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर रेसिलिएंट क्लाइमेट :POCRA) चरण II – 490 मिलियन USD, जिसकी अंतिम परिपक्वता अवधि 24 वर्ष और 6 साल की ग्रेस पीरियड है।
-

Ques: Which new loan product has South Indian Bank launched to help customers consolidate multiple loans?

किस नए ऋण उत्पाद को दक्षिण भारतीय बैंक ने ग्राहकों को कई ऋणों को एकीकृत करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया है?

- A) SIB Flexi Loan / SIB फ्लेक्सी लोन
- B) SIB Power CONSOL / SIB पावर कंसोल
- C) SIB Quick Credit / SIB क्विक क्रेडिट

- D) SIB Home Advantage / SIB होम एडवांटेज
E) SIB Personal Plus / SIB पर्सनल प्लस

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- South Indian Bank launched the SIB Power CONSOL loan scheme, which allows customers to consolidate multiple loans into a single Equated Monthly Instalment (EMI).
- दक्षिण भारतीय बैंक ने SIB पावर कंसोल लोन योजना लॉन्च की है, जो ग्राहकों को कई ऋणों को एक ही मासिक किस्त (EMI) में समेकित करने की सुविधा देती है।
- The product targets salaried individuals, self-employed professionals, and self-employed non-professionals aged 30–55, and covers loans like home, car, education, personal, and consumer durable loans.
- यह योजना 30–55 वर्ष की आयु के वेतनभोगी, स्वरोजगार पेशेवर और गैर-पेशेवर स्वरोजगारियों को लक्षित करती है, और इसमें गृह, वाहन, शिक्षा, व्यक्तिगत और उपभोक्ता टिकाऊ ऋण शामिल हैं।
- Key benefits include lower interest rates, single unified EMI, minimal documentation, zero processing fee, and simplified debt management as the bank acts as a debt counsellor.
- मुख्य लाभों में कम ब्याज दर, एकीकृत EMI, न्यूनतम दस्तावेज़ीकरण, शून्य प्रोसेसिंग शुल्क और बैंक द्वारा ऋण परामर्शक के रूप में आसान ऋण प्रबंधन शामिल हैं।

Ques: Which bank was awarded the Best Profit-Making Bank in Belagavi District in 2025?

2025 में बेलगावी जिले में सर्वश्रेष्ठ लाभकारी बैंक का पुरस्कार किस बैंक को दिया गया?

- A) Rani Channamma Mahila Sahakari Bank / रानी चन्नम्मा महिला सहकारी बैंक
B) Karnataka Vikas Grameena Bank / कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
C) Belagavi Urban Co-op Bank / बेलगावी अर्बन कोऑप-
D) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
E) Canara Bank / केनरा बैंक

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- Rani Channamma Mahila Sahakari Bank (RCMS Bank), headquartered in Belgaum, Karnataka, was awarded the Best Profit-Making Bank in Belagavi District for 2025.
 - बेलगावी, कर्नाटक में मुख्यालय वाले रानी चन्नम्मा महिला सहकारी बैंक)RCMS बैंक (को 2025 के लिए बेलगावी जिले में सर्वश्रेष्ठ लाभकारी बैंक का पुरस्कार दिया गया।
 - The award was presented during the 72nd All India Cooperative Week held at Haveri, Karnataka.
 - यह पुरस्कार कर्नाटक के हावरी में आयोजित 72वीं अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के दौरान दिया गया।
 - The event was organized by the Karnataka State Urban Cooperative Banks Federation and chaired by Preeti Kore Daddwad.
 - यह कार्यक्रम कर्नाटक स्टेट अर्बन को किया आयोजित द्वारा फेडरेशन बैंक ऑपरेटिव-की। ने डाडवाड कोरे प्रीति अध्यक्षता इसकी और गया
-

Ques: Which Indian company recently received the Certificate of Authorisation from RBI to operate as a Payment Aggregator?

हाल ही में किस भारतीय कंपनी को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए RBI से प्राधिकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ?

- A) PayU India / पेयू इंडिया
- B) PhonePe / फोनपे
- C) Google Pay India / गूगल पे इंडिया
- D) Razorpay / रेज़रपे
- E) Paytm Payments Services Limited / पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज़ लिमिटेड

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- Paytm Payments Services Limited (PPSL), a subsidiary of One97

Communications, received the Certificate of Authorisation (COA) from the Reserve Bank of India (RBI) to operate as a Payment Aggregator under the Payment and Settlement Systems Act (PSSA), 2007.

- पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज़ लिमिटेड (PPSL), One97 Communications की सहायक कंपनी, ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (PSSA), 2007 के तहत भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से प्राधिकरण प्रमाणपत्र (COA) प्राप्त किया।
- The RBI also lifted restrictions that had been imposed on PPSL on 25th November 2022, allowing the company to onboard new merchants.
- RBI ने 25 नवंबर 2022 को PPSL पर लगाए गए प्रतिबंध भी हटा दिए, जिससे कंपनी अब नए व्यापारियों को जोड़ सकेंगी।

Ques: What is mandatory for banks under RBI's final norms for digital banking channels?

RBI के डिजिटल बैंकिंग चैनलों के अंतिम दिशा लिए के बैंकों अनुसार के निर्देशों- क्या अनिवार्य है?

- A) Forcing customers to opt for digital channels / ग्राहकों को डिजिटल चैनल अपनाने के लिए बाध्य करना
- B) Displaying third-party products without approval / बिना अनुमति के थर्ड पार्टी-दिखाना उत्पाद
- C) Obtaining explicit consent from customers for digital banking services / डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए ग्राहकों से स्पष्ट सहमति लेना
- D) Making mobile apps compulsory for banking / मोबाइल ऐप को अनिवार्य बनाना
- E) Removing transaction alerts / लेनदेन अलर्ट हटाना

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- RBI has mandated that banks must obtain explicit consent from customers before providing any digital banking service.
- RBI ने अनिवार्य किया है कि बैंक किसी भी डिजिटल बैंकिंग सेवा को शुरू करने से पहले ग्राहक से स्पष्ट सहमति लें।
- Banks cannot force customers to adopt digital channels to avail basic

facilities like debit cards.

- बैंक ग्राहकों को डेबिट कार्ड जैसी सुविधाएँ पाने के लिए डिजिटल चैनल अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।
- Banks can record customers' mobile numbers for transaction alerts as per KYC norms.
- बैंक KYC नियमों के अनुसार लेनदेन अलर्ट के लिए ग्राहकों का मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं।
- Banks must ensure mobile banking works across all mobile networks (network-independent).
- बैंक सुनिश्चित करें कि मोबाइल बैंकिंग सभी मोबाइल नेटवर्क पर काम करे -नेटवर्क)।(सेवा स्वतंत्र
- Risk mitigation rules such as transaction limits, velocity checks, and fraud monitoring must be implemented.
- जोखिम कम करने हेतु लेनदेन सीमा, वेग सीमा और फ्रॉड मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाएँ लागू करनी होंगी।
- Stricter norms by RBI, NPCI, VISA, Mastercard, etc., will override if applicable.
- यदि RBI, NPCI, VISA, Mastercard आदि के कड़े नियम लागू होते हैं, तो वही मान्य होंगे।
- Banks must deploy risk-based monitoring, customer behaviour analysis, and unusual transaction tracking.
- बैंकों को जोखिमनिगरानी आधारित-, ग्राहक व्यवहार विश्लेषण और असामान्य लेनदेन की निगरानी लागू करनी होगी।
- Third-party products/services (subsidiaries, joint ventures, associates) cannot be shown by banks unless RBI permits.
- बैंक थर्डसेव/उत्पाद पार्टि-ाँ सब्सिडियरी), जॉइंट वेंचर आदि हैं सकते दिखा तभी (जबRBI अनुमति दे।
- Banks must clearly communicate that SMS/email alerts will be sent to the customer's registered mobile/email.
- बैंकों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि अलर्ट ग्राहक के पंजीकृत मोबाइलईमेल/ पर ही भेजे जाएँगे।
- These guidelines aim to strengthen customer protection, ensure network-independent mobile banking, and introduce stricter risk control measures.
- इन दिशाकरना मजबूत को संरक्षण ग्राहक श्यउद्दे का निर्देशों-, नेटवर्क मोबाइल स्वतंत्र- बैंकिंग सुनिश्चित करना और कड़े जोखिम नियंत्रण उपाय लागू करना है।

**Ques: What digital solution did Punjab National Bank (PNB) recently launch?
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने हाल ही में कौन सा डिजिटल समाधान लॉन्च किया?**

- A) Digital loan application portal / डिजिटल लोन आवेदन पोर्टल
- B) PM Street Vendor's AtmaNirbhar NIDHI (PM SVANidhi) scheme solution / पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना का समाधान
- C) Online savings account opening platform / ऑनलाइन बचत खाता खोलने का प्लेटफॉर्म
- D) Mobile payment wallet / मोबाइल पेमेंट वॉलेट
- E) Digital insurance service / डिजिटल बीमा सेवा

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Punjab National Bank (PNB) launched a digital solution specifically for the PM Street Vendor's AtmaNirbhar NIDHI (PM SVANidhi) scheme, helping street vendors access benefits digitally.
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना के लिए एक डिजिटल समाधान लॉन्च किया, जिससे स्ट्रीट वेंडर डिजिटल रूप से लाभ प्राप्त कर सकें।
- Alongside this, PNB introduced end-to-end digitisation of its staff accountability portal and rolled out a conduct risk framework for employees.
- इसके साथ ही, PNB ने अपने स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पोर्टल का पूर्ण डिजिटलीकरण किया और कर्मचारियों के लिए कंडक्ट रिस्क फ्रेमवर्क लागू किया।
- The occasion also marked the release of the 5th Edition of 'PNB's Vigilance Manual 2025' and the September 2025 issue of 'PNB Vigil' magazine, while recognizing ethical employees as "Vigilance Warriors."
- इस अवसर पर 'PNB's Vigilance Manual 2025' का पांचवां संस्करण और उनके त्रैमासिक पत्रिका 'PNB Vigil' का सितंबर 2025 अंक जारी किया गया, साथ ही नैतिकता और समर्पण के लिए कर्मचारियों को "Vigilance Warriors" के रूप में सम्मानित किया गया।

PM SVANidhi Scheme :

- Started : 1st June 2020
- Funded by : Ministry of Housing and Urban Affairs
- For providing affordable working capital loans to street vendors to

resume their livelihoods that have been adversely affected due to Covid-19

- Target : 42 lakh street vendors are to be provided benefits under PM SVANidhi Scheme by December, 2024.

Ques: India's Current Account Deficit (CAD) in Q2FY26 stood at what percentage of GDP?

Q2FY26 में भारत का चालू खाता घाटा (CAD) GDP के कितने प्रतिशत पर रहा?

- A) 0.2%
- B) 0.8%
- C) 1.3%
- D) 1.8%
- E) 2.2%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- India's CAD widened sequentially to 1.3% of GDP in Q2FY26, up from 0.2% in Q1FY26.
- Q2FY26 में भारत का CAD अनुक्रमिक रूप से बढ़कर GDP का 1.3% हो गया, जो Q1FY26 में 0.2% था।
- However, it remained lower than the 2.2% recorded in the same quarter last year (Q2FY25).
- हालांकि, यह पिछले वर्ष की समान तिमाही (Q2FY25) में दर्ज 2.2% से कम रहा।
- The main reasons included weaker capital inflows, decline in NRI deposits & ECB inflows, and rising primary income outflows.
- प्रमुख कारणों में कमजोर पूंजी प्रवाह, NRI डिपॉजिट व ECB प्रवाह में कमी, और प्राथमिक आय में अधिक भुगतान शामिल थे।
- Merchandise trade deficit reduced to \$87.4 billion from \$88.5 billion year-on-year.
- माल व्यापार घाटा वर्ष घटकर वर्ष-दर-वर्ष-\$87.4 बिलियन हो गया, जो पहले \$88.5 बिलियन था।
- Net services receipts rose sharply to \$50.9 billion from \$44.5 billion.
- नेट सेवाओं की प्राप्ति बढ़कर \$50.9 बिलियन हो गई, जो पहले \$44.5 बिलियन थी।

Ques: What recent relaxation did SEBI introduce for Investment Advisers (IAs) and Research Analysts (RAs)?

निवेश सलाहकारों (IAs) और रिसर्च एनालिस्ट्स (RAs) के लिए SEBI ने हाल ही में कौन सा छूटकिया जारी रिलैक्सेशन/?

- A) Only finance graduates can register / केवल वित्तीय स्नातक पंजीकरण कर सकते हैं
B) Educational norms relaxed to include graduates from any discipline / किसी भी विषय के स्नातक पंजीकरण के योग्य हुए
C) Certification from foreign universities mandatory / विदेशी विश्वविद्यालय से प्रमाणपत्र अनिवार्य
D) IAs cannot continue client onboarding during corporatisation / कॉर्पोरेटाइजेशन के दौरान क्लाइंट ऑनबोर्डिंग नहीं कर सकते
E) Registration limited to CFA charter holders only / केवल CFA धारक पंजीकरण के लिए योग्य

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- SEBI has relaxed the educational eligibility criteria for Investment Advisers (IAs) and Research Analysts (RAs), allowing graduates from any discipline (India or abroad) or Chartered Financial Analyst (CFA) charter holders to register.
- SEBI ने निवेश सलाहकारों और रिसर्च एनालिस्ट्स के लिए शैक्षणिक योग्यता नियमों में छूट दी है, जिससे किसी भी विषय के स्नातक या (विदेश या भारत) CFA धारक पंजीकरण कर सकते हैं।
- Certification from National Institute of Securities Markets (NISM) or any NISM-accredited institution is still required.
- NISM या NISM द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से प्रमाणन अब भी अनिवार्य है।
- Corporatisation rules now allow IAs exceeding 300 clients or ₹3 crore fees to transition into corporate entities within six months, while continuing client onboarding and fee collection.
- अब कॉर्पोरेटाइजेशन नियमों के तहत, 300 से अधिक क्लाइंट या ₹3 करोड़ शुल्क वाले IAs छह महीने में कॉर्पोरेट इकाई में परिवर्तित हो सकते हैं और इस दौरान क्लाइंट ऑनबोर्डिंग और शुल्क संग्रह जारी रख सकते हैं।

Ques: Ramakrishnan Chander has been appointed as MD of which organisation?

Ramakrishnan Chander को किस संस्था के Managing Director (MD) के रूप में नियुक्त किया गया है?

- A) SBI Life / एसबीआई लाइफ
- B) LIC / एलआईसी
- C) IRDAI / IRDAI
- D) Max Life / मैक्स लाइफ
- E) HDFC Life / HDFC लाइफ

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- LIC announced that Ramakrishnan Chander has taken charge as its Managing Director (MD) from December 1.
- LIC ने घोषणा की कि रामकृष्णन चंदर ने 1 दिसंबर से Managing Director का पदभार संभाला है।
- He will serve in this position until his superannuation on 30 September 2027.
- वह इस पद पर 30 सितंबर 2027 तक कार्य करेंगे।
- His pay scale as LIC MD will range from ₹2,05,400 to ₹2,24,400.
- LIC MD के रूप में उनका वेतनमान ₹2,05,400 से ₹2,24,400 के बीच होगा।

Ques: The Asian Development Bank (ADB) approved a loan of \$846 million to India for which major initiative?

एशियाई विकास बैंक) ADB) द्वारा भारत को स्वीकृत 846 मिलियन डॉलर का ऋण किस प्रमुख पहल के लिए है?

- A) Green Energy Corridor Development / ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकास
- B) Rural Road Connectivity Improvement / ग्रामीण सड़क संपर्क सुधार
- C) Upgradation of Industrial Training Institutes (ITIs) / औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) का उन्नयन
- D) Smart City Mission Expansion / स्मार्ट सिटी मिशन विस्तार
- E) National Digital Literacy Campaign / राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियान

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Asian Development Bank (ADB) has approved a loan of \$846 million to India.
- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत को 846 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है।
- The funding supports the Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs Program.
- यह धनराशि उन्नत ITIs के माध्यम से प्रधानमंत्री स्किलिंग और रोजगार परिवर्तन कार्यक्रम का समर्थन करती है।
- The programme aims to upgrade 650 Industrial Training Institutes (ITIs) across 12 states.
- इस कार्यक्रम का लक्ष्य 12 राज्यों में 650 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) को उन्नत करना है।
- The initiative will enhance skill development, employability, and modern vocational training across the country.
- यह पहल देशभर में कौशल विकास, रोजगार क्षमता और आधुनिक व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देगी।

About Asian Development Bank :

- Established : 19 December 1966
- HQ : Manila, Philippines
- Members : 69
- Chief Economist : Albert Park
- President : Masato Kanda

Ques: Usha Janakiraman has been appointed to which position in RBI?

Usha Janakiraman को RBI में किस पद पर नियुक्त किया गया है?

- A) Deputy Governor / डिप्टी गवर्नर
- B) Executive Director / कार्यकारी निदेशक
- C) Director of Currency / करेंसी निदेशक

- D) Chief Economist / मुख्य अर्थशास्त्री
E) Chief General Manager / मुख्य महाप्रबंधक

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- RBI has appointed Usha Janakiraman as Executive Director (ED) effective from 1 December.
 - RBI ने उषा जनकिरामन को 1 दिसंबर से Executive Director नियुक्त किया है।
 - Prior to this appointment, she was serving as Chief General Manager in the Department of Regulation.
 - नियुक्ति से पहले वह विनियमन विभाग में Chief General Manager के रूप में कार्यरत थीं।
 - As ED, she will oversee the Department of Supervision, including risk, analytics, and vulnerability assessment.
 - ED के रूप में वह Department of Supervision की देखरेख करेगी, जिसमें risk, analytics और vulnerability assessment शामिल हैं।
 - She has over three decades of RBI experience, including regulation, external investment, banking supervision, public debt management, and currency management.
 - RBI में उनके पास तीन दशकों से अधिक का अनुभव है, जिसमें regulation, external investment, banking supervision, public debt management और currency management शामिल हैं।
-

Ques: What is featured on the new NPR 100 note released by Nepal Rastra Bank?

नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा जारी नए NPR 100 नोट में क्या दिखाया गया है?

- A) Mount Everest and national animals / माउंट एवरेस्ट और राष्ट्रीय जानवर
B) Nepal's revised political map including Kalapani, Lipulekh, and Limpiyadhura / कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा सहित नेपाल का संशोधित राजनीतिक मानचित्र
C) Famous Nepalese temples / प्रसिद्ध नेपाली मंदिर
D) Cultural festivals of Nepal / नेपाल के सांस्कृतिक त्योहार
E) Traditional Nepalese art forms / पारंपरिक नेपाली कला रूप

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Nepal Rastra Bank (NRB) released a new NPR 100 note featuring Nepal's revised political map, which includes disputed territories such as Kalapani, Lipulekh, and Limpiyadhura.
 - नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ने नया NPR 100 नोट जारी किया है, जिसमें नेपाल का संशोधित राजनीतिक मानचित्र दिखाया गया है, जिसमें विवादित क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा शामिल हैं।
 - The printing contract was awarded to China Banknote Printing and Minting Corporation. The three territories are currently under India's control but claimed by Nepal.
 - मुद्रण का ठेका चीन बैंकनोट प्रिंटिंग एंड मिंगिंग कॉर्पोरेशन को दिया गया। ये तीनों क्षेत्र वर्तमान में भारत के नियंत्रण में हैं, लेकिन नेपाल द्वारा दावा किया गया है।
 - The revised map was adopted through a constitutional amendment on May 20, 2020, and the NPR 100 design was approved by the Nepalese Cabinet in May 2024.
 - संशोधित मानचित्र 20 मई 2020 को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अपनाया गया और NPR 100 का डिज़ाइन मई 2024 में नेपाली कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया।
-

Ques: What is the main purpose of the 3-in-1 account launched by Utkarsh Small Finance Bank in partnership with Axis Securities?

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने Axis Securities के साथ साझेदारी में लॉन्च किए गए 3-इन-1 खाते का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) To provide only a savings account / केवल बचत खाता प्रदान करना
- B) To offer a unified platform for banking and investing by integrating Savings, Demat, and Trading accounts / बचत, डिमैट और ट्रेडिंग खातों को एकीकृत करके बैंकिंग और निवेश के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करना
- C) To provide only a Demat account for investments / केवल निवेश के लिए डिमैट खाता प्रदान करना
- D) To provide only trading services / केवल ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करना
- E) To offer fixed deposit schemes with high interest / उच्च ब्याज वाले फिक्स्ड

डिपॉजिट योजना प्रदान करना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Utkarsh Small Finance Bank, in partnership with Axis Securities, launched a 3-in-1 account that integrates a Savings Account (Utkarsh SFBL), Demat Account (Axis Securities), and Trading Account (Axis Securities) to provide a single platform for both banking and investing.
- उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने Axis Securities के साथ साझेदारी में 3-इन-1 खाता लॉन्च किया है, जिसमें बचत खाता (Utkarsh SFBL), डिमैट खाता (Axis Securities) और ट्रेडिंग खाता (Axis Securities) एकीकृत हैं, ताकि बैंकिंग और निवेश के लिए एक ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो।
- Key features include seamless fund transfer for investing, one-stop access to account services and wealth management, and availability through branch banking, internet banking, mobile banking, and assisted digital channels.
- प्रमुख विशेषताओं में निवेश के लिए सहज फंड ट्रांसफर, खाते की सेवाओं और वेल्थ मैनेजमेंट का वनएक्सेस स्टॉप-, और शाखा बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और असिस्टेड डिजिटल चैनलों के माध्यम से उपलब्धता शामिल है।

About Utkarsh Small Finance Bank :

- Established : 2016
 - HQ : Varanasi, Uttar Pradesh
 - CEO : Govind Singh
 - Tagline : Aapki Umeed Ka Khata
-

Ques: What is the purpose of YES BANK's "Score Kya Hua" initiative?

YES BANK के "Score Kya Hua" पहल का उद्देश्य क्या है?

- A) To provide home loans at discounted rates / होम लोन छूट पर प्रदान करना
- B) To promote digital banking adoption / डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना
- C) To improve credit literacy and help individuals manage their credit score / क्रेडिट साक्षरता बढ़ाना और व्यक्तियों को उनके क्रेडिट स्कोर का प्रबंधन करने में मदद करना

D) To offer insurance products to young entrepreneurs / युवा उद्यमियों को बीमा उत्पाद प्रदान करना

E) To provide investment advisory services / निवेश परामर्श सेवाएँ प्रदान करना

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- YES BANK's "Score Kya Hua" is a nationwide CSR initiative aimed at improving credit literacy among Indians.
 - YES BANK की "Score Kya Hua" पहल एक राष्ट्रीय CSR पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीयों में क्रेडिट साक्षरता बढ़ाना है।
 - The initiative helps individuals understand credit scores, manage them effectively, and make informed credit decisions.
 - यह पहल व्यक्तियों को क्रेडिट स्कोर को समझने, प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और सूचित क्रेडिट निर्णय लेने में मदद करती है।
 - It targets a wide audience including young entrepreneurs, new credit users, and homebuyers, providing free credit score checks and easy learning modules on credit behaviour via a dedicated microsite.
 - यह युवा उद्यमियों, नए क्रेडिट उपयोगकर्ताओं और होमबायर्स सहित व्यापक दर्शकों को लक्षित करती है, और एक समर्पित माइक्रोसाइट के माध्यम से मुफ्त क्रेडिट स्कोर चेक और क्रेडिट व्यवहार पर सरल लर्निंग मॉड्यूल प्रदान करती है।
 - Knowledge partner for the initiative is CRIF High Mark, a credit bureau.
 - इस पहल के लिए ज्ञान साझेदार CRIF High Mark, एक क्रेडिट ब्यूरो है।
-

Ques: By November 2025, what was LIC's total holding in Cipla after increasing its stake?

नवंबर 2025 तक LIC की Cipla में कुल हिस्सेदारी कितनी हो गई?

- A) 5.02%
- B) 6.50%
- C) 7.05%
- D) 8.10%
- E) 9.00%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- LIC (Life Insurance Corporation of India) acquired over 1.64 crore shares of Cipla within a little over four months starting July 2025.
- LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम जुलाई ने (2025 से अगले चार महीनों में Cipla के 1.64 करोड़ से अधिक शेयर खरीदे।
- LIC's stake increased from 5.025% (mid-July) to 7.055% by November-end 2025.
- LIC की हिस्सेदारी जुलाई मध्य में 5.025% से बढ़कर नवंबर 2025 के अंत तक 7.055% हो गई।
- LIC bought the additional ~2% stake through open-market purchases.
- LIC ने यह अतिरिक्त लगभग 2% हिस्सेदारी खुले बाज़ार के खरीद में (मार्केट ओपन) माध्यम से हासिल की।
- Cipla is one of India's leading pharmaceutical companies.
- Cipla भारत की प्रमुख दवा है। एक से में कंपनियों (फार्मा)
- Cipla shares closed slightly (<1%) lower at ₹1,523.80 on BSE.
- Cipla के शेयर BSE पर ₹1,523.80 पर 1% से कम गिरावट के साथ बंद हुए।

Ques: What does the Ministry of Finance's Monthly Economic Review (October) highlight about India's economy?

वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा भारत की अर्थव्यवस्था के बारे (अक्टूबर)में क्या रुझान दर्शाती है?

- A) Domestic economy showing stability and resilience / घरेलू अर्थव्यवस्था स्थिर और लचीली दिख रही है
- B) Sharp decline in automobile and tractor sales / ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर की बिक्री में तेज गिरावट
- C) Record low services exports / सेवाओं के निर्यात में रिकॉर्ड गिरावट
- D) Manufacturing and services PMI indicate contraction / विनिर्माण और सेवा पीएमआई में संकुचन दर्शाता है
- E) Inflation rising sharply / मुद्रास्फीति में तेज़ वृद्धि

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- The Ministry of Finance noted that India's domestic economy remains stable and resilient, supported by lower inflation, strong consumer demand, and early policy impacts.
- वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था स्थिर और लचीली बनी हुई है, जिसे कम मुद्रास्फीति, मजबूत उपभोक्ता मांग और प्रारंभिक नीतिगत प्रभावों से समर्थन मिला है।
- Retail inflation fell to 0.25 percent, aided by GST rate cuts and declining food prices.
- खुदरा मुद्रास्फीति 0.25 प्रतिशत पर गिर गई, जो GST दरों में कटौती और खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण है।
- Consumption was boosted during the festive season: petrol sales were the highest in 5 months, automobile sales increased 40.5% YoY, and tractor sales were the highest in 11 years due to good monsoon and GST reforms.
- त्योहारों के मौसम में उपभोग बढ़ा पेट्रोल की बिक्री :5 महीनों में सबसे अधिक रही, ऑटोमोबाइल की बिक्री सालाना आधार पर 40.5% बढ़ी, और ट्रैक्टर की बिक्री 11 वर्षों में सबसे अधिक रही, जो अच्छी मानसून और GST सुधारों से समर्थित है।
- External sector performance was strong: services exports reached a record USD 38.5 billion, covering nearly 50% of the merchandise trade deficit.
- बाहरी क्षेत्र का प्रदर्शन मजबूत रहा सेवाओं के निर्यात ने रिकॉर्ड :USD 38.5 बिलियन को छुआ, जो माल व्यापार घाटे का लगभग 50% कवर करता है।
- Manufacturing PMI stood at 59.2 and Services PMI at 58.9, indicating strong expansion and robust growth.
- विनिर्माण पीएमआई 59.2 और सेवा पीएमआई 58.9 पर रही, जो मजबूत विस्तार और सतत विकास को दर्शाता है।

Ques: RBI launched NSFI 2025-30 at the meeting of which body?

RBI ने NSFI 2025-30 किस समिति की बैठक में लॉन्च किया?

- A) Monetary Policy Committee / मौद्रिक नीति समिति
- B) FSDC Sub-Committee / FSDC सबकमेटी-
- C) Financial Inclusion Advisory Board / वित्तीय समावेशन सलाहकार बोर्ड
- D) SEBI Board / SEBI बोर्ड

E) DFS Review Committee / DFS समीक्षा समिति

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- RBI unveiled the National Strategy for Financial Inclusion (NSFI) 2025-30 during the 32nd meeting of the FSDC Sub-Committee, chaired by the RBI Governor.
 - RBI ने NSFI 2025-30 को FSDC सब कमेटी की-32वीं बैठक में लॉन्च किया, जिसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर करते हैं।
 - The strategy aims to boost financial access across India and aligns with the UN's 2030 Sustainable Development Agenda.
 - इस रणनीति का उद्देश्य पूरे भारत में वित्तीय पहुंच बढ़ाना है और यह UN के 2030 सतत विकास एजेंडा के अनुरूप है।
 - NSFI is structured around five pillars called 'Panch-Jyoti' and will be implemented through 47 action points across regulators.
 - NSFI पाँच प्रमुख उद्देश्य 'Panch-Jyoti' पर आधारित है और इसे लागू करने के लिए विभिन्न नियामकों के बीच 47 ऐक्शन पॉइंट तय किए गए हैं।
-

Ques: Punjab National Bank recently appointed which sportsperson as its first-ever female brand ambassador?

हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने किस खिलाड़ी को अपनी पहली महिला ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया?

- A) Smriti Mandhana / स्मृति मंधाना
- B) PV Sindhu / पीवी सिंधु
- C) Harmanpreet Kaur / हरमनप्रीत कौर
- D) Sakshi Malik / साक्षी मलिक
- E) Mithali Raj / मिताली राज

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Punjab National Bank (PNB) appointed Harmanpreet Kaur as its first-ever female brand ambassador.
- पंजाब नेशनल बैंक ने हरमनप्रीत कौर को अपनी पहली महिला ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया।
- Harmanpreet Kaur is the captain of the Indian Women's Cricket Team and a World Cup champion.
- हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और विश्व कप विजेता हैं।
- This appointment marks a significant milestone in PNB's ongoing brand transformation journey.
- यह नियुक्ति PNB की चल रही ब्रांड ट्रांसफॉर्मेशन यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- The association aims to enhance customer trust, brand visibility, and youth engagement.
- यह साझेदारी ग्राहक विश्वास, ब्रांड दृश्यता और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।
- PNB is India's second-largest public sector bank by business volume.
- PNB व्यवसाय मात्रा के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है।

Ques: Tata Realty & Infrastructure recently partnered with which bank for a green loan facility?

टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने हाल ही में किस बैंक के साथ ग्रीन लोन सुविधा के लिए साझेदारी की?

- A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C) DBS Bank India / डीबीएस बैंक इंडिया
- D) SBI / एसबीआई
- E) Axis Bank / एक्सिस बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Tata Realty & Infrastructure partnered with DBS Bank India to secure a Rs 1,280 crore green loan facility.
- टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने डीबीएस बैंक इंडिया के साथ साझेदारी करके ₹1,280 करोड़ की ग्रीन लोन सुविधा हासिल की।
- The loan was taken by a Special Purpose Vehicle (SPV) for the Intellion Park project in Gurugram.
- यह लोन गुरुग्राम में Intellion Park प्रोजेक्ट के लिए Special Purpose Vehicle (SPV) द्वारा लिया गया।
- Intellion Park is a Grade-A commercial campus spanning 2.1 million sq. ft. with four towers.
- Intellion Park एक ग्रेड-A वाणिज्यिक परिसर है, जो 2.1 मिलियन वर्ग फुट में फैला है और इसमें चार टावर हैं।
- The project aims to support sustainable real estate development.
- इस परियोजना का उद्देश्य सतत रियल एस्टेट विकास को बढ़ावा देना है।

About DBS Bank India :

- Established : 1994
- HQ : Mumbai
- CEO : Rajat Verma

Ques: Which bank appointed Ranbir Kapoor and Rashmika Mandanna as brand ambassadors?

किस बैंक ने रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना को ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है?

- A) Equitas SFB / इक्विटास SFB
- B) Ujjivan SFB / उज्जीवन SFB
- C) AU Small Finance Bank / AU स्मॉल फाइनेंस बैंक
- D) ESAF SFB / ईएसएएफ SFB
- E) Jana SFB / जाना SFB

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- AU Small Finance Bank appointed Ranbir Kapoor and Rashmika Mandanna as brand ambassadors soon after receiving RBI's in-principle approval to transition into a universal bank.
- यूनिवर्सल बैंक बनने की प्रारंभिक मंजूरी मिलने के तुरंत बाद AU Small Finance Bank ने रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना को ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया।
- The ambassadors will promote the bank's new campaigns and digital banking initiatives to enhance brand visibility and customer outreach.
- ये ब्रांड एंबेसडर बैंक के नए कैंपेन और डिजिटल बैंकिंग पहलों को प्रमोट करेंगे, ताकि ब्रांड की उपस्थिति और ग्राहक पहुंच बढ़ सके।
- AU SFB is India's largest Small Finance Bank in terms of assets and branch network.
- AU SFB परिसंपत्तियों और शाखा नेटवर्क के मामले में भारत का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है।

Ques: ADB recently approved a \$650 million loan for India. What is the main purpose of this loan?

ADB ने हाल ही में भारत के लिए \$650 मिलियन का ऋण मंजूर किया। इस ऋण का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) Highways Development / हाईवे विकास
- B) Rooftop Solar Adoption / रूफटॉप सोलर अपनाने को बढ़ावा देना
- C) Agriculture Financing / कृषि वित्तपोषण
- D) Smart Cities Mission / स्मार्ट सिटी मिशन
- E) Defence Modernisation / रक्षा आधुनिकीकरण

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Asian Development Bank (ADB) approved a \$650 million (\approx ₹5,780 crore) policy-based loan to support India's rooftop solar programme.
- एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने भारत के रूफटॉप सोलर कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए \$650 मिलियन (\approx ₹5,780 करोड़) आधारित ऋण मंजूर किया।-का नीति (
- The loan aims to accelerate rooftop solar adoption across residential households, providing clean and affordable energy.

- इस ऋण का उद्देश्य आवासीय घरों में रूफटॉप सोलर अपनाने में तेजी लाना और स्वच्छ, सस्ती ऊर्जा प्रदान करना है।
- Target beneficiaries: 1 crore (10 million) households by 2027.
- लक्षित लाभार्थी :2027 तक 1 करोड़ (1,00,00,000) घर।
- The programme supports India's clean energy transition and reduces dependence on fossil fuels.
- यह कार्यक्रम भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करता है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करता है।
- ADB continues to be a key partner in India's renewable energy expansion.
- ADB भारत में नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार में एक प्रमुख भागीदार बना हुआ है।

Ques: What is the current Foreign Direct Investment (FDI) limit in Public Sector Banks (PSBs)?

PSBs में वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) सीमा क्या है?

- A) 49%
- B) 74%
- C) 20%
- D) 26%
- E) 35%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The government clarified that it is not considering any proposal to raise the FDI limit in PSBs from 20% to 49%.
- सरकार ने स्पष्ट किया कि वह PSBs में FDI सीमा 20% से बढ़ाकर 49% करने पर विचार नहीं कर रही है।
- Current FDI caps: 20% for PSBs and 74% for private banks (up to 49% under automatic route for private banks).
- वर्तमान FDI सीमा :PSBs के लिए 20% और निजी बैंकों के लिए 74% (जिसमें 49% स्वचालित मार्ग के तहत अनुमत है।)
- Any acquisition of 5% or more in a bank requires prior RBI approval.
- किसी बैंक में 5% या अधिक हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI की पूर्व मंजूरी आवश्यक है।
- Banks must maintain at least 25% minimum public shareholding.

- बैंकों को न्यूनतम 25% सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग बनाए रखना आवश्यक है।
- NITI Aayog will make recommendations on whether PSBs under strategic sectors should remain under govt control or be considered for privatisation, merger, or subsidiarisation.
- NITI आयोग यह अनुशंसा करेगा कि रणनीतिक क्षेत्रों में आने वाले PSBs को सरकारी नियंत्रण में रखा जाए या निजीकरण, विलय या सहायक कंपनी बनाने पर विचार किया जाए।

Ques: What is the purpose of Axis Bank's 'Flashback' programme?

Axis Bank के 'Flashback' कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?

- A) To provide financial planning workshops for senior citizens / वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय योजना कार्यशालाएँ आयोजित करना
- B) To offer nostalgic film screenings and strengthen cultural connection with elderly customers / वरिष्ठ ग्राहकों के साथ भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने के लिए पुराने फिल्मों की स्क्रीनिंग प्रदान करना
- C) To promote digital banking adoption among senior citizens / वरिष्ठ नागरिकों में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना
- D) To provide health check-up camps for elderly customers / वरिष्ठ ग्राहकों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करना
- E) To offer discounted loans to senior citizens / वरिष्ठ नागरिकों को छूट वाले लोन प्रदान करना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Axis Bank's 'Flashback' is a special engagement programme for senior citizens, offering exclusive screenings of classic films from the 1960s and 1970s.
- Axis Bank का 'Flashback' वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष कार्यक्रम है, जिसमें 1960 और 1970 के दशक की क्लासिक फिल्मों की विशेष स्क्रीनिंग शामिल है।
- The objective is to strengthen emotional and cultural connections with elderly customers, providing nostalgic entertainment and opportunities for social interaction.

- इसका उद्देश्य वरिष्ठ ग्राहकों के साथ भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत करना, पुरानी यादों से जुड़ी मनोरंजन और सामाजिक बातचीत के अवसर प्रदान करना है।
- The programme also includes regional-language films in Kannada, Telugu, Malayalam, and Tamil to enhance relevance in respective states.
- इस कार्यक्रम में कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में भी शामिल हैं, ताकि संबंधित राज्यों में इसकी प्रासंगिकता बढ़ सके।

Ques: How many UPI transactions were recorded in November 2025?
नवंबर 2025 में कितने UPI लेनदेन दर्ज किए गए?

- A) 18.5 billion
- B) 19.7 billion
- C) 20.47 billion
- D) 21.8 billion
- E) 22.5 billion

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- NPCI reported that India's UPI platform processed 20.47 billion transactions in November 2025, with a total value of ₹26.32 lakh crore.
- एनपीसीआई के अनुसार भारत के UPI प्लेटफॉर्म ने नवंबर 2025 में 20.47 बिलियन लेनदेन किए, जिनका कुल मूल्य ₹26.32 लाख करोड़ रहा।
- This represents a 32% YoY rise in transaction volume and 22% rise in transaction value.
- लेनदेन मात्रा में 32% वार्षिक वृद्धि और मूल्य में 22% वृद्धि दर्ज की गई।
- Daily average transactions were 682 million, amounting to ₹87,721 crore.
- दैनिक औसत लेनदेन 682 मिलियन थे, जिनका कुल मूल्य ₹87,721 करोड़ रहा।
- Compared to October 2025 (20.70 billion), November saw a slight dip due to post-festival stabilization.
- अक्टूबर 2025 (20.70 बिलियन) की तुलना में नवंबर में लेनदेन में थोड़ी कमी देखी (गई

Ques: Which two new plans were recently launched by LIC?

LIC ने हाल ही में कौनसी दो नई योजनाएँ लॉन्च की हैं-?

- A) Jeevan Shanti & Jeevan Labh / जीवन शांति और जीवन लाभ
- B) Bima Kavach & Protection Plus / बीमा कवच और प्रोटेक्शन प्लस
- C) Saral Suraksha & Jeevan Umang / सरल सुरक्षा और जीवन उमंग
- D) Dhan Rekha & New Endowment Plan / धन रेखा और नई एंडोमेंट योजना
- E) Jeevan Anand & Jeevan Labh Plus / जीवन आनंद और जीवन लाभ प्लस

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- LIC has officially launched two new plans — Bima Kavach and Protection Plus.
- LIC ने आधिकारिक रूप से दो नई योजनाएँ लॉन्च की हैं — बीमा कवच और प्रोटेक्शन प्लस।
- Bima Kavach is a non-par, non-linked, pure risk life insurance plan providing financial protection to the family in case of unfortunate death.
- बीमा कवच एक non-par, non-linked, pure risk जीवन बीमा योजना है, जो दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में परिवार को आर्थिक सुरक्षा देती है।
- Protection Plus is a non-par, linked, individual savings plan offering both life cover and savings options.
- प्रोटेक्शन प्लस एक non-par, linked, individual savings योजना है, जो जीवन बीमा कवरेज और बचत विकल्प दोनों प्रदान करती है।
- Protection Plus allows fund switching, sum assured increase/decrease, and flexible premium payment options (regular, single, limited).
- प्रोटेक्शन प्लस में investment fund बदलने, sum assured बढ़ाने या घटाने, और regular, single या limited premium विकल्प उपलब्ध हैं।
- Bima Kavach offers two death benefit options — Level Sum Assured and Increasing Sum Assured.
- बीमा कवच में दो death benefit विकल्प हैं — Level Sum Assured और Increasing Sum Assured।
- Partial withdrawal in Protection Plus is allowed after five years, with policy term extendable up to 100 years.
- प्रोटेक्शन प्लस में पाँच साल बाद partial withdrawal संभव है और सुरक्षा अवधि 100 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
- Life-stage benefits (marriage or childbirth) allow increasing life cover in

regular premium level sum assured option.

- Life-stage benefits (विवाह या childbirth) के समय regular premium वाले level sum assured विकल्प में life cover बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध है।

Ques: What did RBI Deputy Governor Poonam Gupta state about inflation forecasting and BoP data?

RBI की उप स्फीति पूर्वानुमान और गवर्नर पूनम गुप्ता ने मुद्रा-BoP डेटा के बारे में क्या बताया?

- A) RBI intentionally overestimates inflation / RBI जानबूझकर मुद्रास्फीति अधिक आंकता है
- B) RBI inflation forecasts have systematic bias / RBI के मुद्रास्फीति पूर्वानुमान में प्रणालीगत पूर्वाग्रह है
- C) RBI forecasts may have errors but no bias; BoP data to be released monthly / पूर्वानुमान में त्रुटियाँ हो सकती हैं लेकिन पूर्वाग्रह नहीं; BoP डेटा अब मासिक जारी होगा
- D) RBI will discontinue Balance of Payments data / RBI BoP डेटा जारी करना बंद कर देगा
- E) RBI uses only historical data for forecasting / पूर्वानुमान के लिए RBI केवल ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करता है

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- RBI Deputy Governor Poonam Gupta stated that while inflation forecasts sometimes go wrong, there is no systematic bias in the RBI's forecasting.
- RBI की उपकभी त्रुटियाँ हो -गवर्नर पूनम गुप्ता ने कहा कि मुद्रास्फीति पूर्वानुमान में कभी-सकती हैं, लेकिन इसमें कोई प्रणालीगत पूर्वाग्रह नहीं है।
- RBI uses multiple tools for inflation forecasting, including econometric models, historical data, surveys, and consultations with ministries and experts.
- मुद्रास्फीति पूर्वानुमान के लिए RBI कई उपकरणों का उपयोग करता है, जिनमें अर्थमितीय मॉडल, ऐतिहासिक डेटा, सर्वेक्षण और मंत्रालयों तथा विशेषज्ञों से परामर्श शामिल हैं।
- To improve data availability, RBI plans to release Balance of Payments (BoP) data monthly instead of quarterly, though monthly data may be less granular.
- डेटा उपलब्धता बढ़ाने के लिए, RBI अब BoP डेटा त्रैमासिक के बजाय मासिक जारी

करेगा, हालांकि मासिक डेटा कम विस्तारपूर्ण हो सकता है।

- The move is part of RBI's effort to enhance transparency and respond to feedback while maintaining accurate and unbiased reporting.
- यह कदम RBI की पारदर्शिता बढ़ाने और सटीक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग बनाए रखने के प्रयास का हिस्सा है।

Ques: What is the purpose of NPCI's newly launched Banking Connect platform?

NPCI द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए Banking Connect प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है?

- A) To facilitate international remittances / अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण की सुविधा देना
- B) To manage stock market investments / शेयर बाजार निवेश प्रबंधित करना
- C) To provide personal loans to customers / ग्राहकों को व्यक्तिगत ऋण प्रदान करना
- D) To issue digital credit cards / डिजिटल क्रेडिट कार्ड जारी करना
- E) To enable RBI to monitor fund transfers in shorter-lag / RBI को फंड ट्रांसफर कम समय में मॉनिटर करने में सक्षम बनाना

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- Banking Connect is a net-banking platform developed by NPCI to allow the RBI to monitor fund transfers with shorter time lags.
- Banking Connect NPCI द्वारा विकसित एक नेटबैंकिंग प्लेटफॉर्म है, जो RBI को कम समय में फंड ट्रांसफर मॉनिटर करने में सक्षम बनाता है।
- Currently, banks report net-banking transactions to RBI with delays ranging from a week to up to a year.
- वर्तमान में, बैंक नेट बैंकिंग लेनदेन की जानकारी-RBI को सप्ताहों से लेकर एक साल तक की देरी से भेजते हैं।
- NBBL aims to increase monthly bill-payment volumes fourfold to 1 billion transactions in four years, up from the current 260 million.
- NBBL का लक्ष्य चार वर्षों में मासिक बिल भुगतान लेनदेन की संख्या चार गुना बढ़ाकर 1 अरब लेनदेन करना है, जो वर्तमान में 2.6 करोड़ है।
- The platform is also designed to minimise fraud by flagging suspicious transactions faster.

- यह प्लेटफॉर्म संदिग्ध लेनदेन को जल्दी पहचानकर धोखाधड़ी कम करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है।

Ques: Which bank falls under Bucket 4 in RBI's 2025 D-SIB list?

RBI की 2025 D-SIB सूची में कौन सा बैंक बकेट 4 में है?

- A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C) State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- RBI has again identified SBI, HDFC Bank, and ICICI Bank as Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs) for 2025.
- RBI ने 2025 के लिए SBI, HDFC Bank और ICICI Bank को एक बार फिर Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs) के रूप में सूचीबद्ध किया है।
- SBI has been placed in Bucket 4 with an additional CET1 requirement of 0.80%, the highest among the three D-SIBs.
- SBI को बकेट 4 में रखा गया है और इसका अतिरिक्त CET1 आवश्यकता 0.80% है, जो तीनों D-SIBs में सबसे अधिक है।
- HDFC Bank is in Bucket 2 with CET1 requirement of 0.40%, while ICICI Bank is in Bucket 1 with CET1 requirement of 0.20%.
- HDFC Bank बकेट 2 में है और इसका CET1 आवश्यकता 0.40% है, जबकि ICICI Bank बकेट 1 में है और इसका CET1 आवश्यकता 0.20% है।
- D-SIB designation is based on size, interconnectedness, substitutability, and complexity.
- D-SIB की पहचान आकार, इंटरकनेक्टेडनेस, विकल्पों की कमी और जटिलता पर आधारित होती है।
- SBI and ICICI Bank were first designated D-SIBs in 2015–16, while HDFC Bank was designated in 2017 onwards.
- SBI और ICICI Bank को 2015–16 में D-SIB नामित किया गया था, जबकि HDFC Bank

को 2017 से नामित किया गया।

Ques: What percentage of total enrolments under Atal Pension Yojana (APY) are women as of October 2025?

अक्टूबर 2025 तक अटल पेंशन योजना (APY) के कुल नामांकनों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है?

- A) 35%
- B) 42%
- C) 48%
- D) 52%
- E) 50%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- As of 31 October 2025, Atal Pension Yojana (APY) has crossed 8.34 crore enrolments.
- 31 अक्टूबर 2025 तक अटल पेंशन योजना (APY) के कुल नामांकन 8.34 करोड़ पार हो गए हैं।
- Women constitute 48% of the total enrolments under APY, highlighting their strong participation in social security schemes.
- APY के कुल नामांकन में महिलाओं की हिस्सेदारी 48% है, जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में उनकी मजबूत भागीदारी को दर्शाता है।
- APY was launched on 9 May 2015 in Kolkata by PM Narendra Modi and is administered by PFRDA under the National Pension System (NPS).
- APY की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी और यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत PFRDA द्वारा संचालित होती है।
- Eligible Indian citizens aged 18–40 years can enroll, and subscribers receive a guaranteed monthly pension of ₹1,000 to ₹5,000 after turning 60.
- 18–40 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक पात्र हैं, और सदस्य 60 वर्ष की आयु पर ₹1,000 से ₹5,000 तक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं।
- If the subscriber dies before 60, the spouse can continue contributions; contributions can be made monthly, quarterly, or half-yearly, with only one APY account allowed per person.

- यदि सदस्य की 60 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाती है, तो जीवनसाथी योगदान जारी रख सकता है; योगदान मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक किया जा सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति केवल एक APY खाता खोल सकता है।

Ques: For what achievement did ICAI earn a Guinness World Record recently?

हाल ही में ICAI को गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड किस उपलब्धि के लिए मिला?

- A) Largest audit conducted in a day / एक दिन में सबसे बड़ी ऑडिट
- B) Largest career advice session in a single day / एक ही दिन में सबसे बड़ी करियर सलाह सत्र
- C) Most students enrolled in accounting courses / लेखा पाठ्यक्रमों में सबसे अधिक छात्रों का नामांकन
- D) Longest continuous online lecture / सबसे लंबा लगातार ऑनलाइन व्याख्यान
- E) Largest donation by an educational institute / किसी शैक्षिक संस्था द्वारा सबसे बड़ी दान राशि

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) set a Guinness World Record by conducting the largest career advice session in a single day.
- इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने एक ही दिन में सबसे बड़ी करियर सलाह सत्र आयोजित करके गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया।
- The Mumbai event had participation from over 7,400 students, teachers, and principals, with 6,166 students officially counted under Guinness World Records criteria.
- मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम में 7,400 से अधिक छात्र, शिक्षक और प्रिंसिपल शामिल हुए, जिसमें 6,166 छात्रों को आधिकारिक रूप से गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड मानदंडों के तहत गिना गया।
- This achievement was part of ICAI's CAFY 4.0 (Career in Accounting and Finance for Youth) initiative and the Super Mega Career Counselling Programme.
- यह उपलब्धि ICAI की CAFY 4.0 (युवा के लिए अकाउंटिंग और फाइनेंस में करियरपहल (

और सुपर मेगा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का हिस्सा थी।

About ICAI :

- Established : 1949
- HQ : New Delhi
- President : CA. Charanjot Singh Nanda

**Ques: What is the purpose of the four-member committee formed by EPFO?
EPFO द्वारा गठित चारसदस्यीय समिति का उद्देश्य क्या है-?**

- A) To reduce EPF contribution rates / EPF योगदान दरों को कम करना
- B) To investigate financial frauds in EPFO / EPFO में वित्तीय धोखाधड़ी की जांच करना
- C) To restructure workforce and enhance subscriber services / कार्यबल का पुनर्गठन और सदस्य सेवा में सुधार करना
- D) To privatize EPFO operations / EPFO संचालन का निजीकरण करना
- E) To launch new pension schemes / नई पेंशन योजनाओं को लॉन्च करना

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- EPFO has formed a four-member committee headed by B P Sharma to review the existing staffing structure and identify inefficiencies.
- EPFO ने बी पी शर्मा की अध्यक्षता में एक चारसदस्यीय समिति बनाई है, जो वर्तमान स्टाफिंग संरचना की समीक्षा करेगी और अक्षमताओं की पहचान करेगी।
- The committee aims to streamline workflows, reduce bureaucratic delays, and recommend measures to improve subscriber services across India.
- समिति का उद्देश्य कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करना, नौकरशाही में देरी को कम करना और पूरे भारत में सदस्यों की सेवा में सुधार के लिए उपाय सुझाना है।
- It will also propose structural changes to support digital transformation and align workforce capability with AI-based systems for gig and unorganised sector workers.
- यह डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने के लिए संरचनात्मक बदलावों का प्रस्ताव भी

रखेगी और गिग एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कार्यबल की क्षमता को AI-आधारित सिस्टम के साथ संरेखित करेगी।

- The final report of the committee is expected by 31 March 2026.
- समिति की अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च 2026 तक अपेक्षित है।

Ques: What is the main objective of the Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) and the 'Aapki Poonji Aapka Adhikar' campaign?

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना)PMMY) और 'आपकी पूँजी आपका अधिकार' अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) To provide education loans to students / छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करना
B) To fund small & micro entrepreneurs and raise awareness on unclaimed financial assets / लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को वित्तपोषण देना और अवैतनिक वित्तीय संपत्तियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना
C) To build new banking infrastructure in rural areas / ग्रामीण क्षेत्रों में नया बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना
D) To offer insurance to all citizens / सभी नागरिकों को बीमा प्रदान करना
E) To increase government tax revenue / सरकार की कर आय बढ़ाना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY), launched in April 2015 by PM Narendra Modi, aims to provide collateral-free loans to support small and micro entrepreneurs.
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना)PMMY), जिसे अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को बिना संपार्श्विक ऋण देने का उद्देश्य रखती है।
- Loans sanctioned under PMMY have reached Rs 34 lakh crore, benefiting 55 crore people, with the loan limit increased from Rs 10 lakh to Rs 20 lakh in Budget 2024-25.
- PMMY के तहत अब तक 34 लाख करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 55 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं, और ऋण सीमा बजट 2024-25 में 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।
- The 'Aapki Poonji Aapka Adhikar' campaign, launched by Finance Minister

Nirmala Sitharaman in October 2025, focuses on creating awareness about unclaimed financial assets like insurance claims, bank deposits, dividends, shares, and mutual fund proceeds.

- 'आपकी पूँजी आपका अधिकार' अभियान, जिसे अक्टूबर 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया, बीमा दावा, बैंक जमा, लाभांश, शेयर और म्यूचुअल फंड जैसी अवैतनिक वित्तीय संपत्तियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है।
- The campaign provides on-the-spot guidance to citizens to search, update records, and claim unclaimed assets using digital tools and demonstrations.
- यह अभियान नागरिकों को डिजिटल टूल्स और डेमो के माध्यम से अवैतनिक संपत्तियों की खोज, रिकॉर्ड अपडेट और दावा प्रक्रिया पूरी करने में तुरंत मार्गदर्शन प्रदान करता है।

**Ques: What is the main objective of the MoU signed between SBI and BOI?
SBI और BOI के बीच किए गए MoU का मुख्य उद्देश्य क्या है?**

- A) Launching new retail banking services / नई रिटेल बैंकिंग सेवाएँ शुरू करना
- B) Establishing a Centre of Excellence in Strategic Partnership / रणनीतिक साझेदारी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना
- C) Merging both banks / दोनों बैंकों का विलय
- D) Expanding international branches / अंतरराष्ट्रीय शाखाओं का विस्तार
- E) Offering microfinance to rural areas / ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रोफाइनेंस प्रदान करना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- State Bank of India (SBI) and Bank of India (BOI) have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to jointly establish a Centre of Excellence (CoE) in Strategic Partnership.
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने रणनीतिक साझेदारी में उत्कृष्टता केंद्र (CoE) स्थापित करने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
- The initiative aims to strengthen leadership and expertise in project financing across India.
- इस पहल का उद्देश्य भारत भर में परियोजना वित्तपोषण में नेतृत्व और विशेषज्ञता को सुदृढ़ करना है।
- Key areas of focus include joint financing for big projects, enhanced brand

presence, and employee training and development.

- मुख्य फोकस क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए संयुक्त वित्तपोषण, ब्रांड की उपस्थिति को बढ़ाना और कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं विकास शामिल हैं।

About State Bank of India (SBI):

- Established : 01 July 1955
- HQ : Mumbai, Maharashtra
- Chairman : Challa Sreenivasulu Setty

About Bank of India:

- Established : 1906
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Rajneesh Karnatak
- Tagline : Relationship Beyond Banking

Ques: Which Indian state received the highest share of FDI Equity inflow in the first half of FY 2025-26?

FY 2025-26 की पहली छमाही में किस भारतीय राज्य ने सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त किया?

- A) Karnataka / कर्नाटक
- B) Gujarat / गुजरात
- C) Tamil Nadu / तमिल नाडु
- D) Maharashtra / महाराष्ट्र
- E) Telangana / तेलंगाना

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- India's FDI inflow surged 18% to \$35.18 billion during April–September 2025-26, with the U.S. showing the sharpest rise among major contributors.
- भारत का एफडीआई प्रवाह अप्रैल–सितंबर 2025-26 में 18% बढ़कर \$35.18 बिलियन हो

गया, जिसमें अमेरिका प्रमुख देशों में सबसे तेज वृद्धि दिखा।

- The services sector, particularly financial and business services, attracted the highest share of FDI.

- सेवा क्षेत्र, विशेषकर वित्तीय और व्यापार सेवाओं, ने सबसे अधिक एफडीआई आकर्षित किया।

- Top investing countries included Singapore, Mauritius, and the U.S.A.

- शीर्ष निवेशक देशों में सिंगापुर, मॉरीशस और अमेरिका शामिल हैं।

- Maharashtra received the highest FDI share at 31% (\$10,571 million), followed by Karnataka (21%) and Gujarat (15%).

- महाराष्ट्र ने 31% के साथ सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया कुल)\$10,571 मिलियन(, इसके बाद कर्नाटक)21%) और गुजरात)15%) रहे।

Ques: How much amount is the government expected to raise by selling its 6% stake in Bank of Maharashtra?

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी 6% हिस्सेदारी बेचकर सरकार कितनी राशि जुटाने की उम्मीद कर रही है?

A) ₹1,850 crore

B) ₹2,000 crore

C) ₹2,492 crore

D) ₹3,100 crore

E) ₹4,250 crore

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The government diluted a 6% stake in Bank of Maharashtra (BoM) through an Offer-for-Sale (OFS), with a floor price of ₹54 per share.

- सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) में अपनी 6% हिस्सेदारी ऑफर) सेल-फॉर-OFS) के माध्यम से बेची, जिसका फ्लोर प्राइस ₹54 प्रति शेयर था।

- The stake sale is expected to raise around ₹2,492 crore for the government.

- इस हिस्सेदारी बिक्री से सरकार लगभग ₹2,492 करोड़ जुटाने की उम्मीद कर रही है।

- After share allotment, BoM will comply with SEBI's Minimum Public Shareholding (MPS) norms.

- शेयर आवंटन के बाद BoM SEBI के न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी (MPS) मानदंडों का

पालन करेगा।

- Prior to the OFS, the government held a 79.60% stake in BoM.
- OFS से पहले सरकार की BoM में हिस्सेदारी 79.60% थी।
- Bank of Maharashtra is headquartered in Pune, Maharashtra.
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है।
- The oversubscribed OFS helped the government raise funds while also supporting BoM in meeting regulatory public shareholding requirements.
- अधिक मांग वाली OFS ने सरकार को फंड जुटाने में मदद की और साथ ही BoM को नियामक न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी मानदंडों को पूरा करने में भी सहायता दी।

Ques: What recent initiative has Tamilnad Mercantile Bank (TMB) launched to improve loan processing?

तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक (TMB) ने ऋण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में कौन सा नया कदम उठाया है?

- A) Digital Savings Account Platform / डिजिटल सेविंग्स अकाउंट प्लेटफॉर्म
- B) Loan Origination System (LOS) / लोन ऑरिजिनेशन सिस्टम (LOS)
- C) Mobile Wallet App / मोबाइल वॉलेट ऐप
- D) Investment Advisory Portal / निवेश परामर्श पोर्टल
- E) Blockchain-based Payment System / ब्लॉकचेन प्रणाली भुगतान आधारित-

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Tamilnad Mercantile Bank (TMB) has launched a new Loan Origination System (LOS) developed with Nucleus Software to streamline loan processing.
- तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक (TMB) ने Nucleus Software के साथ मिलकर ऋण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए नया लोन ऑरिजिनेशन सिस्टम (LOS) लॉन्च किया है।
- The system aims for faster, standardized, and more accurate loan processing with automated checks and digital workflows.
- यह सिस्टम तेज़, मानकीकृत और अधिक सटीक ऋण प्रक्रिया के लिए ऑटोमेटेड चेक और डिजिटल वर्कफ्लो के साथ तैयार किया गया है।
- Uniform appraisal mechanism is included to ensure consistent credit decisions and improved customer experience.

- इसमें एक समान मूल्यांकन तंत्र शामिल है ताकि लगातार बेहतर क्रेडिट निर्णय लिए जा सकें और ग्राहक अनुभव में सुधार हो।
- The new system is expected to reduce Turn Around Time (TAT) for loan approvals.
- नए सिस्टम से ऋण अनुमोदन के टर्नअराउंड टाइम (TAT) में कमी आने की उम्मीद है।

Ques: Which projects did the Asian Development Bank (ADB) approve loans for in Assam and Meghalaya?

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने असम और मेघालय में किन परियोजनाओं के लिए ऋण को मंजूरी दी?

- A) Assam – Infrastructure, Meghalaya – Renewable Energy / असम – अवसंरचना, मेघालय – नवीकरणीय ऊर्जा
- B) Assam – Healthcare & Medical Education, Meghalaya – Ecotourism / असम – स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा, मेघालय – इकोटूरिज़्म
- C) Assam – Agriculture, Meghalaya – Water Supply / असम – कृषि, मेघालय – जल आपूर्ति
- D) Assam – Transport, Meghalaya – Education / असम – परिवहन, मेघालय – शिक्षा
- E) Assam – Industrial Development, Meghalaya – Mining / असम – औद्योगिक विकास, मेघालय – खनन

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Asian Development Bank (ADB) approved USD 398.8 million for healthcare transformation and medical education projects in Assam.
- एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने असम में स्वास्थ्य देखभाल सुधार और चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के लिए 398.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर मंजूर किए।
- A separate loan of USD 77 million was approved for the Ecotourism project in Meghalaya.
- मेघालय में इकोटूरिज़्म परियोजना के लिए अलग से 77 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया गया।
- The loans aim to improve healthcare infrastructure in Assam and promote sustainable tourism in Meghalaya.

- इन ऋणों का उद्देश्य असम में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में सुधार करना और मेघालय में सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है।

About Asian Development Bank :

- Established : 19 December 1966
- HQ : Manila, Philippines
- Members : 69
- Chief Economist : Albert Park
- President : Masato Kanda

Ques: What is the significance of Indian banks achieving ISO 20022 readiness?

भारतीय बैंकों द्वारा ISO 20022 मानक की तैयारी पूरी करने का महत्व क्या है?

- A) To expand domestic ATM networks / घरेलू एटीएम नेटवर्क का विस्तार करना
- B) To enable richer, structured, and detailed payment data for cross-border transactions / सीमासमृद्ध लिए के लेनदेन पार-, संरचित और विस्तृत भुगतान डेटा सक्षम करना
- C) To reduce interest rates on loans / ऋण पर ब्याज दरें कम करना
- D) To merge all public sector banks / सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करना
- E) To launch a new digital currency / नई डिजिटल मुद्रा लॉन्च करना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Indian banks have fully implemented SWIFT's ISO 20022 messaging standard ahead of the 22 November 2025 deadline.
- भारतीय बैंकों ने 22 नवंबर 2025 की समय सीमा से पहले SWIFT के ISO 20022 मैसेजिंग मानक को पूरी तरह लागू कर लिया है।
- With 100% readiness, India has outperformed the global compliance average of 87%.
- 100% तैयारियों के साथ, भारत ने वैश्विक अनुपालन औसत 87% को पीछे छोड़ दिया है।
- ISO 20022 enables richer, structured, and detailed payment data, improving

analytics, compliance, and fraud-prevention capabilities.

- ISO 20022 समृद्ध, संरचित और विस्तृत भुगतान डेटा सक्षम करता है, जो विश्लेषण, अनुपालन और धोखाधड़ी है। बनाता बेहतर को क्षमताओं रोकथाम-
- The transition began in March 2023, with a coexistence period allowing exchange of both MT and ISO 20022 messages; after 22 November 2025, ISO 20022 becomes mandatory for all cross-border payments.
- मार्च 2023 में संक्रमण शुरू हुआ, जिसमें MT और ISO 20022 संदेशों का आदान प्रदान-थी गई रखी अवधि अस्तित्व-सह लिए के करने; 22 नवंबर 2025 के बाद सभी सीमा पार-लिए के भुगतान ISO 20022 अनिवार्य हो जाएगा।
- Non-compliant banks may face severe payment disruptions and penalties.
- जो बैंक इस मानक का पालन नहीं करेंगे, उन्हें गंभीर भुगतान व्यवधान और संभावित दंड का सामना करना पड़ सकता है।

Ques: NPCI International Payments partnered with ACLEDA Bank of which country to enable UPI acceptance?

NPCI International Payments ने किस देश के ACLEDA Bank के साथ साझेदारी की है ताकि UPI वहाँ स्वीकार किया जा सके?

- A) Thailand / थाईलैंड
- B) Vietnam / वियतनाम
- C) Cambodia / कंबोडिया
- D) Singapore / सिंगापुर
- E) Malaysia / मलेशिया

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- NPCI International Payments (NIPL) has partnered with Cambodia-based ACLEDA Bank to enable acceptance of India's real-time digital payment system UPI in Cambodia.
- NPCI International Payments (NIPL) ने कंबोडिया के ACLEDA बैंक के साथ साझेदारी की है ताकि कंबोडिया में भारत का रीयल-टाइम डिजिटल भुगतान सिस्टम UPI स्वीकार किया जा सके।
- The partnership will also allow India to accept Cambodia's national QR

network Bakong (KHQR), facilitating cross-border payments.

- यह साझेदारी भारत में कंबोडिया के राष्ट्रीय QR नेटवर्क Bakong (KHQR) को स्वीकार करने की सुविधा भी प्रदान करेगी, जिससे सीमा पार भुगतान आसान होंगे।
- Indians and Cambodians will be able to pay via QR codes at tourist spots, restaurants, and retail outlets in both countries, promoting seamless and faster cross-border transactions.
- भारतीय और कंबोडियाई नागरिक दोनों देशों में पर्यटन स्थलों, रेस्टोरेंट्स और रिटेल दुकानों पर QR कोड के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे, जिससे सीमा पार लेनदेन आसान और तेज़ होंगे।

Ques: By what percentage did consumer grievances under the RBI's Ombudsman framework increase in FY25 compared to FY24?

आरबीआई के लोकपाल ढांचे के तहत उपभोक्ता शिकायतों में FY24 की तुलना में FY25 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

- A) 10.25%
- B) 11.80%
- C) 17.40%
- D) 15.20%
- E) 13.55%

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- Consumer grievances under the Reserve Bank of India's ombudsman framework saw a notable rise in FY25, indicating growing dissatisfaction with banking and financial services.
- आरबीआई के लोकपाल ढांचे के तहत उपभोक्ता शिकायतों में FY25 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से बढ़ती असंतुष्टि को दर्शाती है।
- Under the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, complaints increased to 13,34,244 in FY25 from 11,75,075 in FY24, marking a 13.55% rise.
- Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme के तहत शिकायतें FY24 के 11,75,075 से बढ़कर FY25 में 13,34,244 हो गईं, यानी 13.55% की वृद्धि।
- Of the total complaints, the 24 RBI Ombudsman Offices received 2,96,321, while the Centralised Receipt and Processing Centre (CRPC) handled 9,11,384

cases and forwarded many to ombudsman offices and Consumer Education and Protection Cells (CEPCs).

- कुल शिकायतों में से 24 आरबीआई लोकपाल कार्यालयों को 2,96,321 शिकायतें मिलीं, जबकि CRPC ने 9,11,384 मामलों को संसाधित किया और कई को लोकपाल कार्यालयों व CEPC को भेजा।
- Over 7.7 lakh cases were marked as non-maintainable and closed at the CRPC level.
- 7.7 लाख से अधिक मामलों को गैर-उपयुक्त मानकर CRPC स्तर पर बंद कर दिया गया।
- Complaints against banks were the highest at 2.41 lakh (81.53%), followed by NBFCs with 43.8K cases (14.80%).
- बैंकों के खिलाफ शिकायतें सबसे अधिक 2.41 लाख (81.53%) रहीं, इसके बाद NBFCs की 43.8K (14.80%) शिकायतें रहीं।
- Complaints against private sector banks rose from 34.39% to 37.53%, while those against public sector banks declined from 38.32% to 34.80%.
- निजी क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ शिकायतें 34.39% से बढ़कर 37.53% हो गईं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शिकायतें 38.32% से घटकर 34.80% रह गईं।
- Loans and advances accounted for the highest complaints at 29.25%, followed by credit cards (17.15%), mobile/electronic banking (16.86%), and deposit account opening (16.84%).
- ऋण और अग्रिम से संबंधित शिकायतें सबसे अधिक 29.25% रहीं, इसके बाद क्रेडिट कार्ड (17.15%), मोबाइल/ई-बैंकिंग (16.86%) और जमा खाता खोलने (16.84%) से संबंधित शिकायतें रहीं।
- Metro cities recorded the most complaints at 45.86%, followed by urban (25.64%), semi-urban (18.46%), and rural areas (10.04%).
- मेट्रो शहरों में सबसे अधिक 45.86% शिकायतें दर्ज हुईं, इसके बाद शहरी (25.64%), अर्ध-शहरी (18.46%) और ग्रामीण क्षेत्रों (10.04%) में शिकायतें दर्ज हुईं।
- The complaint disposal rate fell from 95.10% in FY24 to 93.07% in FY25.
- शिकायत निस्तारण दर FY24 के 95.10% से घटकर FY25 में 93.07% हो गई।

Ques: What was the year-on-year (YoY) growth of bank credit in India as of 14 November 2025?

14 नवंबर 2025 तक भारत में बैंक क्रेडिट की वर्ष (वर्ष-दर-YoY) वृद्धि कितनी रही?

- A) 9.5%
- B) 10.2%
- C) 11.4%
- D) 11.5%

E) 12.0%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- As of 14 November 2025, India's bank credit growth on a year-on-year (YoY) basis stood at 11.4%.
- 14 नवंबर 2025 तक भारत में बैंक क्रेडिट की वर्ष) वर्ष-दर-YoY) वृद्धि 11.4% रही।
- Deposit growth during the same period rose to 10.2% from 9.5% two weeks earlier, indicating healthy liquidity in the system.
- इसी अवधि में जमाओं की वृद्धि 9.5% से बढ़कर 10.2% हो गई, जो प्रणाली में स्वस्थ तरलता को दर्शाती है।
- Gold loans continued their triple-digit surge, up 129% YoY to Rs 41,409 crore as of 31 October 2025.
- सोने के ऋण में लगातार तीन अंकों की वृद्धि हुई, जो 31 अक्टूबर 2025 तक 129% YoY बढ़कर ₹41,409 करोड़ हो गया।
- Consumer durable loans grew only 1% to Rs 23,646 crore, reflecting a weak festive demand compared to 6.9% growth last year.
- उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के ऋण में केवल 1% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की 6.9% वृद्धि की तुलना में त्योहारों के कमजोर प्रभाव को दर्शाता है।
- Outstanding bank credit as of 14 November 2025 was Rs 194 lakh crore, while outstanding deposits stood at Rs 241 lakh crore.
- 14 नवंबर 2025 तक बकाया बैंक क्रेडिट ₹194 लाख करोड़ और बकाया जमा ₹241 लाख करोड़ था।

Ques: Under RBI's new metal loan norms, loans will NOT be provided against which of the following?

आरबीआई के नए मेटल लोन नियमों के तहत किस वस्तु पर लोन नहीं दिया जाएगा?

- A) Gold Jewellery / सोने के आभूषण
- B) Silver Coins / चांदी के सिक्के
- C) Bullion (Gold/Silver Bars) / बुलियन (सोना/चांदी बार)
- D) Silver Jewellery / चांदी के आभूषण
- E) Gold Coins / सोने के सिक्के

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- RBI has liberalized metal loan rules, allowing banks and NBFCs to provide loans against gold and silver jewellery or coins.
- आरबीआई ने मेटल लोन नियमों को उदार बनाते हुए बैंकों और NBFCs को सोने और चांदी के आभूषण या सिक्कों के बदले लोन देने की अनुमति दी है।
- The new norms will come into effect from April 1, 2026, and apply to commercial banks, SFBs, RRBs, UCBs, cooperative banks, NBFCs, and HFCs.
- नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और ये वाणिज्यिक बैंक, SFBs, RRBs, UCBs, सहकारी बैंक, NBFCs और HFCs पर लागू होंगे।
- Loans can be given only against gold/silver jewellery or coins; loans against bullion (gold/silver bars), ETFs, or mutual fund units are not allowed.
- लोन केवल सोने/चांदी के आभूषण या सिक्कों पर ही दिया जाएगा; बुलियन (सोना/चांदी बार), ETFs या MF units पर लोन की अनुमति नहीं है।
- RBI has specified pledging limits: Gold jewellery—1 kg, Silver jewellery—10 kg, Gold coins—50 g, Silver coins—500 g.
- RBI ने पेंडिंग लिमिट तय की हैं: सोने के आभूषण—1 किलो, चांदी के आभूषण—10 किलो, सोने के सिक्के—50 ग्राम, चांदी के सिक्के—500 ग्राम।
- The move aims to streamline lending, enhance transparency, and strengthen risk management.
- यह कदम लेंडिंग को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है।

Ques: Which state received USD 109.97 million under the Skills Development Programme?

कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 109.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर किस राज्य को प्राप्त हुए?

- A) Gujarat / गुजरात
- B) Punjab / पंजाब
- C) Haryana / हरियाणा
- D) Odisha / ओडिशा
- E) Tamil Nadu / तमिलनाडु

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- Maharashtra received USD 500 million for the Power Distribution Enhancement Programme, aimed at modernising rural power infrastructure and supplying daytime solar electricity to farmers.
- महाराष्ट्र को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता पावर डिस्ट्रीब्यूशन एन्हांसमेंट प्रोग्राम के लिए मिली, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विद्युत अवसंरचना का आधुनिकीकरण और किसानों को दिन के समय सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है।
- Madhya Pradesh received USD 190.6 million for the Indore Metro Rail Project, supporting an 8.62 km underground metro line with 7 stations, improving connectivity to Indore Airport.
- मध्य प्रदेश को 190.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए मिली, जो 8.62 किमी भूमिगत मेट्रो लाइन और 7 स्टेशनों के निर्माण के लिए है, जिससे इंदौर हवाई अड्डे से कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
- Gujarat received USD 109.97 million under the Skills Development Programme, to upgrade 11 mega ITIs, establish centres of excellence, and train youth in high-growth sectors.
- गुजरात को 109.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्राप्त हुए, जिसका उद्देश्य 11 मेगा आईटीआई का उन्नयन, उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और युवाओं को उच्च-विकास क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना है।

Ques: LIC has recently signed a bancassurance pact with which bank to expand customer access to life insurance products?

LIC ने हाल ही में किस बैंक के साथ बैंकएश्योरेंस समझौता किया है ताकि ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पादों तक पहुँच बढ़ाई जा सके?

- A) Yes Bank / यस बैंक
- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- LIC has entered into a strategic bancassurance partnership with Yes Bank to provide its life insurance products to customers through both branches and digital platforms.
 - LIC ने Yes Bank के साथ एक रणनीतिक बैंकएश्योरेंस साझेदारी की है ताकि ग्राहक शाखाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से LIC के जीवन बीमा उत्पादों तक पहुँच सकें।
 - The partnership leverages LIC's network of over 3,600 branches and satellite offices, combined with Yes Bank's branch network.
 - यह साझेदारी LIC की 3,600 से अधिक शाखाओं और सैटेलाइट कार्यालयों और Yes Bank के नेटवर्क की संयुक्त ताकत का उपयोग करेगी।
 - The agreement aims to increase insurance penetration and expand customer reach across India.
 - यह समझौता बीमा कवरेज बढ़ाने और भारत में ग्राहक पहुँच का विस्तार करने का लक्ष्य रखता है।
 - Customers can now access LIC's life insurance offerings seamlessly through Yes Bank's physical and digital channels.
 - अब ग्राहक Yes Bank के भौतिक और डिजिटल चैनलों के माध्यम से LIC के जीवन बीमा उत्पादों तक सहज पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।
-

Ques: How many Aadhaar authentication transactions were executed in November 2025?

नवंबर 2025 में कितनी आधार प्रमाणीकरण लेन-देन की गईं?

- A) 219 crore
- B) 231 crore
- C) 250 crore
- D) 200 crore
- E) 245 crore

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Aadhaar number holders executed 231 crore authentication transactions in November 2025, showing a growth of almost 8.5% compared to November 2024.
- नवंबर 2025 में आधार धारकों ने 231 करोड़ प्रमाणीकरण लेन-देन किए, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 8.5% की वृद्धि दर्शाता है।
- In October 2025, 219.51 crore transactions were recorded, showing month-on-month growth.
- अक्टूबर 2025 में 219.51 करोड़ लेन-देन दर्ज हुए, जिससे महीने-दर-महीने वृद्धि स्पष्ट होती है।
- Nearly 60% of Digital Life Certificates generated by pensioners used Aadhaar face authentication; overall, 28.29 crore face authentication transactions were done in November 2025, up from 12.04 crore in Nov 2024.
- लगभग 60% डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनभोगियों द्वारा आधार फेस प्रमाणीकरण का उपयोग कर उत्पन्न किए गए; कुल 28.29 करोड़ फेस प्रमाणीकरण लेन-देन नवंबर 2025 में हुए, जबकि नवंबर 2024 में 12.04 करोड़ थे।
- e-KYC transactions also rose significantly to 47.19 crore in November 2025, a more than 24% increase from November 2024.
- e-KYC लेन-देन भी नवंबर 2025 में 47.19 करोड़ तक बढ़ गए, जो नवंबर 2024 की तुलना में 24% से अधिक की वृद्धि है।

Ques: As per the fiscal data for April–October 2025, India’s fiscal deficit stood at what level?

अप्रैल-अक्टूबर 2025 के वित्तीय आँकड़ों के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा किस स्तर पर रहा?

- A) ₹6 lakh crore
- B) ₹7.2 lakh crore
- C) ₹8.25 lakh crore
- D) ₹9.5 lakh crore
- E) ₹10 lakh crore

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- In April–October 2025, India’s fiscal deficit reached ₹8.25 lakh crore, which is 52.6% of the FY26 target.
- अप्रैल–अक्तूबर 2025 में भारत का राजकोषीय घाटा ₹8.25 लाख करोड़ रहा, जो FY26 लक्ष्य का 52.6% है।
- Net tax receipts stood at ₹12.74 lakh crore, slightly lower than ₹13.05 lakh crore in the same period of 2024.
- शुद्ध कर प्राप्तियाँ ₹12.74 लाख करोड़ रहीं, जो 2024 की समान अवधि के ₹13.05 लाख करोड़ से थोड़ी कम हैं।
- Non-tax revenue increased to ₹4.89 lakh crore, compared to ₹4 lakh crore last year.
- गैर-कर राजस्व बढ़कर ₹4.89 लाख करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह ₹4 लाख करोड़ था।
- Total expenditure rose to ₹26.26 lakh crore, up from ₹24.7 lakh crore in the previous year.
- कुल व्यय बढ़कर ₹26.26 लाख करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह ₹24.7 लाख करोड़ था।
- Capital expenditure (Capex) sharply increased to ₹6.18 lakh crore, compared to ₹4.7 lakh crore in April–October 2024.
- पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) बढ़कर ₹6.18 लाख करोड़ हो गया, जो अप्रैल–अक्तूबर 2024 के ₹4.7 लाख करोड़ से काफी अधिक है।
- Fiscal stance remains focused on infrastructure-led growth.
- सरकार का वित्तीय फोकस अवसंरचना-प्रधान विकास पर बना हुआ है।
- Concern remains over revenue shortfall amid rising expenditure.
- बढ़ते व्यय के बीच राजस्व की कमी चिंता का विषय बनी हुई है।

Ques: ESAF Small Finance Bank recently received an upgraded ESG rating.

What is its new ESG score as per CareEdge Ratings?

ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को हाल ही में CareEdge द्वारा उन्नत ESG रेटिंग मिली। नया ESG स्कोर क्या है?

- A) 62.3
- B) 68.1
- C) 71.9
- D) 75.4
- E) 82.6

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- ESAF Small Finance Bank received one of the highest ESG ratings in Indian banking.
- ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सबसे उच्च ESG रेटिंग्स में से एक प्राप्त हुई।
- CareEdge ESG Ratings upgraded its score to 75.4, placing the bank in the CareEdge-ESG 1 category.
- CareEdge ESG Ratings ने बैंक का स्कोर बढ़ाकर 75.4 कर दिया, जिससे यह CareEdge-ESG 1 श्रेणी में शामिल हो गया।
- The previous year's ESG score was 68.1, showing a significant improvement.
- पिछले वर्ष का स्कोर 68.1 था, जो महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है।
- ESAF SFB demonstrated strong performance across Environmental, Social, and Governance parameters with best-in-class disclosures.
- पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक तीनों ही मापदंडों पर ESAF SFB ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, और इसके खुलासे भी सर्वोत्तम श्रेणी के हैं।
- The Social pillar score was 82.6, well above the industry median.
- सामाजिक स्तंभ का स्कोर 82.6 रहा, जो उद्योग के औसत से काफी अधिक है।
- Key strengths include community development programmes, priority-sector lending, and a women-centric financial inclusion model.
- प्रमुख ताकतों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्राथमिक क्षेत्र ऋण और महिला केंद्रित-हैं। शामिल मॉडल समावेशन वित्तीय
- With a score of 75.4, ESAF SFB ranks among the top-performing institutions under the SEBI ESG framework.
- 75.4 के स्कोर के साथ, ESAF SFB SEBI ESG ढांचे के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं में शामिल है।

Ques: As per NABARD, agricultural credit from banks is expected to reach what level in FY26?

NABARD के अनुसार, FY26 में बैंकों से कृषि ऋण किस स्तर तक पहुँचने का अनुमान है?

- A) ₹25 lakh crore
- B) ₹28.69 lakh crore
- C) ₹30 lakh crore
- D) ₹32.5 lakh crore

E) ₹35 lakh crore

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Credit to agriculture from commercial banks and regional rural banks (RRBs) is expected to exceed ₹32.5 lakh crore in FY26, the highest ever, according to NABARD.
- NABARD के अनुसार, FY26 में वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) द्वारा कृषि क्षेत्र को ₹32.5 लाख करोड़ से अधिक ऋण देने का अनुमान है, जो अब तक का सबसे उच्च स्तर होगा।
- This growth is driven by rising formalisation of rural lending and increasing credit demand.
- ग्रामीण ऋण के औपचारिककरण और बढ़ती ऋण मांग के कारण यह वृद्धि हो रही है।
- In the first half of FY26, banks have already disbursed ₹14.51 lakh crore in farm loans.
- FY26 की पहली छमाही में ही बैंकों ने ₹14.51 लाख करोड़ कृषि ऋण वितरित कर दिया है।
- FY25 performance: Total agriculture credit was ₹28.69 lakh crore, provided by commercial banks, cooperatives, and RRBs.
- FY25 प्रदर्शन: कुल कृषि ऋण ₹28.69 लाख करोड़ रहा, जिसे वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी संस्थाओं और RRBs ने प्रदान किया।
- Loan share : 60%: short-term crop loans and 40%: investment credit (agriculture + allied sectors)
- ऋण वितरण: 60%: अल्पकालिक फसल ऋण और 40%: निवेश ऋण (कृषि + संबद्ध क्षेत्र)
- Regional disparity: Southern states (AP, Telangana, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu) received 48% of agricultural loans in FY25, despite having only 17% of India's gross cropped area.
- क्षेत्रीय असमानता: दक्षिणी राज्यों को FY25 में 48% कृषि ऋण मिला, जबकि उनके पास भारत के सकल बोया क्षेत्र का केवल 17% हिस्सा है।
- NABARD identifies the causes as weak rural financial infrastructure and low financial literacy in many other states.
- NABARD के अनुसार, कई राज्यों में ग्रामीण वित्तीय अवसंरचना कमजोर है और वित्तीय साक्षरता कम होने से यह असमानता बढ़ती है।
- Kisan Credit Cards (KCC) and formal banking channels are expected to help banks achieve the FY26 target of ₹32.5 lakh crore.
- FY26 के ₹32.5 लाख करोड़ लक्ष्य को हासिल करने में KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) और औपचारिक बैंकिंग चैनल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

Ques: Who has been appointed as the Chief Executive Officer (CEO) of Bank of America NA in India?

भारत में बैंक ऑफ अमेरिका NA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Kaku Nakhate / काकु नखाते
- B) Vikram Sahu / विक्रम साहू
- C) Shombi Sharp / शॉम्बी शार्प
- D) Antonio Guterres / एंटोनियो गुटेरेस
- E) Bhupender Yadav / भूपेंद्र यादव

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Vikram Sahu has been appointed as the Chief Executive Officer (CEO) of Bank of America NA (BANA) in India for a tenure of three years.
 - विक्रम साहू को भारत में बैंक ऑफ अमेरिका NA (BANA) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है।
 - He replaces Kaku Nakhate, who has been elevated to the role of Chair of Bank of America India.
 - उन्होंने काकु नखाते का स्थान लिया है, जिन्हें बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया के चेयर पद पर पदोन्नत किया गया है।
 - Bank of America NA India was established in 1964 and has its headquarters in Mumbai.
 - बैंक ऑफ अमेरिका NA इंडिया की स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
-

Ques: As per Fitch Ratings' Global Economic Outlook (December 2025), what is India's revised GDP growth forecast for FY26?

फिच रेटिंग्स की ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक (दिसंबर)2025) रिपोर्ट के अनुसार, FY26 के लिए भारत की संशोधित GDP वृद्धि दर क्या है?

- A) 6.2%

- B) 6.4%
- C) 6.9%
- D) 7.4%
- E) 7.8%

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Fitch Ratings released its “Global Economic Outlook (GEO) – December 2025” report.
 - फिच रेटिंग्स ने अपनी “ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक (GEO) – दिसंबर 2025” रिपोर्ट जारी की।
 - The agency revised India’s GDP growth forecast for FY26 upward to 7.4%, from its earlier estimate of 6.9%.
 - एजेंसी ने FY26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर को 6.9% से बढ़ाकर 7.4% कर दिया।
 - The report further projects that India’s GDP growth will slow to 6.4% in FY27.
 - रिपोर्ट के अनुसार FY27 में भारत की GDP वृद्धि दर घटकर 6.4% होने की उम्मीद है।
 - India’s growth rate is expected to moderate further to 6.2% in FY28.
 - FY28 में यह दर और घटकर 6.2% होने का अनुमान है।
-

Ques: Why did India’s GST collections soften in November 2025?

भारत में नवंबर 2025 में GST संग्रह क्यों धीमा हुआ?

- A) Decline in exports / निर्यात में गिरावट
- B) Rationalisation move reducing GST rates on hundreds of items / सैकड़ों वस्तुओं पर GST दरें घटाने के कारण
- C) Increase in fuel prices / ईंधन की कीमतों में वृद्धि
- D) Delayed tax filings / कर दाखिल करने में देरी
- E) Economic slowdown / आर्थिक मंदी

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- India's GST collections in November 2025 softened due to the rationalisation move that reduced indirect tax rates on 375 items, including soaps and small cars.
- भारत में नवंबर 2025 में GST संग्रह धीमा हुआ क्योंकि सरकार ने 375 वस्तुओं जैसे) टाकर कर स्लैब को दोपर अप्रत्यक्ष कर दरें घ (साबुन और छोटी कारें 5% और 18%) में समेकित किया।
- Gross GST revenue rose only 0.7% year-on-year to ₹1,70,276 crore in November 2025, compared to ₹1.95 lakh crore in October 2025.
- सकल GST राजस्व नवंबर 2025 में मात्र 0.7% की वृद्धि के साथ ₹1,70,276 करोड़ रहा, जबकि अक्टूबर 2025 में यह ₹1.95 लाख करोड़ था।
- The move also introduced a 40% slab for sin and luxury goods while removing the compensation cess.
- इस कदम में पाप और विलासिता वस्तुओं के लिए 40% का नया स्लैब और क्षतिपूर्ति शुल्क समाप्त किया गया।

GST Collection of Previous Months :

- Oct 2025 : 1,95,936 Crore
- Sep 2025 : 1,87,346 crore
- August 2025 : 1,86,315 Crore
- July 2025 : 1,95,735 Crore
- June 2025 : 1,84,567 Crore

Ques: What was India's current account deficit (CAD) as a percentage of GDP in Q2 FY26?

भारत में चालू खाता घाटा (CAD) Q2 FY26 में GDP के कितने प्रतिशत के रूप में था?

- A) 0.2%
- B) 4.1%
- C) 2.2%
- D) 3.0%
- E) 1.3%

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- As per RBI data, India's current account deficit (CAD) moderated to \$12.3 billion, which is 1.3% of GDP in July–September 2025 (Q2 FY26), compared to \$20.8 billion, or 2.2% of GDP, in the same period last year.
- RBI के आंकड़ों के अनुसार, भारत का चालू खाता घाटा (CAD) जुलाई–सितंबर 2025 (Q2 FY26) में \$12.3 बिलियन यानी GDP का 1.3% रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह \$20.8 बिलियन या GDP का 2.2% था।
- The merchandise trade deficit also narrowed to \$87.4 billion from \$88.5 billion a year earlier.
- वस्तु व्यापार घाटा भी \$88.5 बिलियन से घटकर \$87.4 बिलियन हो गया।
- Non-resident deposits declined from \$6.2 billion to \$2.5 billion.
- गैर निवासी जमा-\$6.2 बिलियन से घटकर \$2.5 बिलियन हो गए।

Ques: What measures has the RBI announced to inject durable liquidity amid rupee depreciation?

रुपये के मूल्य में गिरावट के बीच स्थायी तरलता बढ़ाने के लिए RBI ने कौन से उपाय घोषित किए हैं?

- A) Repo rate hike / रेपो दर बढ़ाना
- B) Open Market Operation purchases & dollar–rupee swaps / ओपन मार्केट ऑपरेशन और डॉलर–रुपये स्वैप
- C) Cash reserve ratio reduction / नकद आरक्षित अनुपात में कटौती
- D) Forex intervention only / केवल विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप
- E) Government bond buyback / सरकारी बांड खरीद

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- RBI announced it will conduct Open Market Operation (OMO) purchases of government securities worth ₹1 trillion and a three-year dollar–rupee buy/sell swap of \$5 billion to inject durable liquidity into the financial system.
- RBI ने वित्तीय प्रणाली में स्थायी तरलता बढ़ाने के लिए ₹1 ट्रिलियन मूल्य के सरकारी प्रतिभूतियों की ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) खरीद और \$5 बिलियन के तीन वर्षीय

डॉलर-रुपये स्वैप की घोषणा की।

- OMOs matter when the rupee is under pressure because a sharp fall in the rupee often coincides with foreign investor outflows, which drain liquidity from the banking system.
- ओएमओ महत्वपूर्ण होते हैं जब रुपया दबाव में होता है क्योंकि रुपया तेजी से गिरने पर विदेशी निवेशकों के पैसे बाहर निकलते हैं, जिससे बैंकिंग प्रणाली से तरलता घटती है।
- OMO purchases help replenish this liquidity by injecting durable funds into banks.
- OMO खरीद से बैंक में स्थायी निधियों के जरिए यह तरलता पुनःपूर्ति होती है।

Ques: How many illegal loan lending apps were recently blocked by the Indian government?

भारतीय सरकार ने हाल ही में कितनी अवैध लोन ऐप्स को ब्लॉक किया?

- A) 87
- B) 67
- C) 45
- D) 102
- E) 120

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- The government blocked 87 illegal loan lending apps after completing the required legal procedures.
- आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सरकार ने 87 अवैध लोन ऐप्स को ब्लॉक कर दिया।
- The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) used Section 69A of the Information Technology Act, 2000, to block these apps.
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इन ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A का उपयोग किया।
- Companies running illegal online lending activities are subject to inquiries, account inspections, and investigations under the Companies Act, 2013, with legal action taken for any violations.

- अवैध ऑनलाइन लोन गतिविधियों को चलाने वाली कंपनियों के खिलाफ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जांच, खाता निरीक्षण और जांच की जाती है, और किसी भी उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है।
- The Ministry of Corporate Affairs is responsible for enforcing the Companies Act, 2013.
- कंपनी अधिनियम, 2013 को लागू करने की जिम्मेदारी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की है।

Ques: What decision was taken by the Sanjay Malhotra-headed Monetary Policy Committee (MPC) in its fifth bi-monthly meeting for FY26?

संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने FY26 की अपनी पाँचवीं द्विमासिक बैठक में क्या निर्णय लिया?

- A) Increased repo rate to 6.0% / रेपो दर 6.0% की गई
- B) Reduced repo rate to 5.25% / रेपो दर 5.25% की गई
- C) Kept repo rate unchanged at 5.50% / रेपो दर 5.50% पर स्थिर रखी गई
- D) Shifted stance to 'accommodative' / रुख 'उदार' किया गया
- E) Raised CRR by 50 bps / सीआरआर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The RBI Governor Sanjay Malhotra-led Monetary Policy Committee held its 58th and fifth bi-monthly meeting for FY26 from December 3 to 5.
- आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने FY26 की पाँचवीं द्विमासिक और 58वीं बैठक 3 से 5 दिसंबर तक आयोजित की।
- The six-member MPC unanimously voted to reduce the repo rate by 25 basis points—from 5.50% to 5.25%.
- छह सदस्यीय MPC ने सर्वसम्मति से 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर रेपो दर को 5.50% से घटाकर 5.25% करने का निर्णय लिया।
- The committee decided to continue with a 'neutral' monetary stance.
- समिति ने मौद्रिक रुख को 'तटस्थ' बनाए रखने का फैसला किया।

Various rates are as under with New Rate and Old Rate :

- Repo Rate : 5.25% (New rate) 5.50% (Old rate)
- Reverse Repo Rate : 3.35% (New rate) 3.35% (Old rate)
- Standing Deposit Facility (SDF) : 5.00% (New rate) 5.25% (Old rate)
- Marginal Standing Facility Rate : 5.50% (New rate) 5.75% (Old rate)
- Bank Rate : 5.50% (New rate) 5.75% (Old rate)
- Cash reserve ratio (CRR) : 3.00% (New rate) 3.50% (Old rate)
- Statutory Liquidity Ratio (SLR) : 18.00% (New rate) 18.00% (Old rate)

CPI Inflation Projections:

- For FY 2025-26 : 2%
- For Q3 FY 2025-26 : 0.6%
- For Q4 FY 2025-26 : 2.9%
- For Q1 of FY2026-27 : 3.9%
- For Q2 of FY2026-27 : 4%

GDP Growth Projections:

- For FY 2025-26 : 7.3%
- For Q3 FY 2025-26 : 7%
- For Q4 FY 2025-26 : 6.5%
- For Q1 FY 2026-27 : 6.7%
- For Q2 FY 2026-27 : 6.8%

Ques: What does the House Price Index (HPI) track in India?

भारत में हाउस प्राइस इंडेक्स (HPI) किसको ट्रैक करता है?

- A) Agricultural commodity prices / कृषि वस्तुओं की कीमतें
- B) Residential property prices / आवासीय संपत्ति की कीमतें
- C) Stock market trends / शेयर बाजार के रुझान
- D) Industrial production / औद्योगिक उत्पादन
- E) Inflation rate / मुद्रास्फीति दर

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The House Price Index (HPI), compiled quarterly by the Reserve Bank of India (RBI), tracks residential property prices using transaction-level data from registration authorities.
- हाउस प्राइस इंडेक्स (HPI), जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) तिमाही आधार पर तैयार करता है, आवासीय संपत्ति की कीमतों को रजिस्ट्रेशन अधिकारियों से प्राप्त लेन के स्तर देन-है। करता ट्रेक पर आधार के डेटा
- The new base year for HPI is 2022-23, replacing the earlier 2010-11 base.
- HPI का नया बेस वर्ष 2022-23 है, जो पहले 2010-11 के बेस को बदलता है।
- In Q2 FY26, All-India HPI grew 2.2% year-on-year, led by cities like Nagpur, Ghaziabad, and Chandigarh, while quarterly trend showed a 0.6% decline due to price drops in Kolkata, Chennai, Lucknow, and Hyderabad.
- Q2 FY26 में, ऑल इंडिया-HPI वर्ष वर्ष-दर-2.2% बढ़ा, प्रमुख रूप से नागपुर, गाजियाबाद और चंडीगढ़ द्वारा बढ़ावा मिला, जबकि तिमाही रुझान में कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ और हैदराबाद में कीमतों में गिरावट के कारण 0.6% की कमी दर्ज की गई।
- HPI covers 18 major cities across India, reflecting a mix of rising and falling property prices.
- HPI भारत के 18 प्रमुख शहरों को कवर करता है, जो संपत्ति की कीमतों में वृद्धि और गिरावट दोनों को दर्शाता है।

Ques: Which Payment Bank recently received RBI's in-principle approval to convert into a Small Finance Bank, becoming the first in India to do so?
कौन सा पेमेंट बैंक हाल ही में RBI से इन में बैंक वित्त छोटे कर प्राप्त अनुमोदन प्रिंसिपल-गया बन पहला में भारत लिए के होने परिवर्तित?

- A) Paytm Payments Bank / पेटीएम पेमेंट्स बैंक
- B) Airtel Payments Bank / एयरटेल पेमेंट्स बैंक
- C) India Post Payments Bank / इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
- D) Fino Payments Bank / फिनो पेमेंट्स बैंक
- E) Jio Payments Bank / जियो पेमेंट्स बैंक

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Reserve Bank of India (RBI) granted in-principle approval to Fino Payments Bank Limited (FPBL) to convert into a Small Finance Bank (SFB), making it the first payment bank in India to receive such approval.
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (FPBL) को छोटे वित्त बैंक (SFB) में बदलने के लिए इनदिया अनुमोदन प्रिंसिपल-, जिससे यह भारत का पहला ऐसा पेमेंट बैंक बन गया।
- FPBL was operationalized in 2017 and had applied for an SFB license in December 2023.
- FPBL का संचालन 2017 में शुरू हुआ और इसने दिसंबर 2023 में SFB लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।
- With this conversion, Fino will join the list of 11 existing SFBs including AU SFB, Equitas SFB, Suryoday SFB, Utkarsh SFB, Jana SFB, Unity SFB, Capital SFB, ESAF SFB, Ujjivan SFB, Shivalik SFB, and Slice SFB.
- इस परिवर्तन के बाद, फिनो उन 11 मौजूदा SFBs में शामिल होगा जिनमें AU SFB, Equitas SFB, Suryoday SFB, Utkarsh SFB, Jana SFB, Unity SFB, Capital SFB, ESAF SFB, Ujjivan SFB, Shivalik SFB और Slice SFB शामिल हैं।
- Eligibility: Existing payment banks controlled by residents and operating for at least 5 years can apply for conversion.
- पात्रता कम से कम और वाले नियंत्रण निवासी :5 साल से संचालित पेमेंट बैंक इस परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Requirements for SFBs:

- Maintain minimum net worth of ₹300 crore (or infuse additional capital to reach ₹300 crore within 18 months).
- Maintain a minimum Capital Adequacy Ratio of 15% of Risk Weighted Assets continuously.
- Promoters must hold at least 40% of paid-up voting equity for the first 5 years (reduce if initially above 40%).
- At least 25% of branches must be opened in unbanked rural centres.

SFB के लिए आवश्यकताएँ:

- न्यूनतम नेट वर्थ ₹300 करोड़ बनाए रखना या 18 महीने के भीतर पूंजी बढ़ाकर ₹300 करोड़ तक पहुँचाना।
- लगातार अपने जोखिम न्यूनतम का संपत्तियों भारत-15% कैपिटल अदेक्युअसी अनुपात बनाए रखना।
- पहले 5 वर्षों के लिए प्रमोटर्स के पास कम से कम 40% पेड होनी इक्विटी वोटिंग अप-

- में प्रारंभ यदि) चाहिए 40% से अधिक हो, तो इसे कम करना आवश्यक।)
- कम से कम 25% शाखाएँ बिना बैंकिंग वाले ग्रामीण केंद्रों में खोलना अनिवार्य है।

About Fino Payments Bank :

- Established : 2017
- HQ : Navi Mumbai
- MD & CEO : Rishi Gupta
- Tagline : Qadar Aapki Mehnat Ki

Ques: What is the objective of the 'FPO Shakti' initiative launched by Vrutti in partnership with HSBC India?

HSBC इंडिया के साथ साझेदारी में Vrutti द्वारा लॉन्च की गई 'FPO शक्ति' पहल का उद्देश्य क्या है?

- A) Promote urban startups / शहरी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना
- B) Support Farmer Producer Organisations (FPOs) with structured financing / किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को संरचित वित्तपोषण के माध्यम से समर्थन देना
- C) Provide insurance for small businesses / छोटे व्यवसायों के लिए बीमा प्रदान करना
- D) Fund renewable energy projects / नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करना
- E) Develop e-commerce platforms / ईकरना विकसित प्लेटफॉर्म कॉमर्स-

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- 'FPO Shakti' is a blended, stage-based financing model designed to help Farmer Producer Organisations (FPOs) access capital and strengthen their governance, market systems, financial discipline, and digital capabilities over a 24-month structured journey.
- 'FPO शक्ति' एक मिश्रित, चरण-आधारित वित्तपोषण आधारित-मॉडल है, जो किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को पूंजी तक पहुँचने में मदद करने और 24 महीने की संरचित यात्रा के दौरान उनके शासन, बाज़ार प्रणाली, वित्तीय अनुशासन और डिजिटल क्षमता को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- The initiative is supported by HSBC India and Friends of Women's World Banking (FWWB) India, targeting 15 early-growth FPOs initially, with plans to scale to over 100 organisations.
- इस पहल को HSBC इंडिया और Friends of Women's World Banking (FWWB) इंडिया द्वारा समर्थित किया गया है, जो प्रारंभ में 15 शुरुआती विकास वाले FPOs का समर्थन करेगी, और इसे 100 से अधिक संगठनों तक विस्तार करने की योजना है।
- India has over 44,000 registered FPOs, forming one of the world's largest networks of farmer-owned collectives.
- भारत में 44,000 से अधिक पंजीकृत FPOs हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े किसान स्वामित्व-हैं। बनाते एक से में नेटवर्क सामूहिक वाले

Ques: Which organisation has received SEBI's in-principle approval to register the Raajmarg Infra Investment Trust (RIIT) as an Infrastructure Investment Trust (InvIT)?

किस संगठन को राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) RIIT) को एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) के रूप में पंजीकृत करने के लिए SEBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है?

- A) NHAI / राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
- B) PGCIL / पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
- C) NTPC / एनटीपीसी
- D) IRCON / इरकॉन
- E) GAIL / गेल

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- The National Highways Authority of India (NHAI) received in-principle approval from the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to register the Raajmarg Infra Investment Trust (RIIT) as an Infrastructure Investment Trust (InvIT).
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड) SEBI) ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) NHAI) को राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) RIIT) को एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) InvIT) के रूप में पंजीकृत करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी।

- This approval was granted under the SEBI (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014.
- यह मंजूरी SEBI (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (विनियम, 2014 के तहत दी गई है।
- To receive the final approval, RIIT must fulfil several conditions over the next 6 months, including appointment of directors, submission of financial statements, and compliance with regulatory norms.
- अंतिम मंजूरी प्राप्त करने के लिए, RIIT को अगले 6 महीनों में कई शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे निदेशकों की नियुक्ति, वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना और नियामक नियमों का पालन करना।
- In November 2025, NHAi incorporated Raajmarg Infra Investment Managers Pvt. Ltd. (RIIMPL) as the Investment Manager for RIIT.
- नवंबर 2025 में, NHAi ने राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड) RIIMPL) को RIIT के निवेश प्रबंधक के रूप में शामिल किया।
- RIIMPL has been established as a collaborative venture with equity participation from major banks and financial institutions such as SBI, PNB, NaBFID, Axis Bank, Bajaj Finserv Ventures Ltd., HDFC Bank, ICICI Bank, IDBI Bank, IndusInd Bank, and Yes Bank.
- RIIMPL को प्रमुख बैंकों और वित्तीय संस्थानों जैसे SBI, PNB, NaBFID, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व वेंचर्स लिमिटेड, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, इंडसइंड बैंक और यस बैंक की इक्विटी भागीदारी के साथ एक सहयोगी उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है।

Ques: Which organisation invested USD 50 million in GFCL EV Products Limited to help set up India's first fully integrated battery materials manufacturing facility?

किस संगठन ने भारत की पहली पूर्णतः एकीकृत बैटरी सामग्री विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए GFCL EV प्रोडक्ट्स लिमिटेड में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया?

- A) Asian Development Bank / एशियाई विकास बैंक
- B) World Bank / विश्व बैंक
- C) International Finance Corporation (IFC) / अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम
- D) NITI Aayog / नीति आयोग
- E) KfW Development Bank / KfW विकास बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The International Finance Corporation (IFC) invested USD 50 million (approximately Rs 450 crore) in GFCL EV Products Limited through compulsorily convertible instruments.
- अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम) IFC) ने अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय साधनों के माध्यम से GFCL EV प्रोडक्ट्स लिमिटेड में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर) लगभग 450 करोड़ रुपये (का निवेश किया।
- The investment aims to establish India's first fully integrated battery materials manufacturing facility.
- यह निवेश भारत की पहली पूर्णतः एकीकृत बैटरी सामग्री विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है।
- The greenfield facility will focus on large-scale production of Lithium Hexafluorophosphate, electrolyte formulations, Lithium Iron Phosphate (LFP) cathode materials, and PVDF/PTFE binders used in electric vehicles and energy storage systems.
- यह ग्रीनफील्ड सुविधा लिथियम हेक्साफ्लोरोफॉस्फेट, इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म्युलेशन, लिथियम आयरन फॉस्फेट कैथोड सामग्री और पीवीडीएफ/पीटीएफई बाइंडर्स के बड़े पैमाने पर उत्पादन पर केंद्रित होगी, जिन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में उपयोग किया जाता है।
- Barclays served as the financial advisor to GFCL EV for this transaction.
- इस लेनदेन के लिए बार्कलेज ने GFCL EV के वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया।

About International Finance Corporation :

- Established : 1956
- HQ : Washington, D.C., United States
- Managing Director : Makhtar Diop

Ques: According to RBI guidelines, customer communication by Scheduled Commercial Banks (SCBs) must be provided in how many and which languages?

RBI दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों) SCBs) द्वारा ग्राहक संचार कितनी और किन भाषाओं में प्रदान किया जाना चाहिए?

- Two – English and Hindi / दो – अंग्रेज़ी और हिंदी
- Two – Regional language and English / दो – क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेज़ी
- Three – Hindi, English, and Regional language / तीन – हिंदी, अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय

भाषा

D) Four – Hindi, English, Sanskrit, and Regional language / चार – हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा

E) One – Only Regional language / एक – केवल क्षेत्रीय भाषा

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- RBI guidelines mandate that all customer communication by Scheduled Commercial Banks (SCBs) must be trilingual: Hindi, English, and the regional language.
- RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को ग्राहक संचार तीन भाषाओं में प्रदान करना अनिवार्य है :हिंदी, अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषा।
- Banks must adopt a Board-approved policy for branch management, ensuring customer-friendly services.
- बैंकों को शाखा प्रबंधन के लिए बोर्ड-अनुमोदित नीति अपनानी होती है ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।
- Banks must display indicator boards, provide service booklets, and ensure that forms, pay-in slips, and passbooks are available in Hindi, English, and the regional language.
- बैंकों को संकेतक बोर्ड प्रदर्शित करने, सेवा पुस्तिकाएं उपलब्ध कराने और सभी फॉर्म, पे-इन स्लिप्स, पासबुक आदि हिंदी, अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
- DFS instructed Public Sector Banks (PSBs) to strictly follow these regional language guidelines.
- DFS ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) को इन क्षेत्रीय भाषा दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है।
- Indian Banks' Association (IBA) advised PSBs to recruit Local Bank Officers (LBOs) to improve communication with customers, especially in rural and semi-urban areas.
- इंडियन बैंक्स' एसोसिएशन (IBA) ने PSBs को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों से बेहतर संवाद के लिए स्थानीय बैंक अधिकारियों (LBOs) की भर्ती करने की सलाह दी है।
- Customer Service Associates (CSAs) must pass a Local Language Proficiency Test (LPT) for the posting location.
- ग्राहक सेवा सहयोगियों (CSAs) को अपने कार्यस्थल की स्थानीय भाषा में दक्षता परीक्षा (LPT) उत्तीर्ण करनी होती है।
- Aim: seamless communication in regional languages and improved customer

experience.

- उद्देश्य : क्षेत्रीय भाषाओं में सुगम संचार और बेहतर ग्राहक सेवा।

Ques: Which bank has launched the premium 'Luxura' card powered by RuPay?

किस बैंक ने रूपे द्वारा संचालित प्रीमियम 'लक्जूरा' कार्ड लॉन्च किया है?

- A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- D) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- E) Canara Bank / केनरा बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Punjab National Bank (PNB) has launched a premium card named 'Luxura', powered by RuPay.
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने रूपे द्वारा संचालित एक प्रीमियम कार्ड 'लक्जूरा' लॉन्च किया है।
- The card is available for individuals aged between 21 and 70 years.
- यह कार्ड 21 से 70 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।
- For salaried persons, the income eligibility is ₹2.5 lakh per month and above.
- वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आय मानदंड प्रति माह ₹2.5 लाख या उससे अधिक है।
- For non-salaried individuals, the applicant must have a minimum annual income of ₹30 lakh.
- गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए न्यूनतम वार्षिक आय ₹30 लाख होनी चाहिए।

About Punjab National Bank :

- Established : 19 May 1894
- HQ : New Delhi
- MD & CEO : Ashok Chandra
- Tagline : The Name You Can Bank Upon

Ques: What is the primary aim of SEBI's newly launched Past Risk and Return Verification Agency (PaRRVA)?

SEBI द्वारा शुरू की गई Past Risk and Return Verification Agency (PaRRVA) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) To regulate mutual fund NAV calculations / म्यूचुअल फंड NAV गणना को नियंत्रित करना
- B) To prevent misleading claims about past performance in financial product advertisements / वित्तीय उत्पादों के विज्ञापनों में पिछले प्रदर्शन से जुड़े भ्रामक दावों को रोकना
- C) To monitor insider trading cases / इनसाइडर ट्रेडिंग मामलों की निगरानी करना
- D) To create a central registry for investment advisors / निवेश सलाहकारों के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री बनाना
- E) To certify financial influencers / वित्तीय इन्फ्लुएंसर्स को प्रमाणित करना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Securities and Exchange Board of India (SEBI) launched the Past Risk and Return Verification Agency (PaRRVA) to prevent misleading claims related to past performance made by Research Analysts, Investment Advisors, and stock brokers in financial product advertisements.
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने Past Risk and Return Verification Agency (PaRRVA) की शुरुआत की ताकि वित्तीय उत्पादों के विज्ञापनों में रिसर्च एनालिस्ट, निवेश सलाहकार और स्टॉक ब्रोकरों द्वारा किए जाने वाले पिछले प्रदर्शन से जुड़े भ्रामक दावों को रोका जा सके।
- This is the world's first initiative of its kind, launched in partnership with the National Stock Exchange (NSE) and CARE Edge Ratings.
- यह विश्व का पहला ऐसा प्रयास है, जिसे राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और CARE Edge Ratings के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है।
- Intermediaries submit data through secure API or file upload, which is validated by the PaRRVA–NSE Data Centre (PDC). The system generates 50+ risk–return metrics with T+1 portfolio checks.
- मध्यस्थ सुरक्षित API या फ़ाइल अपलोड के माध्यम से जानकारी जमा करते हैं, जिसे PaRRVA–NSE डेटा सेंटर (PDC) द्वारा सत्यापित किया जाता है। यह प्रणाली T+1

पोर्टफोलियो जांच के साथ 50 से अधिक जोखिम-प्रतिफल मीट्रिक तैयार करती है।

- Earlier, SEBI's rules restricted registered intermediaries from showing their past performance, even if legitimate, while unregistered players freely advertised unverifiable returns — creating a regulatory imbalance.
- पहले, SEBI के नियम पंजीकृत मध्यस्थों को अपने पिछले प्रदर्शन दिखाने से रोकते थे, जबकि गैर-पंजीकृत खिलाड़ी अप्रमाणित रिटर्न का प्रचार कर निवेशकों को आकर्षित करते थे, जिससे नियामकीय असंतुलन पैदा होता था।
- PaRRVA was initially announced in December 2024 during SEBI's 208th Board Meeting and the operational framework was officially issued in April 2025.
- PaRRVA की घोषणा पहली बार दिसंबर 2024 में SEBI की 208वीं बोर्ड बैठक में की गई थी, और इसका परिचालन ढांचा अप्रैल 2025 में जारी किया गया।
- As per SEBI's circular, a Credit Rating Agency (CRA) with at least 15 years of experience, ₹100 crore net worth, grievance redressal mechanisms (including ODR), and 250+ rated issuers can act as PaRRVA.
- SEBI के परिपत्र के अनुसार, 15 वर्षों का अनुभव, ₹100 करोड़ की शुद्ध संपत्ति, शिकायत निवारण तंत्र) ODR सहित(, और 250+ रेटेड इश्यूअर्स वाले क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) CRA) को PaRRVA के रूप में मान्यता दी जा सकती है।
- A recognised Stock Exchange with at least 15 years of experience, ₹200 crore net worth, nationwide terminals, and grievance redressal mechanisms (including ODR) can act as PaRRVA Data Centre (PDC).
- कम से कम 15 वर्षों के अनुभव, ₹200 करोड़ की शुद्ध संपत्ति, देशभर में टर्मिनल, और शिकायत निवारण तंत्र) ODR सहित (वाली मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को PaRRVA डेटा सेंटर) PDC) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

Ques: According to the ACI Worldwide 'Prime Time for Real-Time 2024' report, what share does UPI hold in global real-time payment transactions? ACI Worldwide की 'Prime Time for Real-Time 2024' रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक रियल में लेनदेन पेमेंट टाइम-UPI की हिस्सेदारी कितनी है?

- A) 35%
- B) 49%
- C) 28%
- D) 56%
- E) 40%

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The International Monetary Fund (IMF), in its June 2025 report, recognised India's Unified Payments Interface (UPI) as the world's largest real-time retail fast-payment system by transaction volume.
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी जून 2025 की रिपोर्ट में UPI को लेनदेन की मात्रा के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा रियलमाना सिस्टम पेमेंट-फास्ट रिटेल टाइम-
- According to ACI Worldwide's 'Prime Time for Real-Time 2024' report, UPI accounts for 49% of global real-time payment transactions.
- ACI Worldwide की 'Prime Time for Real-Time 2024' रिपोर्ट के अनुसार, UPI वैश्विक रियल का लेनदेन पेमेंट टाइम-49% हिस्सा रखता है।
- India recorded 129.3 billion real-time transactions, the highest in the world, far ahead of countries like Brazil, Thailand, China and South Korea.
- भारत ने 129.3 बिलियन रियलकिए दर्ज लेनदेन टाइम-, जो ब्राज़ील, थाईलैंड, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से कहीं अधिक हैं।
- Government, RBI and NPCI initiatives such as BHIM-UPI incentives and Payment Infrastructure Development Fund (PIDF) support helped small merchants rapidly adopt digital payments.
- सरकार, RBI और NPCI की BHIM-UPI इंसेंटिव और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) जैसी पहलों ने छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने में मदद की।
- As of 31 October 2025, 5.45 crore digital touchpoints and 56.86 crore QR codes were deployed across around 6.5 crore merchants nationwide.
- 31 अक्टूबर 2025 तक, देशभर में लगभग 6.5 करोड़ व्यापारियों के लिए 5.45 करोड़ डिजिटल टचपॉइंट और 56.86 करोड़ QR कोड तैनात किए गए थे।

Genius

Ques: Which company will acquire Rivpe Technology for ₹22 crore, resulting in 100% ownership on a fully diluted basis?

कौन कंपनी सी-₹22 करोड़ में Rivpe Technology का अधिग्रहण करेगी, जिससे पूर्ण रूप से डायल्यूटेड आधार पर 100% स्वामित्व प्राप्त होगा?

- A) Paytm / पेटीएम
- B) PhonePe / फोनपे
- C) Zaggie Prepaid Ocean Services / जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज
- D) Razorpay / रेज़रपे

E) BharatPe / भारतपे

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Zaggle Prepaid Ocean Services has announced the acquisition of Rivpe Technology for ₹22 crore.
 - जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज ने ₹22 करोड़ में Rivpe Technology के अधिग्रहण की घोषणा की है।
 - The acquisition includes 81,429 equity shares and 16,407 Compulsory Convertible Preference Shares (CCPS), resulting in 100% ownership on a fully diluted basis.
 - इस अधिग्रहण में 81,429 इक्विटी शेयर और 16,407 अनिवार्य परिवर्तनीय वरीयता शेयर (CCPS) शामिल हैं, जिससे पूर्ण डायल्यूटेड आधार पर 100% स्वामित्व प्राप्त होगा।
 - The deal is expected to be completed within 120 days.
 - यह सौदा 120 दिनों के भीतर पूरा होने की संभावना है।
 - In addition to the acquisition, Zaggle will invest ₹75 crore in Rio.Money, the consumer payments brand of Rivpe.
 - अधिग्रहण के अलावा, जैगल Rivpe के कंज्यूमर पेमेंट ब्रांड Rio.Money में ₹75 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करेगा।
 - The investment will be used for product enhancement, technology upgrades, go-to-market initiatives, and expansion of consumer payment offerings.
 - इस निवेश का उपयोग उत्पाद सुधार, तकनीकी उन्नयन, गो और रणनीतियों मार्केट-टू-जाएगा। किया लिए के विस्तार के सेवाओं भुगतान उपभोक्ता
 - The total financial commitment by Zaggle amounts to ₹97 crore, comprising ₹22 crore for the acquisition and ₹75 crore for Rio.Money's expansion.
 - जैगल की कुल वित्तीय प्रतिबद्धता ₹97 करोड़ है, जिसमें ₹22 करोड़ अधिग्रहण और ₹75 करोड़ Rio.Money के विस्तार के लिए शामिल हैं।
-

Ques: AU Small Finance Bank has received approval to increase its foreign investment limit up to what level?

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को विदेशी निवेश सीमा बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी मिली है?

- A) 51%
- B) 60%

- C) 65%
- D) 70%
- E) 74%

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- AU Small Finance Bank has received approval from the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance.
 - एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) से मंजूरी प्राप्त हुई है।
 - The approval allows the bank to increase its foreign investment limit from 49% to 74% of its paid-up capital.
 - इस मंजूरी के तहत बैंक की चुकता पूंजी में विदेशी निवेश सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है।
 - The 74% cap is the maximum permissible foreign investment limit for private sector banks in India.
 - 74% की सीमा भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए अधिकतम अनुमेय विदेशी निवेश सीमा है।
 - The move is expected to enhance capital availability, attract global investors and support the bank's growth plans.
 - इस कदम से पूंजी उपलब्धता बढ़ेगी, वैश्विक निवेशकों की भागीदारी बढ़ेगी और बैंक की विकास योजनाओं को समर्थन मिलेगा।
 - The approval is subject to compliance with RBI guidelines and applicable regulatory norms.
 - यह मंजूरी RBI के दिशानिर्देशों और लागू नियामकीय नियमों के पालन के अधीन है।
-

Ques: Why did Airpay recently receive approval from the Reserve Bank of India (RBI)?

एयरपे को हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मंजूरी क्यों मिली है?

- A) To launch a digital bank / डिजिटल बैंक शुरू करने के लिए
- B) To operate as a cross-border payment aggregator / सीमा के एग्रीगेटर पेमेंट पार-लिए के करने कार्य में रूप

- C) To issue credit cards / क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए
D) To manage government subsidies / सरकारी सब्सिडी प्रबंधन के लिए
E) To provide cryptocurrency services / क्रिप्टोकॉरेन्सी सेवाएँ देने के लिए

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Airpay Payment Services has received RBI approval to operate as a cross-border payment aggregator.
- एयरपे पेमेंट सर्विसेज को सीमा लिए के करने कार्य में रूप के एग्रीगेटर पेमेंट पार-RBI की मंजूरी मिली है।
- With this approval, Airpay has completed all required authorisations under the unified payment aggregator framework.
- इस मंजूरी के साथ, एयरपे ने यूनिफाइड पेमेंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ पूरी कर ली हैं।
- Airpay is now licensed to operate as a payment aggregator across online, physical and cross-border payment categories.
- अब एयरपे ऑनलाइन, फिजिकल और क्रॉस में रूप के एग्रीगेटर पेमेंट में श्रेणियों सभी बॉर्डर-सकेगा। कर कार्य
- The approval strengthens India's regulated fintech ecosystem and enables smoother international digital transactions.
- यह मंजूरी भारत के विनियमित फिनटेक इकोसिस्टम को मज़बूत बनाती है और अंतरराष्ट्रीय डिजिटल भुगतानों को आसान बनाती है।
- RBI's payment aggregator framework ensures compliance, transparency and consumer protection in digital payments.
- RBI का पेमेंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क डिजिटल भुगतानों में अनुपालन, पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

Ques: Which bank launched the FIRST WOW! Black Credit Card backed by Fixed Deposit?

किस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से समर्थित FIRST WOW! ब्लैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया?

A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक

- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C) IDFC First Bank / आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
- D) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- E) SBI Card / एसबीआई कार्ड

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- IDFC First Bank Limited launched the FIRST WOW! Black Credit Card, a premium credit card backed by a Fixed Deposit (FD).
- आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड ने FIRST WOW! ब्लैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) से समर्थित एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है।
- The card offers 0% forex (FX) markup, making it attractive for international travellers and cross-border online shoppers.
- इस कार्ड में 0% विदेशी मुद्रा (FX) मार्कअप की सुविधा है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और क्रॉसहै। बनाता आकर्षक लिए के खरीदारों ऑनलाइन बॉर्डर-
- Eligibility: Available to individuals aged 18 years and above, against a Fixed Deposit starting at Rs 20,000.
- पात्रता कार्ड यह :18 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, जिनके पास कम से कम ₹20,000 का फिक्स्ड डिपॉजिट हो।

About IDFC First Bank :

- Established : 2015
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : V Vaidyanathan
- Tagline : Always You First

Ques: Which banks have received RBI approval to set up the Indian Digital Payment Intelligence Corporation (IDPIC)?

भारतीय डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन (IDPIC) की स्थापना के लिए RBI की मंजूरी किन बैंकों को मिली है?

- A) SBI and PNB / एसबीआई और पीएनबी
- B) Bank of Baroda and Canara Bank / बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक

- C) SBI and Bank of Baroda / एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा
D) Union Bank and Bank of India / यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया
E) SBI and HDFC Bank / एसबीआई और एचडीएफसी बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The State Bank of India (SBI) and Bank of Baroda (BoB) have received approval from the Reserve Bank of India (RBI).
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से मंजूरी मिली है।
- The approval is for setting up a dedicated Digital Payments Intelligence Platform.
- यह मंजूरी एक समर्पित डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए दी गई है।
- The new entity will be named the Indian Digital Payment Intelligence Corporation (IDPIC).
- इस नई संस्था का नाम भारतीय डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन (IDPIC) होगा।
- IDPIC aims to strengthen fraud detection and prevention across public sector banks.
- IDPIC का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी की पहचान और रोकथाम को मजबूत करना है।
- The proposed IDPIC will be incorporated as a Section 8 company under the Companies Act, 2013.
- प्रस्तावित IDPIC को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सेक्शन 8 कंपनी (लाभकारी-गैर) पंज में रूप के (संस्थाीकृत किया जाएगा।
- RBI approval is subject to an exemption granted by the Department of Financial Services, Ministry of Finance.
- RBI की मंजूरी वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा दी गई छूट पर निर्भर है।
- The exemption allows the banks to hold more than 30% of the paid-up share capital in the company till 16 October 2026, under Section 19(2) of the Banking Regulation Act, 1949.
- यह छूट बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के तहत बैंकों को 16 अक्टूबर 2026 तक कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का 30% से अधिक हिस्सा रखने की अनुमति देती है।

About Bank of Baroda :

- Established : 1908
 - HQ : Vadodara, Gujarat
 - MD & CEO : Debadatta Chand
 - Tagline : India's International Bank
-

Ques : What is ADB's revised GDP growth forecast for India for FY26?
FY26 के लिए ADB द्वारा भारत की संशोधित GDP वृद्धि दर कितनी है?

- A) 6.5%
- B) 6.8%
- C) 7.0%
- D) 7.2%
- E) 7.5%

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The Asian Development Bank (ADB) has raised India's GDP growth forecast for FY26 from 6.5% to 7.2%.
- एशियाई विकास बैंक (ADB) ने FY26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है।
- The upward revision of 0.7 percentage points is mainly driven by strong domestic consumption supported by recent tax cuts.
- 0.7 प्रतिशत अंक का यह उन्नयन हालिया कर कटौती से समर्थित मजबूत घरेलू उपभोग के कारण किया गया है।
- Stronger Q2 expansion reflected improving economic momentum in India, and the revision will also support Asia's overall growth, now projected at 5.1% for 2025.
- दूसरी तिमाही (Q2) में मजबूत विस्तार भारत की बेहतर आर्थिक गति को दर्शाता है, और इस संशोधन से एशिया की समग्र वृद्धि दर को भी बल मिलेगा, जिसे 2025 के लिए 5.1% अनुमानित किया गया है।
- The forecast was published in ADB's Asian Development Outlook, December 2025 edition.

- यह अनुमान ADB की Asian Development Outlook, दिसंबर 2025 रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है।

Ques: According to the World Bank International Debt Report 2024, what was the debt situation of developing countries between 2022–2024?

वर्ल्ड बैंक के अंतरराष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 के अनुसार, 2022–2024 के बीच विकासशील देशों की ऋण स्थिति क्या थी?

- A) Developing countries received more financing than debt service payments / विकासशील देशों ने ऋण सेवा भुगतानों से अधिक वित्तपोषण प्राप्त किया
- B) Developing countries' debt service payments exceeded new financing by \$741 billion / विकासशील देशों के ऋण सेवा भुगतान नई वित्त पोषण से \$741 बिलियन अधिक थे
- C) Debt gap was the lowest in 50 years / 50 वर्षों में ऋण अंतर सबसे कम था
- D) Interest rates fell to pre-2020 levels / ब्याज दरें 2020 से पहले के स्तर पर गिर गईं
- E) Bond markets were closed entirely / बॉन्ड बाजार पूरी तरह बंद थे

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Developing countries paid \$741 billion more in debt service than they received in new financing between 2022–2024, marking the largest gap in 50 years.
- विकासशील देशों ने 2022–2024 के बीच नई वित्तपोषण की तुलना में \$741 बिलियन अधिक ऋण सेवा भुगतान किए, जो पिछले 50 वर्षों का सबसे बड़ा अंतर है।
- Despite high debt service, temporary relief came as interest rates peaked and bond markets reopened; \$90 billion of debt was restructured in 2024, the highest since 2010.
- उच्च ऋण सेवा के बावजूद, ब्याज दरें चरम पर पहुंचने और बॉन्ड बाजार के फिर से खुलने से अस्थायी राहत मिली; 2024 में \$90 बिलियन का ऋण पुनर्गठित किया गया, जो 2010 के बाद सबसे अधिक है।
- Bond investors provided \$80 billion in net financing, enabling new bond issuances but at high interest (~10%), double pre-2020 levels.
- बॉन्ड निवेशकों ने \$80 बिलियन शुद्ध वित्तपोषण प्रदान किया, जिससे नए बॉन्ड जारी किए

गए लेकिन उच्च ब्याज)~10%) पर, जो 2020 से पहले के स्तर का दोगुना है।

- External debt of low- and middle-income countries reached \$8.9 trillion in 2024; IDA-eligible countries owe \$1.2 trillion (record).
- 2024 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों का बाहरी ऋण \$8.9 ट्रिलियन पहुंच गया; IDA-योग्य देशों का ऋण \$1.2 ट्रिलियन है। (रिकॉर्ड)
- Developing nations paid \$415 billion in interest alone, diverting funds from health, education, and infrastructure; in highly indebted countries, 1 in 2 people cannot afford a minimum daily diet.
- विकासशील देशों ने केवल ब्याज पर \$415 बिलियन का भुगतान किया, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए धन हटा लिया गया; अत्यधिक ऋणी देशों में हर दो में एक व्यक्ति न्यूनतम दैनिक आहार भी नहीं खरीद सकता।
- Financing sources shifted: World Bank remained the largest low-cost financier, providing \$18.3 billion net financing + \$7.5 billion in grants in 2024.
- वित्तपोषण स्रोतों में बदलावरहा बना वित्तपोषक वाला लागत कम बड़ा सबसे बैंक वर्ल्ड :, 2024 में \$18.3 बिलियन शुद्ध वित्तपोषण +\$7.5 बिलियन अनुदान प्रदान किए।
- Bilateral creditors withdrew funds (\$8.8 billion net repayments) instead of providing new loans; domestic debt grew faster than external debt in 86 countries.
- द्विपक्षीय ऋणदाता ने नई ऋण देने के बजाय \$8.8 बिलियन शुद्ध प्रतिपूर्ति ली; 86 देशों में घरेलू ऋण बाहरी ऋण की तुलना में तेजी से बढ़ा।

Ques : As per RBI data, how much loan amount has been written off by PSBs during the last five financial years and the current year till September 30, 2025?

RBI के अनुसार, पिछले पाँच वित्तीय वर्षों और 30 सितंबर 2025 तक चालू वर्ष में PSBs द्वारा कितना ऋण राइटहै गया किया ऑफ-?

- A) ₹3,25,000 crore
- B) ₹4,80,000 crore
- C) ₹5,10,000 crore
- D) ₹6,15,647 crore
- E) ₹7,00,000 crore

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- RBI data shows that Public Sector Banks (PSBs) have written off loans worth ₹6,15,647 crore over the last five financial years and the current year up to September 30, 2025.
- RBI डेटा के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने पिछले पाँच वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष (30 सितंबर 2025 तक) में कुल ₹6,15,647 करोड़ के ऋण राइट हैं किए ऑफ-
- Loan write-off is an accounting exercise to clean bank balance sheets and does not imply waiver of loans; banks continue recovery efforts even after write-off.
- ऋण राइट है प्रक्रिया लेखांकन एक ऑफ, जिससे बैंक की बैलेंस शीट साफ की जाती है; इसका मतलब ऋण माफी नहीं होता। राइट प्रक्रिया की वसूली ऋण बैंक भी बाद के ऑफ हैं। रखते जारी
- Large write-offs are mainly related to stressed assets and non-performing assets (NPAs).
- बड़े राइट परिसंप तनावग्रस्त से रूप मुख्य ऑफ-तियों और एनपीए (Non-Performing Assets) से संबंधित होते हैं।

Ques : How much funding has the World Bank approved to promote clean air in Uttar Pradesh and Haryana?

उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्वच्छ वायु को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने कितनी राशि मंजूर की है?

- A) \$400 million
- B) \$500 million
- C) \$600 million
- D) \$700 million
- E) \$800 million

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The World Bank has approved \$600 million financing for two clean air programmes in Uttar Pradesh and Haryana.
- विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दो स्वच्छ वायु कार्यक्रमों के लिए कुल \$600 मिलियन का वित्तपोषण स्वीकृत किया है।

- The Uttar Pradesh Clean Air Management Programme (UPCAMP) will receive \$299.66 million to strengthen the state's Clean Air Plan through investments in transport, agriculture, and industrial sectors.
- उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम (UPCAMP) को \$299.66 मिलियन दिए जाएंगे, जिससे परिवहन, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से राज्य की क्लीन एयर योजना को मजबूत किया जाएगा।
- The Haryana Clean Air Project for Sustainable Development Operation will receive \$300 million and focuses on reducing air pollution through multi-sectoral interventions.
- हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑपरेशन को \$300 मिलियन मिलेंगे, जो बहुहै। केंद्रित पर करने कम प्रदूषण वायु से माध्यम के हस्तक्षेपों क्षेत्रीय-

Ques: What is the main objective of the nationwide campaign “Aapki Poonji, Aapka Adhikar – Your Money, Your Right” launched by the Government of India?

“आपकी पूंजी, आपका अधिकार – योर मनी, योर राइट” अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- A) Promoting digital payments / डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना
- B) Recovery of unclaimed financial assets / बिना दावे की वित्तीय परिसंपत्तियों की वापसी
- C) Financial literacy for students / छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता
- D) Tax compliance awareness / कर अनुपालन जागरूकता
- E) Expansion of banking services / बैंकिंग सेवाओं का विस्तार

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Ministry of Finance, Government of India conducted the nationwide campaign “Aapki Poonji, Aapka Adhikar – Your Money, Your Right” as a three-month drive from 4 October to 5 December 2025.
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने “आपकी पूंजी, आपका अधिकार – योर मनी, योर राइट” अभियान 4 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक तीन महीने के राष्ट्रीय अभियान के रूप में चलाया।
- The campaign aims to facilitate the settlement and recovery of unclaimed

financial assets such as bank deposits, insurance claims, dividends, shares, mutual funds and pension amounts.

- इस अभियान का उद्देश्य बैंक जमा, बीमा राशि, डिविडेंड, शेयर, म्यूचुअल फंड और पेंशन जैसी बिना दावे की वित्तीय परिसंपत्तियों की वापसी सुनिश्चित करना है।
- The initiative follows the 3A Framework — Awareness, Accessibility and Action.
- यह पहल 3A फ्रेमवर्क — जागरूकता, सुलभता और कार्रवाई — पर आधारित है।
- Key regulators involved include RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA and IEPFA.
- इसमें RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA और IEPFA जैसे प्रमुख नियामक शामिल हैं।
- District-level camps were organised in 477 districts across India during the campaign period.
- अभियान अवधि के दौरान देश के 477 जिलों में जिलागए। किए आयोजित शिविर स्तरीय-
- Digital platforms such as Unclaimed Deposits – Gateway to Access inforMation (UDGAM), Bima Bharosa and Mutual Fund Investment Tracing and Retrieval Assistant (MITRA) were used to trace and claim unclaimed assets.
- बिना दावे की परिसंपत्तियों की खोज और दावा करने के लिए UDGAM, बीमा भरोसा और MITRA जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया।
- In the first two months alone, nearly ₹2,000 crore of unclaimed funds were successfully reclaimed by rightful owners.
- केवल पहले दो महीनों में ही लगभग ₹2,000 करोड़ की बिना दावे की राशि सही मालिकों को वापस दिलाई गई।

Ques: Which company has launched the Wise Travel Card in India for multi-currency international travel?

भारत में बहु यात्रा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा-के लिए Wise Travel Card किस कंपनी ने लॉन्च किया है?

- A) PayPal / पेपाल
- B) Wise / वाइज
- C) Revolut / रेवोल्यूट
- D) Mastercard / मास्टरकार्ड
- E) Visa / वीज़ा

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Wise, a global money movement company, has launched its multi-currency Wise Travel Card in India.
- वैश्विक मनी मूवमेंट कंपनी Wise ने भारत में अपना मल्टी करेंसी-Wise Travel Card लॉन्च किया है।
- The card targets international travellers seeking transparent pricing and ease of use abroad.
- यह कार्ड पारदर्शी मूल्य निर्धारण और विदेश में आसान उपयोग चाहने वाले यात्रियों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है।
- The launch was initially announced at the Global Fintech Festival (GFF) 2025.
- इसकी घोषणा सबसे पहले ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल (GFF) 2025 में की गई थी।
- GFF 2025 was held in Mumbai, Maharashtra.
- GFF 2025 का आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया था।
- The Wise Travel Card supports over 40 currencies, including Vietnam, Indonesia, Turkey and Georgia.
- Wise Travel Card 40 से अधिक मुद्राओं को सपोर्ट करता है, जिनमें वियतनाम, इंडोनेशिया, तुर्की और जॉर्जिया शामिल हैं।
- The card is accepted on the Visa Network in more than 160 countries worldwide.
- यह कार्ड वीज़ा नेटवर्क पर 160 से अधिक देशों में स्वीकार्य है।
- It offers free ATM withdrawals up to USD 200 per month, after which standard charges apply.
- इसमें प्रति माह USD 200 तक निःशुल्क ATM निकासी की सुविधा है, इसके बाद मानक शुल्क लागू होंगे।

Ques: On which bank did the Reserve Bank of India impose a penalty of ₹99.30 lakh for regulatory non-compliance?

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नियामकीय उल्लंघन के लिए ₹99.30 लाख का जुर्माना किस बैंक पर लगाया?

- A) Punjab & Sind Bank / पंजाब एंड सिंध बैंक
- B) Jammu and Kashmir Bank Limited / जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड
- C) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- D) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- E) Central Bank of India / सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India imposed a monetary penalty of ₹99.30 lakh on Jammu and Kashmir Bank Limited.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड पर ₹99.30 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
- The penalty was imposed for contravention of Section 26A of the Banking Regulation Act, 1949.
- यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26A के उल्लंघन के लिए लगाया गया।
- The bank was also found non-compliant with RBI directions on the Internal Ombudsman Scheme, 2018.
- बैंक ने आंतरिक लोकपाल योजना, 2018 से संबंधित RBI के निर्देशों का पालन नहीं किया।
- Additional non-compliance was observed in Customer Service norms and Know Your Customer (KYC) guidelines.
- ग्राहक सेवा मानदंडों और 'अपने ग्राहक को जानें' (KYC) दिशानिर्देशों के पालन में भी कमी पाई गई।
- The penalty highlights RBI's focus on strengthening regulatory compliance and consumer protection in the banking sector.
- यह कार्रवाई बैंकिंग क्षेत्र में नियामकीय अनुपालन और उपभोक्ता संरक्षण को मज़बूत करने पर RBI के ज़ोर को दर्शाती है।

Ques: Which company has received a ₹12,000 crore loan from SBI and Bank of Baroda to fund its Dahej plant in Gujarat?

गुजरात के दहेज संयंत्र के लिए SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा से ₹12,000 करोड़ का ऋण किस कंपनी को मिला है?

- A) GAIL (India) Limited / गेल लिमिटेड (इंडिया)
- B) ONGC / ओएनजीसी
- C) Indian Oil Corporation / इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन
- D) Petronet LNG Limited / पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड
- E) Bharat Petroleum Corporation Limited / भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Petronet LNG Limited has received a loan of ₹12,000 crore. The loan has been extended jointly by State Bank of India (SBI) and Bank of Baroda.
 - पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड को ₹12,000 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ है। यह ऋण भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया है।
 - The funding will be used for the company's Dahej LNG plant in Gujarat.
 - इस धनराशि का उपयोग गुजरात स्थित दहेज एलएनजी संयंत्र के लिए किया जाएगा।
 - Petronet LNG is India's largest liquefied natural gas (LNG) importer.
 - पेट्रोनेट एलएनजी भारत का सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) आयातक है।
 - The company is a joint venture of GAIL, ONGC, Indian Oil and Bharat Petroleum Corporation.
 - यह कंपनी GAIL, ONGC, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का संयुक्त उपक्रम है।
 - Each of these four public sector companies holds a 12.5% stake in Petronet LNG.
 - इन चारों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की पेट्रोनेट एलएनजी में 12.5% हिस्सेदारी है।
-

Ques: Which companies have partnered to offer insurance products to housing loan customers across 17 states and 340 districts in India?

भारत में 17 राज्यों और 340 जिलों में हाउसिंग लोन ग्राहकों को बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए कौन सी कंपनियों ने साझेदारी की है?

- A) HDFC Ergo and LIC / HDFC एर्गो और LIC
- B) ICICI Lombard and Vastu Housing Finance / ICICI लोम्बार्ड और वास्तु हाउसिंग फाइनेंस
- C) Bajaj Allianz and PNB Housing / बजाज एलियांज और PNB हाउसिंग
- D) SBI General Insurance and L&T Finance / SBI जनरल इंश्योरेंस और L&T फाइनेंस
- E) Tata AIG and Indiabulls / टाटा AIG और इंडियाबुल्स

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- ICICI Lombard General Insurance has partnered with Vastu Housing Finance to offer insurance to Vastu's housing loan customers.
- ICICI लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस ने वासु हाउसिंग फाइनेंस के हाउसिंग लोन ग्राहकों को बीमा प्रदान करने के लिए साझेदारी की है।
- The insurance coverage spans 17 states and 340 districts in India.
- बीमा कवरेज भारत के 17 राज्यों और 340 जिलों में उपलब्ध है।

• Key insurance products offered:

- Income Protect: Covers 33 critical illnesses, accidental death, and permanent total disability.
- इनकम प्रोटेक्ट :33 गंभीर बीमारियों, आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता को कवर करता है।
- Home Insurance: Protects homes against fire, natural calamities, theft, and accidental damage.
- होम इश्योरेंसआग को घर ;, प्राकृतिक आपदाओं, चोरी और आकस्मिक क्षति से सुरक्षा प्रदान करता है।
- Target segment includes peri-urban and rural borrowers, many of whom are first-generation homeowners and self-employed.
- लक्षित वर्ग में उपहैं शामिल उधारकर्ता ग्रामीण और शहरी-, जिनमें से कई प्रथम पीढ़ी के गृहस्वामी और स्वरोजगार वाले हैं।
- Distribution is through Vastu's branch network and digital platforms.
- उत्पाद वासु की शाखा नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरित किए जाते हैं।
- Technology features include instant policy issuance via API integration and cashless claims within 60 minutes via IL TakeCare app.
- तकनीकी सुविधाओं में API इंटीग्रेशन के माध्यम से तुरंत पॉलिसी जारी करना और IL TakeCare ऐप के जरिए 60 मिनट में कैशलेस क्लेम शामिल हैं।

Ques: What has the RBI directed banks to do regarding core and non-core business risks?

RBI ने बैंक से कोर और गैर के जोखिमों के व्यवसाय कोर-संबंध में क्या करने को कहा है?

A) Merge all lending entities / सभी लेंडिंग संस्थाओं को मिलाना

- B) Submit a plan to ringfence core business from riskier non-core business / कोर व्यवसाय को जोखिम भरे गैरकरना प्रस्तुत योजना का रखने अलग से व्यवसाय कोर-
- C) Stop overseas operations / विदेशी संचालन बंद करना
- D) Seek prior approval for all non-financial holdings / सभी गैर के होल्डिंग वित्तीय-लेना अनुमोदन पूर्व लिए
- E) Limit board approvals to one entity / बोर्ड अनुमोदन को एक संस्था तक सीमित करना

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- RBI has asked banks to submit a plan to ringfence core business from riskier non-core business by March 2026.
- RBI ने बैंक से मार्च 2026 तक कोर व्यवसाय को जोखिम भरे गैर अलग से व्यवसाय कोर- है। कहा को करने प्रस्तुत योजना का रखने
- Banks may have multiple lending entities but must obtain board approval.
- बैंक के पास कई लेंडिंग संस्थाएँ हो सकती हैं, लेकिन बोर्ड से अनुमोदन आवश्यक है।
- The new rules are to be implemented by March 31, 2028.
- नए नियम 31 मार्च 2028 तक लागू किए जाएंगे।
- This revises the October 2024 guidelines, which allowed only one entity per bank group for similar business.
- यह अक्टूबर 2024 के दिशानिर्देशों में संशोधन है, जो समान व्यवसाय के लिए प्रत्येक बैंक समूह में केवल एक संस्था की अनुमति देते थे।
- The change provides relief to banks, especially private banks with lending subsidiaries like HDFC Bank and Axis Bank.
- यह बदलाव बैंक, विशेषकर HDFC बैंक और Axis बैंक जैसी लेंडिंग सहायक कंपनियों वाले निजी बैंकों के लिए राहत प्रदान करता है।
- For overseas operations, banks require an NOC from RBI for branches engaging in activities not permitted for the parent bank.
- विदेशी संचालन के लिए, उन शाखाओं को जो मूल बैंक के लिए अनुमत गतिविधियों में संलग्न नहीं हैं, RBI से NOC लेना आवश्यक है।
- RBI has relaxed rules for non-financial holding companies in businesses like mutual funds, insurance, pension fund management, investment advisory, and broking.
- RBI ने म्यूचुअल फंड, बीमा, पेंशन फंड प्रबंधन, निवेश परामर्श और ब्रोकिंग जैसे व्यवसायों में गैरनि लिए के कंपनियों होल्डिंग वित्तीय-यमों में ढील दी है।

- Now, non-financial holding companies can inform RBI within 15 days after board approval instead of seeking prior approval.
- अब गैर के अनुमोदन बोर्ड कंपनियां होल्डिंग वित्तीय-15 दिनों के भीतर RBI को सूचना दे सकती हैं, पहले की तरह पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

Ques: What change has the Reserve Bank of India (RBI) introduced regarding cash credit, current and overdraft accounts?

नकद ऋण (क्रेडिट कैश), करंट और ओवरड्राफ्ट खातों से संबंधित नियमों में RBI ने क्या बदलाव किया है?

- A) Complete ban on current accounts / करंट खातों पर पूर्ण प्रतिबंध
- B) Only one bank can maintain OD accounts / केवल एक बैंक OD खाते रख सकता है
- C) Easing of norms for opening and maintenance of CC, current and OD accounts / कैश क्रेडिट, करंट और ओवरड्राफ्ट खातों के खोलने व संचालन के नियमों में ढील
- D) Mandatory restrictions on cash credit accounts / कैश क्रेडिट खातों पर अनिवार्य प्रतिबंध
- E) Withdrawal of overdraft facilities / ओवरड्राफ्ट सुविधाओं की समाप्ति

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India has eased norms related to the opening and maintenance of cash credit, current and overdraft accounts.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने कैश क्रेडिट, करंट और ओवरड्राफ्ट खातों के खोलने और संचालन से जुड़े नियमों में ढील दी है।
- The changes were notified through amended master directions.
- ये बदलाव संशोधित मास्टर निर्देशों के माध्यम से जारी किए गए हैं।
- The regulator adopted these changes after considering industry feedback on draft rules issued on 1 October 2025.
- 1 अक्टूबर 2025 को जारी मसौदा नियमों पर उद्योग से मिले फीडबैक के बाद RBI ने ये बदलाव किए हैं।
- As per the final guidelines, banks can now offer cash credit accounts to customers based on their needs without any restrictions.
- अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक अब ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर बिना किसी

प्रतिबंध के कैश क्रेडिट खाते प्रदान कर सकते हैं।

- Banks may now maintain current accounts without restriction for customers with banking exposure below ₹100 million.
- ₹100 मिलियन से कम बैंकिंग एक्सपोज़र वाले ग्राहकों के लिए करंट अकाउंट पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
- For exposures exceeding ₹100 million, banks with at least 10% exposure to the borrower can provide current and overdraft facilities.
- ₹100 मिलियन से अधिक एक्सपोज़र के मामलों में, जिन बैंकों का उधारकर्ता पर कम-से-कम 10% एक्सपोज़र है, वे करंट और ओवरड्राफ्ट सुविधाएं दे सकते हैं।
- If no bank or only one bank crosses the 10% exposure threshold, the top two lenders by exposure are allowed to maintain current and OD accounts.
- यदि कोई भी बैंक या केवल एक बैंक 10% एक्सपोज़र सीमा को पार करता है, तो RBI ने एक्सपोज़र के आधार पर शीर्ष दो उधारदाताओं को करंट और OD खाते रखने की अनुमति दी है।
- This modifies the earlier two-bank cap and aims to provide greater operational flexibility to borrowers and banks.
- यह पहले की दो में सीमा बैंक-संशोधन है और उधारकर्ताओं व बैंकों को अधिक परिचालन लचीलापन प्रदान करने का उद्देश्य रखता है।

Ques: Why has the RBI asked partner banks to stop issuing OneCard credit cards?

RBI ने पार्टनर बैंकों से OneCard क्रेडिट कार्ड जारी करना क्यों रोकने को कहा है?

- A) Due to high interest rates / उच्च ब्याज दरों के कारण
- B) Due to fraudulent transactions / धोखाधड़ी लेनदेन के कारण
- C) To seek clarity on data-sharing norms in the partnership / साझेदारी में डेटा-कारण के मिलने न स्पष्टता पर नियमों के करने साझा
- D) Because of low customer demand / कम ग्राहक मांग के कारण
- E) Due to technical issues with card network / कार्ड नेटवर्क में तकनीकी समस्याओं के कारण

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- FPL Technologies offers co-branded credit cards under the brand OneCard.
- FPL Technologies OneCard ब्रांड के तहत सहजै। करता प्रदान कार्ड क्रेडिट ब्रांडेड-
- RBI has asked partner banks to stop issuing OneCard credit cards.
- RBI ने पार्टनर बैंकों से OneCard क्रेडिट कार्ड जारी करना रोकने को कहा है।
- The reason is that RBI seeks clarity on the data-sharing norms followed in the partnership.
- इसका कारण यह है कि RBI साझेदारी में अपनाए गए डेटा स्पष्टता पर नियमों साझाकरण- है। चाहता
- The issuance ban will continue until RBI receives clarity or compliance confirmation.
- यह कार्ड जारी करने पर रोक तब तक रहेगी जब तक RBI को स्पष्टता या अनुपालन की पुष्टि नहीं मिलती।
- The action affects both FPL Technologies and its partner banks who issue the cards on its behalf.
- यह कदम FPL Technologies और उसके पार्टनर बैंकों दोनों को प्रभावित करता है, जो कार्ड उसके behalf पर जारी करते हैं।
- The move is seen as a regulatory hurdle impacting business operations.
- इसे व्यवसायिक संचालन पर प्रभाव डालने वाली नियामक बाधा के रूप में देखा जा रहा है।

Ques: Which two institutions signed an MoU to expand access to mutual fund services across India?

भारत में म्यूचुअल फंड सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए किन दो संस्थानों ने समझौता (MoU) किया है?

- A) Department of Posts and BSE / डाक विभाग और बीएसई
- B) Department of Posts and NSE / डाक विभाग और एनएसई
- C) RBI and BSE / आरबीआई और बीएसई
- D) SEBI and India Post / सेबी और इंडिया पोस्ट
- E) LIC and BSE / एलआईसी और बीएसई

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- The Department of Posts (DoP) and BSE, Asia's oldest stock exchange, have signed a landmark MoU to expand access to mutual fund services across India.
- डाक विभाग (DoP) और एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने भारत भर में म्यूचुअल फंड सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है।
- The initiative will leverage India Post's extensive end-to-end presence in rural and semi-urban areas.
- इस पहल में ग्रामीण और अर्ध का उपस्थिति नेटवर्क व्यापक की पोस्ट इंडिया में क्षेत्रों शहरी-उपयोग किया जाएगा।
- The aim is to bring investment opportunities closer to millions of citizens with limited access to formal financial products.
- इसका उद्देश्य औपचारिक वित्तीय उत्पादों तक सीमित पहुँच रखने वाले करोड़ों नागरिकों तक निवेश के अवसर पहुँचाना है।
- Mutual fund distribution will be carried out through BSE StAR MF, India's largest mutual fund platform.
- म्यूचुअल फंड का वितरण भारत के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म बीएसई स्टार एमएफ (BSE StAR MF) के माध्यम से किया जाएगा।
- The MoU is valid for a period of three years, from 12 December 2025 to 11 December 2028.
- यह समझौता 12 दिसंबर 2025 से 11 दिसंबर 2028 तक, कुल तीन वर्षों के लिए वैध है।

About BSE :

- Established : 1875
- HQ : Mumbai
- Chairman : Subhasis Chaudhuri
- MD & CEO : Sundararaman Ramamurthy

Ques: Which institution announced that retail Central Bank Digital Currency (CBDC) transactions have crossed 120 million in India?

भारत में रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) लेनदेन 120 मिलियन से अधिक होने की घोषणा किस संस्था ने की?

- A) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- B) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- C) Securities and Exchange Board of India / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

- D) NITI Aayog / नीति आयोग
E) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) announced that the volume of retail Central Bank Digital Currency (CBDC) transactions has crossed 120 million.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) लेनदेन की संख्या 120 मिलियन से अधिक हो गई है।
- The total transaction value through retail CBDC has exceeded ₹28,000 crore.
- रिटेल CBDC के माध्यम से कुल लेनदेन मूल्य ₹28,000 करोड़ से अधिक हो गया है।
- More than 8 million users are actively using the digital rupee (e₹) for daily transactions.
- 80 लाख से अधिक उपयोगकर्ता दैनिक लेनदेन के लिए डिजिटल रुपया (e₹) सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं।
- Retail CBDC, also known as the digital rupee (e₹), is RBI's flagship digital payment initiative providing a sovereign, secure, and efficient alternative to cash.
- रिटेल CBDC, जिसे डिजिटल रुपया (e₹) भी कहा जाता है, RBI की प्रमुख डिजिटल भुगतान पहल है, जो नकद का संप्रभु, सुरक्षित और कुशल विकल्प प्रदान करती है।
- The pilot project for retail CBDC began on 1 December 2022 and has since seen significant growth in adoption.
- रिटेल CBDC का पायलट प्रोजेक्ट 1 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ था, जिसके बाद इसके उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- RBI is also exploring programmable CBDCs for use in government schemes, Direct Benefit Transfers (DBTs), and sector-specific applications like education and healthcare.
- RBI प्रोग्रामेबल CBDC की संभावनाएँ भी तलाश रहा है, जिनका उपयोग सरकारी योजनाओं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है।
- To promote innovation, RBI has established a retail CBDC sandbox allowing banks and fintech firms to test CBDC-based wallets and payment solutions.
- नवाचार को बढ़ावा देने के लिए RBI ने रिटेल CBDC सैंडबॉक्स स्थापित किया है, जिससे बैंक और फिनटेक कंपनियाँ CBDC-आधारित वॉलेट और भुगतान समाधान विकसित व परीक्षण कर सकें।

Ques: Which public sector bank partnered with the Government of Nagaland for the Hornbill Festival 2025?

हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए नागालैंड सरकार के साथ किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने साझेदारी की?

- A) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- D) Canara Bank / केनरा बैंक
- E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- Bank of Baroda, a public sector bank, partnered with the Government of Nagaland for the Hornbill Festival 2025.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा ने हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए नागालैंड सरकार के साथ साझेदारी की।
- The festival was held at the Kisama Heritage Village near Kohima.
- यह महोत्सव कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया गया।
- Bank of Baroda has strengthened its presence in North East India with 3 Regional Offices and 197 branches.
- बैंक ऑफ बड़ौदा ने पूर्वोत्तर भारत में 3 क्षेत्रीय कार्यालयों और 197 शाखाओं के साथ अपनी उपस्थिति मजबूत की है।
- About 61% of the bank's branches in the region are located in rural and semi-urban areas.
- क्षेत्र में बैंक की लगभग 61% शाखाएँ ग्रामीण और अर्धहैं। स्थित में क्षेत्रों शहरी-
- The bank recently inaugurated a new Zonal Office in Guwahati to cover all North Eastern States.
- बैंक ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करने के लिए हाल ही में गुवाहाटी में एक नया ज़ोनल कार्यालय शुरू किया है।

Ques: What was India's Wholesale Price Inflation (WPI) rate in November 2025?

नवंबर 2025 में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति) WPI) दर कितनी रही?

- A) 0.52
- B) 0.13%
- C) -0.32%
- D) -1.21%
- E) 2.16%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Wholesale Price Inflation (WPI) in India stood at -0.32% in November 2025, according to government data.
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2025 में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति) WPI) - 0.32% रही।
- The marginal improvement was driven by a month-on-month increase in prices of food articles such as pulses and vegetables.
- यह मामूली सुधार दालों और सब्जियों जैसी खाद्य वस्तुओं की मासिक आधार पर बढ़ती कीमतों के कारण हुआ।
- WPI-based inflation was recorded at -1.21% in October 2025.
- अक्टूबर 2025 में WPI आधारित मुद्रास्फीति -1.21% थी।
- In comparison, WPI inflation was 2.16% in November last year.
- तुलना में, पिछले वर्ष नवंबर में WPI मुद्रास्फीति 2.16% थी।

Recent WPI-based Retail inflation in India:

- October 2025 : -1.21%
- September 2025 : 0.13%
- August 2025 : 0.52%
- July 2025 : - 0.58%

Ques: Which city's metro rail expansion has received a USD 240 million loan from the Asian Development Bank (ADB)?

एशियाई विकास बैंक) ADB) से 240 मिलियन डॉलर का ऋण किस शहर के मेट्रो विस्तार के लिए मिला है?

- A) Bengaluru / बेंगलुरु
- B) Hyderabad / हैदराबाद
- C) Chennai / चेन्नई
- D) Mumbai / मुंबई
- E) Kolkata / कोलकाता

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Asian Development Bank (ADB) has approved a USD 240 million loan for the expansion of the Chennai Metro Rail network.
- एशियाई विकास बैंक) ADB) ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 240 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है।
- This is the second tranche under the Chennai Metro Rail Investment Project.
- यह चेन्नई मेट्रो रेल निवेश परियोजना के तहत दूसरी किस्त है।
- The project aims to provide cleaner, safer, and more reliable urban transport across the Chennai Metropolitan Area.
- इस परियोजना का उद्देश्य चेन्नई महानगरीय क्षेत्र में स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक भरोसेमंद शहरी परिवहन उपलब्ध कराना है।
- The loan is part of ADB's USD 780 million multi-tranche financing facility approved in 2022. The first tranche of USD 350 million was approved earlier.
- यह ऋण 2022 में स्वीकृत ADB की 780 मिलियन डॉलर की मल्टी-ट्रान्च फाइनेंसिंग सुविधा का हिस्सा है, जिसमें पहले 350 मिलियन डॉलर की पहली किस्त स्वीकृत की गई थी।

Ques: NABARD has extended a loan of ₹1,685.27 crore to which organisation?

नाबार्ड ने ₹1,685.27 करोड़ का ऋण किस संस्था को प्रदान किया है?

- A) Odisha Power Generation Corporation / ओडिशा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन

- B) Odisha Power Transmission Corporation Limited / ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
C) GRIDCO Limited / ग्रिडको लिमिटेड
D) Odisha Hydro Power Corporation / ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन
E) Power Finance Corporation / पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) has sanctioned a loan of ₹1,685.27 crore to Odisha Power Transmission Corporation Limited (OPTCL).
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कॉर्पोरेशन ट्रांसमिशन पावर ओडिशा ने (नाबार्ड) लिमिटेड (OPTCL) को ₹1,685.27 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया है।
- The loan carries an interest rate of 7.75% per annum.
- इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 7.75% निर्धारित की गई है।
- The tenure of the loan is 15 years, with the first 3 years as a moratorium period.
- ऋण की अवधि 15 वर्ष है, जिसमें पहले 3 वर्ष मोराटोरियम अवधि के रूप में रखे गए हैं।
- The funding will support power transmission infrastructure development in Odisha.
- यह वित्तपोषण ओडिशा में विद्युत पारेषण अवसंरचना के विकास में सहायता करेगा।

About NABARD :

- Established : 12 July 1982 (Under recommendations of B. Sivaraman Committee)
 - HQ : Mumbai
 - Chairman : K V Shaji
-

Ques: Why has RBI directed banks to link MSME loans to an external benchmark?

RBI ने MSME ऋणों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने का निर्देश क्यों दिया है?

A) To increase bank profitability / बैंकों की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए

- B) To standardise MSME loan documentation / MSME ऋण दस्तावेजों का मानकीकरण करने के लिए
- C) To improve monetary policy transmission / मौद्रिक नीति के प्रभावी प्रसारण के लिए
- D) To reduce MSME loan defaults / MSME ऋण डिफॉल्ट कम करने के लिए
- E) To eliminate collateral requirements / जमानत की आवश्यकता समाप्त करने के लिए

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- RBI has directed banks to link MSME loans to an external benchmark to ensure faster and transparent transmission of policy rate changes to borrowers.
- RBI ने MSME ऋणों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने का निर्देश इसलिए दिया है ताकि नीतिगत दरों में बदलाव का प्रभाव उधारकर्ताओं तक तेज़ी और पारदर्शिता के साथ पहुंच सके।
- Under this system, the interest rate reset period for MSME loans has been reduced to three months.
- इस प्रणाली के तहत MSME ऋणों के लिए ब्याज दर रीसेट अवधि तीन महीने कर दी गई है।
- Existing MSME borrowers are allowed to switch to the external benchmark-linked interest rate regime as per mutually agreed terms with banks.
- मौजूदा MSME उधारकर्ताओं को बैंक के साथ पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार बाहरी बेंचमार्क आधारित ब्याज दर प्रणाली में स्थानांतरित होने की अनुमति दी गई है।

Genius

Ques: India's banking sector recently achieved a 20-year low in Gross Non-Performing Assets (GNPAs). What was the GNPA level by March 2025?

भारत के बैंकिंग क्षेत्र में मार्च 2025 तक सकल गैर) परिसंपत्तियाँ निष्पादित-GNPA) किस स्तर तक आ गईं?

- A) 3.95%
- B) 2.98%
- C) 2.58%
- D) 2.31%

E) 1.85%

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- India's banking sector recorded its lowest Gross Non-Performing Assets (GNPA) level in 20 years, declining from 11.46% in 2018 to 2.31% by March 2025.
- भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सकल गैर परिसंपत्तियाँ निष्पादित-2018 में 11.46% से घटकर मार्च 2025 में 2.31% पर आ गई, जो 20 वर्षों में सबसे कम स्तर है।
- Net NPA (NNPA) ratio also fell sharply to 0.52%, the lowest in two decades, compared to 6.1% in 2018, supported by stronger provisioning.
- शुद्ध एनपीए अनुपात भी 2018 के 6.1% से घटकर 0.52% पर आ गया, जो दो दशकों में सबसे कम है।
- GNPA of Public Sector Banks (PSBs) declined from 9.11% in March 2021 to 2.58% in March 2025.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के GNPA मार्च 2021 में 9.11% से घटकर मार्च 2025 में 2.58% रह गए।
- GNPA of Scheduled Commercial Banks (SCBs) reduced from 7.33% to 2.22% during the same period.
- इसी अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के GNPA 7.33% से घटकर 2.22% हो गए।
- Domestic deposits rose from ₹88.35 lakh crore (2015) to ₹231.90 lakh crore (2025), while credit expanded from ₹66.91 lakh crore to ₹181.34 lakh crore.
- घरेलू जमा 2015 में ₹88.35 लाख करोड़ से बढ़कर 2025 में ₹231.90 लाख करोड़ हो गए, जबकि ऋण ₹66.91 लाख करोड़ से बढ़कर ₹181.34 लाख करोड़ हो गया।
- Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) improved from 12.94% (March 2015) to 17.36% (March 2025).
- पूंजी से जोखिमका परिसंपत्तियों भारित- अनुपात (CRAR) मार्च 2015 के 12.94% से बढ़कर मार्च 2025 में 17.36% हो गया।
- Total business of PSBs increased from ₹203 lakh crore (FY23) to ₹252 lakh crore (FY25), with net profit rising from ₹1.05 lakh crore to ₹1.78 lakh crore.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल व्यवसाय FY23 में ₹203 लाख करोड़ से बढ़कर FY25 में ₹252 लाख करोड़ हो गया और शुद्ध लाभ ₹1.05 लाख करोड़ से बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ हो गया।
- Scheduled Commercial Banks recorded their highest-ever aggregate net profit of ₹4.01 lakh crore in FY25.
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने FY25 में अब तक का सबसे अधिक कुल शुद्ध लाभ ₹4.01

लाख करोड़ दर्ज किया।

**Ques: What is SBI's user target under YONO 2.0 over the next two years?
YONO 2.0 के तहत अगले दो वर्षों में SBI का यूजर लक्ष्य क्या है?**

- A) 150 million
- B) 175 million
- C) 180 million
- D) 200 million
- E) 250 million

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- State Bank of India (SBI) has launched YONO 2.0, the upgraded version of its digital banking platform "You Only Need One (YONO)".
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म "यू ओनली नीड वन (YONO)" का उन्नत संस्करण YONO 2.0 लॉन्च किया है।
- SBI aims to double its YONO user base from 96 million to 200 million in the next two years.
- SBI का लक्ष्य अगले दो वर्षों में YONO यूजर्स की संख्या 96 मिलियन से बढ़ाकर 200 मिलियन करना है।
- SBI plans to hire around 10,000 staff (floor managers) to shift customers from branches to digital channels.
- SBI शाखाओं से ग्राहकों को डिजिटल चैनलों पर स्थानांतरित करने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारियों (फ्लोर मैनेजर) की नियुक्ति करेगा।
- YONO 2.0 is expected to reduce customer service costs by 40–60 percent.
- YONO 2.0 से ग्राहक सेवा लागत में 40–60 प्रतिशत तक कमी आने की उम्मीद है।
- The platform will help reduce branch footfall by 20–30 percent and enhance productivity.
- यह प्लेटफॉर्म शाखाओं में भीड़ को 20–30 प्रतिशत तक कम करेगा और उत्पादकता बढ़ाएगा।
- YONO 2.0 will accelerate digital credit delivery through automated decision-making processes.
- YONO 2.0 ऑटोमेटेड निर्णय प्रणाली के माध्यम से डिजिटल क्रेडिट को तेज करेगा।

- Currently, YONO 2.0 is available in English and Hindi and will soon support 15 languages.
- YONO 2.0 फिलहाल अंग्रेज़ी और हिंदी में उपलब्ध है और जल्द ही 15 भाषाओं में उपलब्ध होगा।

Ques: JPMorgan Chase is establishing Asia's largest Global Capability Centre (GCC) in which city?

JPMorgan Chase एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर)GCC) किस शहर में स्थापित कर रहा है?

- A) Bengaluru / बेंगलुरु
- B) Chennai / चेन्नई
- C) Hyderabad / हैदराबाद
- D) Pune / पुणे
- E) Mumbai / मुंबई

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- JPMorgan Chase, a leading U.S. banking and financial services firm, is setting up Asia's largest Global Capability Centre (GCC) in Powai, Mumbai.
- JPMorgan Chase, एक प्रमुख अमेरिकी बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी, एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर)GCC) मुंबई के पोवाई में स्थापित कर रहा है।
- The centre will cover approximately 2 million square feet and is expected to be completed by 2029.
- यह सेंटर लगभग 20 लाख वर्ग फुट में फैलेगा और 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है।
- The GCC aims to enhance JPMorgan's operational capabilities and provide advanced services across Asia.
- यह GCC JPMorgan की संचालन क्षमताओं को बढ़ाने और एशिया भर में उन्नत सेवाएं प्रदान करने का उद्देश्य रखता है।

Ques: Which bank won the Global Bank of the Year 2025 award by The Banker?

The Banker द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार किस बैंक को दिया गया?

- A) HSBC / एचएसबीसी
- B) Standard Chartered / स्टैंडर्ड चार्टर्ड
- C) DBS Bank / डीबीएस बैंक
- D) JPMorgan Chase / जेपी मॉर्गन चेस
- E) Citibank / सिटीबैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Singapore-based DBS Bank was awarded Global Bank of the Year 2025.
- सिंगापुर स्थित DBS बैंक को ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 चुना गया।
- The award was conferred by The Banker, a reputed publication of the Financial Times Group.
- यह पुरस्कार फाइनेंशियल टाइम्स समूह की प्रतिष्ठित पत्रिका The Banker द्वारा प्रदान किया गया।
- The honour was presented at the Bank of the Year Awards 2025 held in London, United Kingdom.
- यह सम्मान लंदन, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 में दिया गया।
- DBS also won other major titles such as Asia Bank of the Year, Singapore Bank of the Year, Investment Bank of the Year – Asia, and the first-ever Investment Bank of the Year award.
- इसके अलावा DBS ने एशिया बैंक ऑफ द ईयर, सिंगापुर बैंक ऑफ द ईयर, इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ द ईयर – एशिया और पहली बार दिया गया इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार भी जीता।
- This is DBS's third Global Bank of the Year win after 2018 and 2021.
- यह 2018 और 2021 के बाद इस श्रेणी में DBS की तीसरी जीत है।
- With this achievement, DBS now holds Best Bank titles from both The Banker and Euromoney in 2025.
- इस उपलब्धि के साथ DBS ने 2025 में The Banker और Euromoney दोनों से सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब हासिल किया।

Ques: NCDEX has received in-principle approval from SEBI to launch which of the following platforms?

NCDEX को SEBI से किस प्लेटफॉर्म को शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली है?

- A) Commodity spot trading platform / कमोडिटी स्पॉट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
- B) Mutual Fund transaction platform / म्यूचुअल फंड लेनदेन प्लेटफॉर्म
- C) Digital lending platform / डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म
- D) Insurance distribution platform / बीमा वितरण प्लेटफॉर्म
- E) Crypto asset exchange / क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- National Commodity and Derivatives Exchange Limited (NCDEX) has received in-principle approval from the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to launch a Mutual Fund transaction platform.
- नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (NCDEX) को म्यूचुअल फंड लेनदेन प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।
- The approval will enable NCDEX to set up a platform that allows investors to buy and sell mutual fund units, subject to compliance with regulatory requirements.
- इस मंजूरी के तहत NCDEX निवेशकों को म्यूचुअल फंड यूनिट्स की खरीद और बिक्री की सुविधा देने वाला प्लेटफॉर्म स्थापित कर सकेगा, बशर्ते नियामकीय शर्तों का पालन किया जाए।
- The backend processing for the MF transaction platform will be handled by National Commodity Clearing Limited (NCCL).
- म्यूचुअल फंड लेनदेन प्लेटफॉर्म की बैकएंड प्रोसेसिंग नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड (NCCL) द्वारा की जाएगी।
- NCCL is a wholly owned subsidiary of NCDEX.
- NCCL, NCDEX की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

Ques: According to data shared by the Ministry of Finance, what was the value of crypto transactions in India during 2024–25?

वित्त मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 2024–25 में भारत में क्रिप्टो लेनदेन का कुल मूल्य कितना था?

- A) ₹36,270 crore
- B) ₹45,000 crore
- C) ₹51,180 crore
- D) ₹60,000 crore
- E) ₹22,130 crore

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- For 2024–25, the value of crypto transactions in India crossed ₹51,000 crore, registering a 41% year-on-year growth, as informed by the Ministry of Finance in the Rajya Sabha.
- 2024–25 में भारत में क्रिप्टो लेनदेन का मूल्य ₹51,000 करोड़ से अधिक हो गया, जिसमें 41% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जैसा कि वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया।
- The government collected ₹511.8 crore as 1% Tax Deducted at Source (TDS) on crypto transactions during this period.
- इस अवधि के दौरान सरकार ने क्रिप्टो लेनदेन पर 1% टीडीएस के रूप में ₹511.8 करोड़ एकत्र किए।
- Growth trend in crypto transaction value shows a steady rise: ₹22,130 crore in 2022–23, ₹36,270 crore in 2023–24, and ₹51,180 crore in 2024–25.
- क्रिप्टो लेनदेन मूल्य की वृद्धि का रुझान निरंतर बढ़ता हुआ रहा : 2022–23 में ₹22,130 करोड़, 2023–24 में ₹36,270 करोड़ और 2024–25 में ₹51,180 करोड़।
- Under Indian law, cryptocurrencies are classified as Virtual Digital Assets (VDAs); they are not legal tender but are treated as taxable assets.
- भारतीय कानून के तहत क्रिप्टोकॉइन्स को वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है; यह वैध मुद्रा नहीं है बल्कि कर योग्य परिसंपत्ति है।
- VDAs include cryptocurrencies like Bitcoin and Ether, NFTs, and other cryptographic tokens, but exclude the RBI-issued digital rupee (e₹).
- VDAs में बिटकॉइन और ईथर जैसी क्रिप्टोकॉइन्स, एनएफटी और अन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन शामिल हैं, जबकि RBI द्वारा जारी डिजिटल रुपया (e₹) इसमें शामिल नहीं है।
- Crypto taxation in India follows the Finance Act, 2022, with a 30% flat tax on profits, no loss set-off, and 1% TDS on every transaction, even if there is no

profit.

- भारत में क्रिप्टो कराधान वित्त अधिनियम, 2022 के अनुसार है, जिसमें मुनाफे पर 30% फ्लैट टैक्स, नुकसान की समायोजन की अनुमति नहीं और हर लेनदेन पर 1% टीडीएस लागू है, चाहे लाभ हो या नहीं।

Ques: Under which route has the RBI permitted Rural Co-operative Banks to open new branches as per the 2025 Directions?

RBI के 2025 निर्देशों के अनुसार ग्रामीण सहकारी बैंकों को नई शाखाएँ किस मार्ग के तहत खोलने की अनुमति दी गई है?

- A) Approval Route / अनुमोदन मार्ग
- B) Automatic Route / स्वचालित मार्ग
- C) Liberalised Route / उदारीकृत मार्ग
- D) Special Permission Route / विशेष अनुमति मार्ग
- E) State Government Route / राज्य सरकार मार्ग

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India has allowed Rural Co-operative Banks to open new branches under the Automatic Route, as per the RBI (Rural Co-operative Banks – Branch Authorisation) Directions, 2025.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने RBI (ग्रामीण सहकारी बैंक – शाखा प्राधिकरणनिर्देश (, 2025 के तहत ग्रामीण सहकारी बैंकों को स्वचालित मार्ग से नई शाखाएँ खोलने की अनुमति दी है।
- State Co-operative Banks (StCBs) and Central Co-operative Banks (CCBs) that meet the Eligibility Criteria for Business Authorization (ECBA) can open branches without prior RBI approval.
- जो राज्य सहकारी बैंक (StCBs) और केंद्रीय सहकारी बैंक (CCBs) व्यवसाय प्राधिकरण के लिए पात्रता मानदंड (ECBA) पूरा करते हैं, वे RBI की पूर्व अनुमति के बिना शाखाएँ खोल सकते हैं।
- The number of branches under the Automatic Route in a financial year is capped at 15% of total branches as on March 31 of the previous year, with a minimum of one and a maximum of ten branches.
- स्वचालित मार्ग के तहत एक वित्तीय वर्ष में खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या पिछले

वर्ष 31 मार्च तक की कुल शाखाओं के 15% तक सीमित है, जिसमें न्यूनतम एक और अधिकतम दस शाखाएँ शामिल हैं।

- The Directions also mandate that all existing branches of the bank must have valid RBI authorisation.
- निर्देशों के अनुसार बैंक की सभी मौजूदा शाखाओं के पास RBI से वैध प्राधिकरण होना अनिवार्य है।

Ques: Which bank partnered with SalarySe to launch the Level Up Credit Card powered by Credit on UPI?

किस बैंक ने SalarySe के साथ मिलकर Credit on UPI आधारित Level Up Credit Card लॉन्च किया?

- A) Federal Bank / फेडरल बैंक
- B) City Union Bank / सिटी यूनियन बैंक
- C) Canara Bank / केनरा बैंक
- D) IDFC First Bank / आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
- E) Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- City Union Bank has partnered with the financial wellbeing platform SalarySe to launch the Level Up Credit Card.
- सिटी यूनियन बैंक ने वित्तीय कल्याण प्लेटफॉर्म SalarySe के साथ मिलकर Level Up Credit Card लॉन्च किया है।
- The card is designed exclusively for salaried individuals and is powered by Credit on UPI (Unified Payments Interface) technology.
- यह कार्ड विशेष रूप से वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए बनाया गया है और Credit on UPI तकनीक पर आधारित है।
- The initiative aligns with the Reserve Bank of India's vision of promoting a cashless economy.
- यह पहल कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की भारतीय रिज़र्व बैंक की सोच के अनुरूप है।
- The Level Up Credit Card rewards users based on real-life spending patterns

such as everyday UPI payments, online transactions, monthly bills, and in-store purchases.

- Level Up Credit Card रोजमर्रा के UPI भुगतान, ऑनलाइन लेनदेन, मासिक बिल और इनहै। देता रिवाँर्ड पर आधार के पैटर्न खर्च वास्तविक जैसे खरीदारी स्टोर-
- The collaboration aims to seamlessly integrate credit cards with UPI, enhancing convenience and digital payment adoption among working professionals.
- इस सहयोग का उद्देश्य क्रेडिट कार्ड को UPI के साथ सहज रूप से जोड़कर कार्यरत पेशेवरों के बीच सुविधा और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।

Ques: JPMorgan Chase & Co. has received in-principle approval from the RBI to open a new branch in which Indian city?

JPMorgan Chase & Co. को RBI से किस भारतीय शहर में नई शाखा खोलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली है?

- A) Pune / पुणे
- B) Ahmedabad / अहमदाबाद
- C) Chennai / चेन्नई
- D) Gurugram / गुरुग्राम
- E) Kochi / कोच्चि

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- JPMorgan Chase & Co. has received in-principle approval from the Reserve Bank of India (RBI) to open a new branch in Pune.
- JPMorgan Chase & Co. को पुणे में नई शाखा खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।
- This marks JPMorgan's first branch expansion in India in nearly a decade.
- यह लगभग एक दशक में भारत में JPMorgan का पहला शाखा विस्तार है।
- The Pune branch will be JPMorgan's fourth branch in India and will mainly serve corporate clients.
- पुणे शाखा भारत में JPMorgan की चौथी शाखा होगी और यह मुख्य रूप से कॉर्पोरेट ग्राहकों को सेवाएं देगी।

- Currently, J.P. Morgan has major corporate centres in Mumbai, Bengaluru, and Hyderabad.
- वर्तमान में J.P. Morgan के प्रमुख कॉर्पोरेट केंद्र मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में स्थित हैं।
- JPMorgan last received approval to open branches in India in 2016, when it was allowed to set up three branches.
- इससे पहले JPMorgan को भारत में शाखाएं खोलने की अनुमति 2016 में मिली थी, जब उसे तीन शाखाएं स्थापित करने की मंजूरी दी गई थी।

Ques: The newly launched mutual fund First-India, offering Russian retail investors exposure to India's equity market, is linked to which stock market index?

रूसी खुदरा निवेशकों को भारत के इक्विटी बाज़ार में निवेश का अवसर देने वाला First-India म्यूचुअल फंड किस शेयर बाज़ार सूचकांक से जुड़ा है?

- A) Sensex
- B) Nifty Bank
- C) Nifty Midcap 100
- D) Nifty50 Index
- E) BSE 500

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Sberbank and JSC First Asset Management have jointly launched a new mutual fund named First-India.
- Sberbank और JSC First Asset Management ने मिलकर First-India नामक एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है।
- The fund provides Russian retail investors with exposure to India's equity market.
- यह फंड रूसी खुदरा निवेशकों को भारत के शेयर बाज़ार में निवेश का अवसर प्रदान करता है।
- The fund tracks the Nifty50 Index, India's flagship equity index.
- यह फंड भारत के प्रमुख इक्विटी सूचकांक निफ्टी 50 से जुड़ा है।
- The fund was unveiled during Sberbank CEO Herman Gref's visit to India at an event hosted by the National Stock Exchange (NSE).

- इस फंड का अनावरण Sberbank के CEO हरमन ग्रेफ की भारत यात्रा के दौरान NSE द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया।
- The Nifty50 Index was launched in 1996 and consists of 50 major stocks across 15 sectors.
- निफ्टी 50 सूचकांक की शुरुआत 1996 में हुई थी और इसमें 15 क्षेत्रों की 50 प्रमुख कंपनियाँ शामिल हैं।
- It is one of the world's most widely tracked indices, with over 45 passive funds in India and 22 overseas funds linked to it.
- यह दुनिया के सबसे अधिक ट्रैक किए जाने वाले सूचकांकों में से एक है, जिससे भारत में 45 से अधिक और विदेशों में 22 फंड जुड़े हुए हैं।

Ques: RBI has approved HDFC Bank and its group entities to acquire up to what maximum stake in IndusInd Bank Limited?

RBI ने HDFC बैंक और उसकी समूह इकाइयों को इंडसइंड बैंक लिमिटेड में अधिकतम कितनी हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है?

- A) 5%
- B) 7.5%
- C) 9%
- D) 9.5%
- E) 10%

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India has approved HDFC Bank Limited, along with its group entities, to acquire an aggregate holding of up to 9.5% of the paid-up share capital or voting rights in IndusInd Bank Limited.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने HDFC बैंक लिमिटेड और उसकी समूह इकाइयों को इंडसइंड बैंक लिमिटेड की चुकता शेयर पूंजी या मतदान अधिकारों में कुल मिलाकर 9.5% तक हिस्सेदारी प्राप्त करने की मंजूरी दी है।
- The approval is valid for a period of one year, from 15 December 2025 to 14 December 2026.
- यह मंजूरी 15 दिसंबर 2025 से 14 दिसंबर 2026 तक एक वर्ष की अवधि के लिए वैध है।
- RBI has clearly specified that the aggregate holding of HDFC Bank and its

group entities must not exceed 9.50% at any point during the approval period.

- RBI ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि के दौरान HDFC बैंक और उसकी समूह इकाइयों की कुल हिस्सेदारी किसी भी समय 9.50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Ques: According to a Moody's survey, banks in which region have stronger capital positions compared to banks in the United States and Western Europe?

मूडीज़ के सर्वेक्षण के अनुसार, किस क्षेत्र के बैंकों की पूंजी स्थिति अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के बैंकों की तुलना में अधिक मजबूत है?

- A) Latin America / लैटिन अमेरिका
- B) Africa / अफ्रीका
- C) Asia-Pacific / एशियाप्रशांत-
- D) Middle East / मध्य पूर्व
- E) Eastern Europe / पूर्वी यूरोप

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- A Moody's survey states that banks in the Asia-Pacific region, including India, have stronger capital positions than banks in the United States and Western Europe, supported by prudent regulatory supervision.
- मूडीज़ के सर्वेक्षण के अनुसार भारत सहित एशियास् पूंजी की बैंकों के क्षेत्र प्रशांत-थिति अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के बैंकों की तुलना में अधिक मजबूत है, जिसका कारण सतर्क नियामकीय निगरानी है।
- A comparison of the largest Asia-Pacific banks with their US and Western European peers shows stronger capital buffers and healthier balance sheets.
- एशिया तुलना की बैंकों यूरोपीय पश्चिमी और अमेरिकी में तुलना की बैंकों बड़े के क्षेत्र प्रशांत-गई। पाई शीट बैलेंस मजबूत और बफर पूंजी बेहतर पास इनके में
- Risk-Weighted Asset (RWA) densities of Asia-Pacific banks generally reflect actual asset risks and align with their credit loss patterns over the last decade.
- एशिया) परिसंपत्ति भारित-जोखिम की बैंकों प्रशांत-RWA) घनत्व आमतौर पर वास्तविक परिसंपत्ति जोखिम को दर्शाती है और पिछले दशक के क्रेडिट नुकसान पैटर्न से मेल खाती है।
- India, Vietnam and parts of China show higher RWA densities due to the use

of the Standardised Approach, which assigns fixed regulatory risk weights.

- भारत, वियतनाम और चीन के कुछ हिस्सों में मानकीकृत पद्धति (Standardised Approach) अपनाने के कारण RWA घनत्व अधिक है, जिसमें निश्चित नियामकीय जोखिम भार दिए जाते हैं।
- Indian regulators plan to allow banks to shift to the advanced Internal Ratings-Based (IRB) approach by 2028, which may reduce RWA densities.
- भारत में नियामक 2028 तक बैंकों को उन्नत आंतरिक रेटिंग) आधारित-IRB) पद्धति अपनाने की अनुमति देने की योजना बना रहे हैं, जिससे RWA घनत्व कम हो सकता है।
- For India, the sample included SBI, Axis Bank, ICICI Bank and HDFC Bank, covering about 50% of the total banking system assets.
- भारत के लिए नमूने में SBI, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक शामिल थे, जो कुल बैंकिंग प्रणाली की लगभग 50% परिसंपत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- Overall, Moody's evaluated 35 banks across eight Asia-Pacific banking systems, representing nearly 75% of total rated bank assets in these markets.
- कुल मिलाकर, मूडीज़ ने आठ एशिया के प्रणालियों बैंकिंग प्रशांत-35 बैंकों का मूल्यांकन किया, जो इन बाजारों की लगभग 75% रेटेड बैंक परिसंपत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Ques: The government plans to sell up to 3% stake in which public sector bank to raise ₹2,100 crore?

सरकार ₹2,100 करोड़ जुटाने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में 3% तक हिस्सेदारी बेचेगी?

- A) Bank of Maharashtra / महाराष्ट्र बैंक
- B) Punjab & Sind Bank / पंजाब एंड सिंध बैंक
- C) Indian Overseas Bank / इंडियन ओवरसीज बैंक
- D) Central Bank of India / सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- E) UCO Bank / यूको बैंक

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Government of India has decided to divest up to 3% stake in Indian Overseas Bank (IOB) through an Offer for Sale (OFS) route.

- भारत सरकार ने इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) में 3% तक हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से बेचने का निर्णय लिया है।
- At current market prices, the stake sale is expected to raise around ₹2,100 crore.
- मौजूदा बाजार कीमतों पर इस हिस्सेदारी की बिक्री से लगभग ₹2,100 करोड़ जुटने की उम्मीद है।
- The OFS will first open for non-retail investors, followed by retail investors the next day.
- OFS पहले गैरखुलेगा लिए के निवेशकों रिटेल-, उसके बाद अगले दिन रिटेल निवेशकों के लिए।
- IOB shares closed at ₹36.57 per share on the BSE, down 1.08%.
- IOB के शेयर BSE पर ₹36.57 पर बंद हुए, जिसमें 1.08% की गिरावट रही।
- This move is part of the government's disinvestment and asset monetisation strategy.
- यह कदम सरकार की विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण रणनीति का हिस्सा है।

Ques: State Bank of India (SBI) extended a loan of €150 million to KfW Development Bank for what purpose?

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने KfW डेवलपमेंट बैंक को €150 मिलियन का ऋण किस उद्देश्य के लिए दिया है?

- A) Expansion of digital banking services / डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार
- B) Urban transport infrastructure development / शहरी परिवहन अवसंरचना विकास
- C) Climate-friendly energy generation projects / जलवायु उत्पादन ऊर्जा अनुकूल-परियोजनाएं
- D) Affordable housing projects / किफायती आवास परियोजनाएं
- E) MSME credit support / MSME ऋण सहायता

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- State Bank of India (SBI) has extended a loan of €150 million (approximately ₹1,360 crore) to Germany's KfW Development Bank.

- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने जर्मनी के KfW डेवलपमेंट बैंक को €150 मिलियन लगभग) ₹1,360 करोड़ है। किया प्रदान ऋण का (
- The loan is aimed at supporting financing for climate-friendly energy generation projects in India.
- यह ऋण भारत में जलवायु लिए के वित्तपोषण के परियोजनाओं उत्पादन ऊर्जा अनुकूल- है। गया दिया
- The initiative seeks to accelerate renewable energy adoption and promote sustainable infrastructure development across the country.
- इस पहल का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाना और देश में सतत अवसंरचना विकास को बढ़ावा देना है।
- Such international green financing partnerships align with India's long-term climate goals and transition towards a low-carbon economy.
- इस प्रकार की अंतरराष्ट्रीय हरित वित्तीय साझेदारियाँ भारत के दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों और कम हैं। अनुरूप के संक्रमण ओर की अर्थव्यवस्था कार्बन-

Ques: NABARD is set to launch two new thematic funds in January 2026 primarily to support which sector?

NABARD जनवरी 2026 में जिन दो नए थीमैटिक फंड्स को लॉन्च करने जा रहा है, उनका मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र को समर्थन देना है?

- A) Urban housing and infrastructure / शहरी आवास और अवसंरचना
- B) Manufacturing and MSMEs / विनिर्माण और MSME
- C) Agriculture and climate technology start-ups / कृषि और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप-
- D) Digital payments and fintech / डिजिटल भुगतान और फिनटेक
- E) Healthcare and pharmaceuticals / स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) will launch two thematic funds in January 2026 — the ₹1,000 crore NABARD Green Impact Fund (NGIF) and the ₹300 crore NABARD Carbon Fund (NCF).
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) जनवरी 2026 में दो थीमैटिक फंड —

₹1,000 करोड़ का NABARD ग्रीन इम्पैक्ट फंड (NGIF) और ₹300 करोड़ का NABARD कार्बन फंड (NCF) — लॉन्च करेगा।

- These funds are aimed at supporting agriculture and climate technology start-ups across India.
- इन फंड्स का उद्देश्य देश में कृषि और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप देना समर्थन को अप्स-
- Both funds have been developed with technical assistance from Intellecip, which is part of the Aavishkaar Group.
- दोनों फंड्स को आविष्कार ग्रुप की इकाई इंटेलेकैप (Intellecip) की तकनीकी सहायता से विकसित किया गया है।
- The NABARD Green Impact Fund, financed from NABARD's profits, will use interest income to reduce borrowing costs for state governments implementing climate adaptation projects such as crop diversification and water-efficient farming.
- NABARD ग्रीन इम्पैक्ट फंड, जिसे NABARD के मुनाफे से वित्तपोषित किया गया है, जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं जैसे फसल विविधीकरण और जल लागू को खेती कुशल-करेगा। कम लागत उधारी लिए के सरकारों राज्य वाले करने
- The NABARD Carbon Fund will focus on carbon developers and start-ups working on emission reduction and carbon capture, which are capital-intensive and underserved by traditional finance.
- NABARD कार्बन फंड उन कार्बन डेवलपर्स और स्टार्ट में उत्सर्जन जो होगा केंद्रित पर अप्स-हैं रहे कर काम पर कैप्चर कार्बन और कमी, जो पूंजीग-हन हैं और पारंपरिक वित्त व्यवस्था से कम समर्थित हैं।

Ques: Who has been appointed as the Managing Director (MD) of State Bank of India with tenure up to December 31, 2027?

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के प्रबंध निदेशक (MD) के रूप में किसे 31 दिसंबर 2027 तक के लिए नियुक्त किया गया है?

- A) Rana Ashutosh Kumar Singh / राणा अशुतोष कुमार सिंह
- B) Rama Mohan Rao Amara / रामा मोहन राव अमरा
- C) Ravi Ranjan / रवि रंजन
- D) Ashwini Kumar Tewari / अश्विनी कुमार तिवारी
- E) Ashwini Kumar Tiwari / अश्विनी कुमार तिवारी

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Ashwini Kumar Tewari has been appointed as the Managing Director (MD) of the State Bank of India.
- अश्विनी कुमार तिवारी को भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।
- His tenure will be up to December 31, 2027, or until further orders, whichever is earlier.
- उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2027 तक या अगले आदेश तक रहेगा। (हो पहले जो)
- He first took charge as SBI Managing Director in January 2021 for a period of three years.
- उन्होंने जनवरी 2021 में पहली बार तीन वर्षों के लिए SBI के MD का कार्यभार संभाला था।
- His tenure was later extended by two years in 2024, till January 2026.
- बाद में वर्ष 2024 में उनका कार्यकाल बढ़ाकर जनवरी 2026 तक कर दिया गया।
- Other Managing Directors of SBI include Rana Ashutosh Kumar Singh, Ashwini Kumar Tiwari, Rama Mohan Rao Amara, and Ravi Ranjan.
- SBI के अन्य प्रबंध निदेशकों में राणा अशुतोष कुमार सिंह, अश्विनी कुमार तिवारी, रामा मोहन राव अमरा और रवि रंजन शामिल हैं।

Ques: 'Google Pay Flex Axis Bank Credit Card' is built on which payment network?

'Google Pay Flex Axis Bank Credit Card' किस भुगतान नेटवर्क पर आधारित है?

- A) Visa / वीज़ा
- B) Mastercard / मास्टरकार्ड
- C) American Express / अमेरिकन एक्सप्रेस
- D) RuPay / रुपये
- E) NPCI Card / एनपीसीआई कार्ड

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Axis Bank and Google Pay have jointly launched the 'Google Pay Flex Axis

Bank Credit Card’.

- एक्सिस बैंक और गूगल पे ने संयुक्त रूप से ‘Google Pay Flex Axis Bank Credit Card’ लॉन्च किया है।
- It is a UPI-enabled co-branded credit card built on the RuPay network.
- यह RuPay नेटवर्क पर आधारित UPI-सक्षम सहै। कार्ड क्रेडिट ब्रांडेड-
- The card allows users to make payments at millions of offline merchants as well as online apps.
- यह कार्ड उपयोगकर्ताओं को लाखों ऑफलाइन व्यापारियों और ऑनलाइन ऐप्स पर भुगतान करने की सुविधा देता है।
- Users can earn and instantly redeem reward points directly through Google Pay.
- उपयोगकर्ता गूगल पे के माध्यम से तुरंत रिवाँर्ड पॉइंट्स कमा और रिडीम कर सकते हैं।
- The card also offers easy and seamless repayment options via Google Pay.
- यह कार्ड गूगल पे के जरिए आसान और सुगम पुनर्भुगतान विकल्प भी प्रदान करता है।
- The launch further strengthens digital credit access in India through the UPI ecosystem.
- यह लॉन्च भारत में UPI इकोसिस्टम के माध्यम से डिजिटल क्रेडिट पहुंच को और मजबूत करता है।

Ques: What do the RBI’s final “Commercial Banks – Undertaking of Financial Services, 2025” guidelines primarily focus on?

आरबीआई के अंतिम “Commercial Banks – Undertaking of Financial Services, 2025” दिशानिर्देश मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हैं?

- A) Reducing lending rates / ऋण दरों में कटौती
- B) Easing bank group reorganisation with tighter compliance / बैंक समूह पुनर्गठन में लचीलापन और कड़ाई से अनुपालन
- C) Merging all NBFCs into banks / सभी एनबीएफसी को बैंकों में विलय
- D) Nationalising private banks / निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण
- E) Promoting digital-only banks / केवल डिजिटल बैंकों को बढ़ावा

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The RBI released the final guidelines titled “Commercial Banks – Undertaking of Financial Services, 2025” to provide flexibility in bank group reorganisation while strengthening compliance norms.
- आरबीआई ने “Commercial Banks – Undertaking of Financial Services, 2025” शीर्षक से अंतिम दिशानिर्देश जारी किए, ताकि बैंक समूह पुनर्गठन में लचीलापन प्रदान किया जा सके और अनुपालन मानदंड मजबूत किए जा सकें।
- The guidelines allow overlapping lending operations for bank group entities with board approval, preventing compulsory restructuring for around 12 major bank groups.
- दिशानिर्देशों के तहत बोर्ड की मंजूरी से बैंक समूह इकाइयों को ओवरलैपिंग लेंडिंग जारी रखने की अनुमति है, जिससे लगभग 12 प्रमुख बैंक समूहों के लिए अनिवार्य पुनर्गठन से बचाव होता है।
- RBI retained key restrictions across group entities, including upper-layer scale-based rules for NBFCs and a 20% ceiling on bank group shareholding in Asset Reconstruction Companies (ARCs).
- आरबीआई ने समूह इकाइयों पर प्रमुख प्रतिबंध बनाए रखा, जिसमें एनबीएफसी के लिए उच्च) कंपनियों रिकंस्ट्रक्शन एसेट और नियम आधारित पैमाना स्तरीय-ARC) में बैंक समूह हिस्सेदारी पर 20% सीमा शामिल है।
- Crisil noted that the final guidelines reduce operational disruption compared to the 2024 draft while ensuring continuity and compliance.
- क्रिसिल ने बताया कि अंतिम दिशानिर्देश 2024 ड्राफ्ट की तुलना में परिचालन में व्यवधान कम करते हैं और संचालन की निरंतरता तथा अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

Ques: The Securities Markets Code Bill, 2025 seeks to replace which of the following laws?

प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025 निम्न में से किन कानूनों को प्रतिस्थापित करना चाहता है?

- SEBI Act, 1992 / सेबी अधिनियम, 1992
- Depositories Act, 1996 / डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996
- Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 / प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956
- All of the above / उपरोक्त सभी
- Companies Act, 2013 / कंपनी अधिनियम, 2013

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Securities Markets Code Bill, 2025 in the Lok Sabha.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025 पेश किया।
- The Bill aims to consolidate and replace three existing securities laws into a single modern framework.
- यह विधेयक तीन मौजूदा प्रतिभूति कानूनों को एक एकीकृत और आधुनिक ढांचे में समाहित करने का लक्ष्य रखता है।
- The laws proposed to be repealed and subsumed are the SEBI Act, 1992, Depositories Act, 1996, and Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.
- जिन कानूनों को निरस्त कर नए विधेयक में शामिल किया जाएगा, वे हैं सेबी अधिनियम 1992, डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 और प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम (विनियमन) 1956।
- The objective of the Bill is to strengthen investor protection, improve ease of doing business, and enable efficient capital mobilisation.
- विधेयक का उद्देश्य निवेशक संरक्षण को मजबूत करना, व्यापार में सुगमता लाना और पूंजी जुटाने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है।
- It proposes decriminalisation of minor procedural violations by shifting them from criminal liability to civil penalties.
- इसमें छोटे प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाकर सिविल दंड में बदलने का प्रावधान किया गया है।
- The Bill also strengthens SEBI's governance with stricter conflict-of-interest disclosure norms.
- यह विधेयक हितों के टकराव से जुड़े कड़े प्रकटीकरण नियमों के माध्यम से सेबी के शासन ढांचे को मजबूत करता है।
- Additional provisions such as a specialised ombudsman and a regulatory sandbox are included to promote innovation in securities markets.
- प्रतिभूति बाजार में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष लोकपाल (Ombudsman) और रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जैसे प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

Ques: Airtel Payments Bank has partnered with which organisation to enable Electric Vehicle (EV) wallet recharge through Bharat Connect?

एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारत कनेक्ट के माध्यम से ईवी वॉलेट रिचार्ज सक्षम करने के लिए

किस संगठन के साथ साझेदारी की है?

- A) Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक
- B) National Payments Corporation of India (NPCI) / नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
- C) NPCI Bharat BillPay Limited (NBBL) / एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड
- D) Power Finance Corporation / पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन
- E) Energy Efficiency Services Limited / एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Airtel Payments Bank has partnered with NPCI Bharat BillPay Limited (NBBL), a wholly owned subsidiary of the National Payments Corporation of India (NPCI).
- एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NPCI भारत बिलपे लिमिटेड (NBBL) के साथ साझेदारी की है।
- This partnership enables users to recharge Electric Vehicle (EV) wallets through Bharat Connect, earlier known as the Bharat BillPay System (BBPS).
- इस साझेदारी के माध्यम से उपयोगकर्ता भारत कनेक्ट सिस्टम बिलपे भारत में पूर्व)– BBPS) के जरिए ईवी वॉलेट रिचार्ज कर सकते हैं।
- The initiative integrates the EV wallet recharge facility into the Airtel Thanks application.
- इस पहल के तहत ईवी वॉलेट रिचार्ज सुविधा को एयरटेल थैंक्स ऐप में एकीकृत किया गया है।
- The service is powered by the BBPS platform, expanding digital payment options for electric mobility users.
- यह सेवा BBPS प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित है, जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान विकल्पों का विस्तार हुआ है।

About Airtel Payments Bank :

- Established : 2017
- HQ : New Delhi
- MD & CEO : Anubrata Biswas

Ques: Which regional rural banks have been directed by the Ministry of Finance to prepare draft IPO plans by the end of March?

वित्त मंत्रालय ने किन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मार्च के अंत तक ड्राफ्ट IPO योजना तैयार करने का निर्देश दिया है?

- A) Punjab Gramin Bank, Karnataka Gramin Bank, Odisha Gramin Bank / पंजाब ग्रामीण बैंक, कर्नाटक ग्रामीण बैंक, ओडिशा ग्रामीण बैंक
- B) Haryana Gramin Bank, Kerala Gramin Bank, Tamil Nadu Grama Bank / हरियाणा ग्रामीण बैंक, केरल ग्रामीण बैंक, तमिलनाडु ग्राम बैंक
- C) Assam Gramin Bank, Bihar Gramin Bank, Jharkhand Gramin Bank / असम ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, झारखंड ग्रामीण बैंक
- D) Rajasthan Marudhara Gramin Bank, Baroda UP Bank, Aryavart Bank / राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक
- E) Maharashtra Gramin Bank, Andhra Pradesh Grameena Bank, Telangana Grameena Bank / महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Ministry of Finance has directed Haryana Gramin Bank, Kerala Gramin Bank and Tamil Nadu Grama Bank to prepare and submit draft Initial Public Offering (IPO) plans by the end of March.
- वित्त मंत्रालय ने हरियाणा ग्रामीण बैंक, केरल ग्रामीण बैंक और तमिलनाडु ग्राम बैंक को मार्च के अंत तक ड्राफ्ट IPO योजना तैयार कर जमा करने का निर्देश दिया है।
- Senior officials from these three banks and their respective sponsor institutions participated in the review process.
- इन तीनों बैंकों और उनके प्रायोजक संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में भाग लिया।
- The Centre aims to list at least five Regional Rural Banks (RRBs) over the next two financial years, with up to three potential listings planned for FY27.
- केंद्र सरकार अगले दो वित्तीय वर्षों में कम से कम पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचीबद्ध करने का लक्ष्य रखती है, जिनमें FY27 में तीन तक संभावित लिस्टिंग हो सकती हैं।
- This move follows the consolidation of RRBs from 43 to 28 under the 'One State, One RRB' initiative.
- यह कदम 'एक राज्य, एक RRB' पहल के तहत RRBs की संख्या 43 से घटाकर 28 किए जाने के बाद उठाया गया है।

- At present, the shareholding pattern of RRBs is 50% with the Central Government, 15% with State Governments and 35% with sponsor banks.
 - वर्तमान में RRBs की शेयरहोल्डिंग संरचना में केंद्र सरकार की 50%, राज्य सरकारों की 15% और प्रायोजक बैंकों की 35% हिस्सेदारी है।
-

Ques: Which bank launched the 'IDFC First Global Savings Account' for Non-Resident Indians, allowing them to hold earnings in USD and EUR?

किस बैंक ने अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए 'IDFC First Global Savings Account' लॉन्च किया है, जिसमें USD और EUR में कमाई रखी जा सकती है?

- A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- B) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- C) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- D) IDFC First Bank / आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
- E) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- IDFC First Bank has launched the 'IDFC First Global Savings Account' for Non-Resident Indians (NRIs).
- आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए 'IDFC First Global Savings Account' लॉन्च किया है।
- The account allows NRIs to hold their foreign currency earnings in United States Dollar (USD) and Euro (EUR).
- इस खाते के माध्यम से एनआरआई अपनी विदेशी मुद्रा आय को अमेरिकी डॉलर (USD) और यूरो (EUR) में रख सकते हैं।
- The account is offered through the International Financial Services Centre (IFSC) at GIFT City, Gandhinagar.
- यह खाता गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक (सिटी-GIFT City), गांधीनगर स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।
- Key features include zero fees on overseas transfers, interest rate of around 4.75% per annum on USD balances, and no minimum balance requirement.
- इसकी प्रमुख विशेषताओं में विदेशी ट्रांसफर पर शून्य शुल्क, USD बैलेंस पर लगभग 4.75%

वार्षिक ब्याज दर और न्यूनतम बैलेंस की कोई शर्त नहीं शामिल है।

- The account offers 100% repatriation of principal and interest to overseas accounts along with TDS exemption on interest earned.
- इस खाते में मूलधन और ब्याज की 100% विदेश में प्रत्यावर्तन सुविधा उपलब्ध है तथा अर्जित ब्याज पर TDS से छूट दी गई है।

About IDFC First Bank :

- Established : 2015
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : V Vaidyanathan
- Tagline : Always You First

Ques: Why did the Finance Ministry unveil a new logo for Regional Rural Banks (RRBs)?

वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के लिए नया लोगो क्यों लॉन्च किया?

- A) To reflect merger with public sector banks / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ विलय को दर्शाने के लिए
- B) To signify a single and unified brand identity for RRBs / RRBs की एकीकृत और समान ब्रांड पहचान को दर्शाने के लिए
- C) To mark the completion of 50 years of RRBs / RRBs के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में
- D) To promote digital-only banking in rural areas / ग्रामीण क्षेत्रों में केवल डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए
- E) To replace sponsor banks' logos / प्रायोजक बैंकों के लोगो को बदलने के लिए

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Finance Ministry unveiled a new logo for Regional Rural Banks (RRBs) to signify a single and unified brand identity across the country.
- वित्त मंत्रालय ने देशभर में RRBs की एक समान और एकीकृत ब्रांड पहचान को दर्शाने के लिए नया लोगो लॉन्च किया है।

- The colours of the logo reflect the objectives of RRBs — dark blue represents finance and trust, while green symbolises life and growth, highlighting their mission to serve rural India.
- लोगो के रंग RRBs के उद्देश्यों को दर्शाते हैं—गहरा नीला वित्त और विश्वास का प्रतीक है, जबकि हरा रंग जीवन और विकास को दर्शाता है, जो ग्रामीण भारत की सेवा के उनके मिशन को प्रतिबिंबित करता है।
- Under the 'One State, One RRB' principle, the Department of Financial Services has consolidated 15 Regional Rural Banks across 11 states and Union Territories, effective from May 1, 2025.
- 'एक राज्य, एक RRB' सिद्धांत के तहत वित्तीय सेवा विभाग ने 1 मई 2025 से 11 राज्यों में प्रदेशों शासित केंद्र/15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया है।
- At present, 28 RRBs continue to operate nationwide through a network of over 22,000 branches across more than 700 districts.
- वर्तमान में 28 RRBs देशभर में 700 से अधिक जिलों में फैली 22,000 से ज्यादा शाखाओं के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

Ques: Which bank launched a new advertising campaign featuring Sachin Tendulkar as its global brand ambassador?

सचिन तेंदुलकर को वैश्विक ब्रांड एंबेसडर के रूप में शामिल करते हुए किस बैंक ने नया विज्ञापन अभियान लॉन्च किया है?

- A) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- C) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- D) Canara Bank / केनरा बैंक
- E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option A

Explanation / व्याख्या:

- Bank of Baroda (BoB) has unveiled a new advertising campaign featuring Sachin Tendulkar as its global brand ambassador.
- बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने सचिन तेंदुलकर को अपना वैश्विक ब्रांड एंबेसडर बनाते हुए नया

विज्ञापन अभियान शुरू किया है।

- The campaign focuses on promoting four key retail banking products: Home Loans, Car Loans, MSME Loans through *bob Digi Udyam*, and the *bob Masterstroke Lite Savings Account*.
- यह अभियान चार प्रमुख रिटेल बैंकिंग उत्पादों—होम लोन, कार लोन, *bob Digi Udyam* के माध्यम से MSME लोन और *bob Masterstroke Lite* बचत खाता—को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- The campaign builds on last year's branding platform titled "Play The Masterstroke."
- यह अभियान पिछले वर्ष के ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म "Play The Masterstroke" पर आधारित है।
- Campaign teasers featured cricket commentator Jatin Sapru and media entrepreneur Kamiya Jani.
- अभियान के टीज़र में क्रिकेट कमेंटेटर जतिन सप्रू और मीडिया उद्यमी कामिया जानी को दिखाया गया।
- Bank of Baroda was founded in 1908 and is a public sector bank with 63.97% ownership held by the Government of India.
- बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई थी और यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसमें भारत सरकार की 63.97% हिस्सेदारी है।

Ques: Bank of India raised ₹2,500 crore through the issuance of which type of bonds?

बैंक ऑफ इंडिया ने ₹2,500 करोड़ किस प्रकार के बॉन्ड जारी करके जुटाए?

- A) Tier-1 Bonds – टियर-1 बॉन्ड
- B) Tier-2 Bonds – टियर-2 बॉन्ड
- C) Perpetual Bonds – परपेचुअल बॉन्ड
- D) Infrastructure Bonds – इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड
- E) None of these

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Bank of India raised ₹2,500 crore by issuing Tier-2 bonds with a 10-year maturity.

- बैंक ऑफ इंडिया ने 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले टियर-2 बॉन्ड जारी करके ₹2,500 करोड़ जुटाए।
- The total amount raised includes a ₹1,500 crore greenshoe option.
- जुटाई गई कुल राशि में ₹1,500 करोड़ का ग्रीनशू विकल्प शामिल है।
- Cut-off yield for the bond issue was set at 7.28%.
- इस बॉन्ड इश्यू के लिए कट यील्ड ऑफ-7.28% निर्धारित की गई।
- The bonds include a call option after 5 years, and the option can be exercised annually thereafter.
- इन बॉन्ड्स में 5 वर्षों के बाद कॉल ऑप्शन है, जिसे उसके बाद हर वर्ष प्रयोग किया जा सकता है।

Ques: Central Bank of India has entered into a Memorandum of Understanding (MoU) with which bank to build a strategic partnership for strengthening project financing capabilities in India?

भारत में परियोजना वित्तपोषण क्षमताओं को सुदृढ़ करने हेतु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- B) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- C) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- D) Canara Bank / केनरा बैंक
- E) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक

Answer: Option E

Explanation / व्याख्या:

- Central Bank of India has signed an MoU with State Bank of India (SBI) to establish a strategic partnership focused on enhancing leadership and institutional capabilities in project financing.
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने परियोजना वित्तपोषण में नेतृत्व और संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ एक रणनीतिक साझेदारी हेतु MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
- The collaboration aims to create new opportunities for co-financing of large infrastructure and development projects across India.

- यह सहयोग भारत भर में बड़े बुनियादी ढांचा एवं विकास परियोजनाओं के सह वित्तपोषण- (co-financing) के नए अवसर प्रदान करेगा।
- It will also support capacity building initiatives and facilitate the sharing of institutional knowledge and expertise between the two public sector banks.
- यह साझेदारी क्षमता निर्माण (capacity building) को बढ़ावा देने के साथ दोनों साथ-सक्षम भी को प्रदान-आदान के विशेषज्ञता और ज्ञान संस्थागत बीच के बैंकों के क्षेत्र सार्वजनिक बनाएगी।
- The MoU strengthens inter-bank cooperation to support India's long-term infrastructure financing needs.
- यह समझौता भारत की दीर्घकालिक अवसंरचना वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अंतरहै। करता सुदृढ़ को सहयोग बैंक-

About Central Bank of India :

- Established : 1911
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Kalyan Kumar
- Tagline : Central to you since 1911

Ques: Which authority directed IRDAI-regulated entities to adopt “1600” series phone numbers for service and transactional calls to consumers?

IRDAI द्वारा विनियमित संस्थाओं को सेवा एवं लेनदेन संबंधी कॉल के लिए “1600” सीरीज़ के फोन नंबर अपनाने का निर्देश किस प्राधिकरण ने दिया है?

- A) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
- B) Securities and Exchange Board of India / भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
- C) Telecom Regulatory Authority of India / भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
- D) Insurance Regulatory and Development Authority of India / बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
- E) Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), under the Ministry of Communications, directed all entities regulated by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) to adopt “1600” series phone numbers.
- संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने IRDAI द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं को “1600” सीरीज़ के फोन नंबर अपनाने का निर्देश दिया है।
- The directive applies to service and transactional calls made to consumers.
- यह निर्देश उपभोक्ताओं को की जाने वाली सेवा और लेनदेन संबंधी कॉल पर लागू होगा।
- The deadline for adopting the “1600” series numbers is 15 February 2026.
- “1600” सीरीज़ नंबर अपनाने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है।
- The objective is to help customers easily identify genuine calls from regulated financial institutions.
- इसका उद्देश्य ग्राहकों को विनियमित वित्तीय संस्थानों से आने वाली वास्तविक कॉल की पहचान करने में मदद करना है।
- The move will also assist consumers in distinguishing legitimate calls from spam or fraudulent calls.
- यह कदम उपभोक्ताओं को स्पैम या धोखाधड़ी वाली कॉल से वास्तविक कॉल को अलग पहचानने में भी सहायता करेगा।

About TRAI :

- Established : 1997
- HQ : New Delhi
- Chairperson : Anil Kumar Lahoti

Ques. What key relaxation has SEBI introduced for Non-Resident Indians (NRIs) regarding the re-KYC process?

SEBI ने NRI के लिए re-KYC प्रक्रिया में कौन है दी छूट प्रमुख सी-?

- A) Physical presence in India is no longer required for digital re-KYC / डिजिटल re-KYC के लिए भारत में शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक नहीं
- B) New NRI clients can complete onboarding from abroad / नए NRI ग्राहक विदेश से ही ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं
- C) Geo-tagging and time-stamping are no longer mandatory / जियो और टैगिंग-

नहीं अनिवार्य अब स्टैम्पिंग-टाइम

D) Digital KYC apps can allow spoofed IP addresses / डिजिटल KYC ऐप स्पूफ़ड IP को अनुमति दे सकते हैं

E) Re-KYC norms have been withdrawn completely / re-KYC नियम पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- SEBI has eased the re-KYC process for existing NRI clients by removing the requirement of being physically present in India during digital re-KYC.
- SEBI ने मौजूदा NRI ग्राहकों के लिए डिजिटल re-KYC के दौरान भारत में शारीरिक रूप से उपस्थित रहने की अनिवार्यता हटा दी है।
- This relaxation applies only to re-KYC and not to digital onboarding of new NRI clients, which still requires presence in India.
- यह छूट केवल re-KYC पर लागू होती है; नए NRI ग्राहकों की डिजिटल ऑनबोर्डिंग के लिए भारत में मौजूद होना अब भी जरूरी है।
- Digital safeguards such as random prompts, geo-tagging, time-stamping, GPS location matching, and IP spoofing checks remain mandatory.
- रैंडम प्रॉम्प्ट, जियोटैगिंग-, टाइमस्टैम्पिंग-, GPS लोकेशन मिलान और IP स्पूफिंग रोकने जैसे डिजिटल सुरक्षा उपाय यथावत रहेंगे।
- The objective is to make the re-KYC process smoother, more accessible, and user-friendly for NRIs living abroad.
- इसका उद्देश्य विदेश में रहने वाले NRI के लिए re-KYC प्रक्रिया को सरल, सुलभ और उपयोगकर्ता है। बनाना अनुकूल-

Ques: SEBI has approved which fintech platform as an Online Bond Platform Provider (OBPP)?

सेबी ने किस फिनटेक प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर (OBPP) के रूप में मंजूरी दी है?

- A) Zerodha / ज़ेरोधा
- B) Paytm Money / पेटीएम मनी
- C) Groww / ग्रो

- D) Upstox / अपस्टॉक्स
- E) Angel One / एंजेल वन

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has approved Groww as an Online Bond Platform Provider (OBPP).
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) ने Groww को ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर (OBPP) के रूप में मंजूरी दी है।
 - With this approval, Groww can list, distribute, and facilitate transactions of listed corporate bonds on its app.
 - इस मंजूरी के बाद Groww अपने ऐप पर सूचीबद्ध कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की लिस्टिंग, वितरण और लेनसकेगा। कर प्रदान सुविधा की देन-
 - The platform will offer SEBI-regulated and secure access to fixed-income investment products.
 - यह प्लेटफॉर्म SEBI-नियमित और सुरक्षित तरीके से फिक्स्ड उपलब्ध विकल्प निवेश इनकम-कराएगा।
 - Corporate bonds will now be available alongside Groww's existing offerings such as stocks, mutual funds, and other market-linked instruments.
 - अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, Groww के मौजूदा निवेश विकल्पों—जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और अन्य मार्केटइंस्ट्रूमेंट्स लिंकड—के साथ उपलब्ध होंगे।
 - The move makes bond investing simpler and more accessible for retail investors, supports portfolio diversification, and provides access to relatively stable, lower-risk returns.
 - यह कदम रिटेल निवेशकों के लिए बॉन्ड निवेश को आसान बनाता है, पोर्टफोलियो विविधीकरण में मदद करता है और अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले स्थिर रिटर्न तक पहुँच प्रदान करता है।
-

Ques: Which life insurance company introduced a new brand identity with the promise “Har Wada Mumkin – Promises Made Possible”?

“हर वादा मुमकिन – Promises Made Possible” के वादे के साथ किस जीवन बीमा कंपनी ने नई ब्रांड पहचान पेश की है?

- A) HDFC Life Insurance / एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस
- B) ICICI Prudential Life Insurance / आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस
- C) Ageas Federal Life Insurance / एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस
- D) SBI Life Insurance / एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस
- E) Max Life Insurance / मैक्स लाइफ इंश्योरेंस

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Ageas Federal Life Insurance has unveiled a new brand identity with the promise “Har Wada Mumkin – Promises Made Possible.”
- एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने “हर वादा मुमकिन – Promises Made Possible” के वादे के साथ अपनी नई ब्रांड पहचान प्रस्तुत की है।
- The rebranding was launched in Mumbai by Managing Director & CEO Jude Gomes along with brand ambassador Sachin Tendulkar.
- यह रीब्रांडिंग मुंबई में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ जूड गोम्स द्वारा ब्रांड एंबेसडर सचिन तेंदुलकर के साथ लॉन्च की गई।
- The new logo features two unifying arcs symbolising protection and guidance.
- नए लोगो में दो एकीकृत आर्क (arcs) हैं, जो सुरक्षा और मार्गदर्शन का प्रतीक हैं।
- The colour palette reflects key values: orange represents optimism, while violet signifies trust.
- रंग योजना में नारंगी रंग आशावाद (optimism) और बैंगनी रंग विश्वास (trust) को दर्शाता है।
- The rebrand aims to simplify insurance and expand access to financial protection across India.
- इस नई पहचान का उद्देश्य बीमा को सरल बनाना और पूरे भारत में वित्तीय सुरक्षा की पहुँच को बढ़ाना है।
- Ageas Federal Life Insurance is a joint venture between Ageas Group and Federal Bank and has been operational since 2008.
- एजियस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस, एजियस ग्रुप और फेडरल बैंक का संयुक्त उद्यम है और यह 2008 से परिचालन में है।

Ques: The Reserve Bank of India (RBI) imposed a monetary penalty of ₹61.95 lakh on which bank for regulatory violations?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नियामकीय उल्लंघनों के लिए ₹61.95 लाख का जुर्माना किस बैंक पर लगाया है?

- A) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- B) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- D) Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक
- E) IndusInd Bank / इंडसइंड बैंक

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) imposed a penalty of ₹61.95 lakh on Kotak Mahindra Bank for non-compliance with certain regulatory guidelines.
 - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कुछ नियामकीय दिशानिर्देशों का पालन न करने पर कोटक महिंद्रा बैंक पर ₹61.95 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है।
 - The penalty relates to violations in three key areas.
 - यह जुर्माना तीन प्रमुख क्षेत्रों में उल्लंघनों से संबंधित है।
 - These include non-compliance related to Basic Savings Bank Deposit (BSBD) accounts.
 - इसमें बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खातों से जुड़े उल्लंघन शामिल हैं।
 - Irregularities in the functioning of Business Correspondents (BCs) were also observed.
 - बिज़नेस करेस्पॉन्डेंट्स (BCs) के संचालन में अनियमितताएँ पाई गईं।
 - The bank also failed to comply with norms related to reporting to Credit Information Companies (CICs).
 - इसके अलावा क्रेडिट सूचना कंपनियों (CICs) को रिपोर्टिंग से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया गया।
-

Ques: Which bank has underwritten a \$500 million, 5-year foreign currency term loan for OVL Overseas IFSC Limited (OOIL)?

OVL ओवरसीज IFSC लिमिटेड (OOIL) के लिए 5 वर्ष की अवधि का 500 मिलियन अमेरिकी

डॉलर का विदेशी मुद्रा टर्म लोन किस बैंक ने अंडरराइट किया है?

- A) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
- B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- C) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- D) Canara Bank / केनरा बैंक
- E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Bank of Baroda (BoB) has underwritten a \$500 million, 5-year foreign currency term loan for OVL Overseas IFSC Limited (OOIL).
 - बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने OVL ओवरसीज IFSC लिमिटेड (OOIL) के लिए 5 वर्षों की अवधि का 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा टर्म लोन अंडरराइट किया है।
 - OOIL is a wholly owned subsidiary of ONGC Videsh Limited (OVL) and is registered in GIFT City, Gujarat.
 - OOIL, ONGC विदेश लिमिटेड (OVL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और गुजरात के GIFT सिटी में पंजीकृत है।
 - Bank of Baroda acted as the Sole Mandated Lead Arranger (SMLA) for the loan.
 - इस ऋण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने सोल मैंडेटेड लीड अरेंजर (SMLA) की भूमिका निभाई।
 - The transaction highlights Bank of Baroda's capability and strength in syndicated foreign currency lending.
 - यह लेनदेन सिंडिकेटेड विदेशी मुद्रा ऋण व्यवस्था में बैंक ऑफ बड़ौदा की क्षमता और मजबूती को दर्शाता है।
-

Ques: Who has been appointed as the Non-Executive Chairman of the Board of IIFL Finance Limited?

आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के बोर्ड के गैर नियुक्त किसे में रूप के अध्यक्ष कार्यकारी-गया किया है?

- A) Shaktikanta Das / शक्तिकांत दास

- B) Urjit Patel / उर्जित पटेल
C) Bibhu Prasad (BP) Kanungo / बिभु प्रसाद कानूनगो (बीपी)
D) Viral Acharya / वायरल आचार्य
E) Raghuram Rajan / रघुराम राजन

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Bibhu Prasad (BP) Kanungo, former Deputy Governor of the Reserve Bank of India (RBI), has been appointed as the Non-Executive Chairman of the Board of IIFL Finance Limited.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पूर्व उप को कानूनगो (बीपी) प्रसाद बिभु गवर्नर-लिमिटेड फाइनेंस आईआईएफएलड के बोर्ड का गैर है। गया किया नियुक्त अध्यक्ष कार्यकारी-
- Kanungo served as Deputy Governor of the RBI from 2017 to 2021.
- कानूनगो ने 2017 से 2021 तक RBI के उपक्रिया। कार्य में रूप के गवर्नर-
- He was also a member of the Monetary Policy Committee (MPC).
- वह मौद्रिक नीति समिति (MPC) के सदस्य भी रह चुके हैं।
- IIFL Finance Limited was established in 1995 and is headquartered in Mumbai.
- आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।

Ques: Which digital payments platform has launched UPI Biometric Authentication, allowing users to approve transactions using fingerprint or face scan without entering a PIN?

फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन के माध्यम से बिना पिन डाले यूपीआई लेनदेन की सुविधा किस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ने शुरू की है?

- A) Google Pay / गूगल पे
B) PhonePe / फोनपे
C) Paytm / पेटीएम
D) Amazon Pay / अमेज़न पे
E) BHIM / भीम

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Amazon Pay has launched UPI Biometric Authentication, enabling users to approve UPI transactions using fingerprint or face scan instead of entering a UPI PIN.
- अमेज़न पे ने यूपीआई बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की शुरुआत की है, जिससे उपयोगकर्ता फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन के जरिए बिना पिन डाले भुगतान कर सकते हैं।
- Amazon Pay is among the first payment service providers in India to introduce biometric-based authentication for UPI payments.
- अमेज़न पे भारत में यूपीआई भुगतान के लिए बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण शुरू करने वाले शुरुआती पेमेंट सेवा प्रदाताओं में शामिल है।
- The biometric authentication feature is available for transactions of up to ₹5,000 across Amazon Pay UPI services.
- यह बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सुविधा अमेज़न पे यूपीआई सेवाओं के तहत ₹5,000 तक के लेनदेन के लिए उपलब्ध है।
- The move aims to enhance security, convenience, and ease of use for UPI customers.
- इस पहल का उद्देश्य यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा, सुविधा और उपयोग में आसानी को बढ़ाना है।

Ques: According to the Periodic Labour Force Survey (PLFS) Monthly Bulletin for November 2025, what was the unemployment rate among persons aged 15 years and above in India?

पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के नवंबर 2025 बुलेटिन के अनुसार, भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोज़गारी दर क्या थी?

- A) 5.1%
- B) 4.9%
- C) 4.7%
- D) 4.5%
- E) 6.0%

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- The National Statistical Office (NSO), under the Ministry of Statistics and Programme Implementation, released the PLFS Monthly Bulletin for November 2025.
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने नवंबर 2025 के लिए PLFS मासिक बुलेटिन जारी किया।
- As per the report, the unemployment rate among persons aged 15 years and above declined to 4.7% in November 2025.
- रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में बेरोज़गारी दर घटकर 4.7% रह गई।
- This was the lowest unemployment rate recorded since April 2025, when it stood at 5.1%.
- यह अप्रैल 2025 (5.1%) के बाद दर्ज की गई सबसे कम बेरोज़गारी दर है।
- The report showed that rural unemployment rate fell to a new low of 3.9%, while urban unemployment rate declined to 6.5%.
- रिपोर्ट में बताया गया कि ग्रामीण बेरोज़गारी दर घटकर 3.9% के नए निचले स्तर पर आ गई, जबकि शहरी बेरोज़गारी दर 6.5% हो गई।

Ques: Which digital payments firm received the final Payment Aggregator (PA) licence from the Reserve Bank of India to offer both online and offline merchant payment acceptance under a single regulatory framework?

किस डिजिटल पेमेंट्स कंपनी को एकल नियामक ढांचे के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेन्ट भुगतान स्वीकार करने के लिए RBI से अंतिम पेमेंट एग्रीगेटर (PA) लाइसेंस प्राप्त हुआ?

- A) PayU / पेयू
- B) Razorpay / रेज़रपे
- C) Pine Labs / पाइन लैब्स
- D) Mswipe Technologies / एमस्वाइप टेक्नोलॉजीज
- E) Easebuzz / ईज़बज़

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- Digital payments firm Mswipe Technologies Private Limited received the final Payment Aggregator licence from the Reserve Bank of India.
- डिजिटल पेमेंट्स कंपनी एमस्वाइप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक से अंतिम पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त हुआ।
- The licence allows Mswipe to offer both online and offline merchant payment acceptance under a single regulatory framework.
- यह लाइसेंस एमस्वाइप को एक ही नियामक ढांचे के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेन्ट भुगतान सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है।
- Mswipe also holds an in-principle Prepaid Payment Instrument (PPI) licence and a Non-Banking Financial Company (NBFC) licence obtained in 2022.
- एमस्वाइप के पास 2022 में प्राप्त इन) इंस्ट्रूमेंट पेमेंट प्रीपेड प्रिंसिपल-PPI) लाइसेंस और नॉन) कंपनी फाइनेंशियल बैंकिंग-NBFC) लाइसेंस भी है।
- With this approval, Mswipe joins a select group of fully authorised payment aggregators such as Paytm, Razorpay, Pine Labs, Easebuzz, PayU, and Airpay.
- इस मंजूरी के साथ, एमस्वाइप पूरी तरह अधिकृत पेमेंट एग्रीगेटर्स के चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है, जिसमें Paytm, Razorpay, Pine Labs, Easebuzz, PayU और Airpay शामिल हैं।

Ques: The Reserve Bank of India (RBI) imposed regulatory restrictions on which two Urban Cooperative Banks (UCBs)?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने किन दो शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) पर नियामकीय प्रतिबंध लगाए हैं?

- A) Mumbai District Central Co-op Bank & Surat Mercantile Co-op Bank
- B) Gauhati Cooperative Urban Bank (Assam) & Valsad Mahila Nagrik Sahakari Bank (Gujarat)
- C) PMC Bank & Cosmos Cooperative Bank
- D) Ahmedabad Mercantile Co-op Bank & Shamrao Vithal Co-op Bank
- E) Nashik Merchants Co-op Bank & Kolhapur Urban Bank

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) imposed regulatory restrictions on two Urban

Cooperative Banks—The Gauhati Cooperative Urban Bank Limited in Assam and The Valsad Mahila Nagrik Sahakari Bank Limited in Gujarat.

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने दो शहरी सहकारी बैंकों—असम स्थित गौहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड और गुजरात स्थित वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड—पर नियामकीय प्रतिबंध लगाए हैं।

• The restrictions were issued in the form of 'Directions' under the Banking Regulation (BR) Act, 1949, and will remain in force for six months, subject to review.

• ये प्रतिबंध बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत 'Directions' के रूप में जारी किए गए हैं और समीक्षा के अधीन छह महीनों तक प्रभावी रहेंगे।

About Directions on Gauhati Cooperative Urban Bank / गौहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक:

• Directions came into effect from the close of business on December 17, 2025.

• निर्देश 17 दिसंबर 2025 को व्यवसाय समाप्ति के बाद से प्रभावी हुए।

• Depositors are allowed to withdraw up to ₹35,000 across all deposit accounts; the bank may adjust outstanding loans against deposits.

• जमाकर्ता सभी जमा खातों से कुल मिलाकर ₹35,000 तक की निकासी कर सकते हैं; बैंक बकाया ऋण को जमा के विरुद्ध समायोजित कर सकता है।

About Directions on Valsad Mahila Nagrik Sahakari Bank / वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक:

• Directions came into effect from the close of business on December 18, 2025.

• निर्देश 18 दिसंबर 2025 को व्यवसाय समाप्ति के बाद से लागू हुए।

• No withdrawals are permitted from any deposit accounts; however, the bank may adjust outstanding loans against deposits as per RBI conditions.

• किसी भी जमा खाते से कोई निकासी अनुमत नहीं है; हालांकि RBI की शर्तों के अनुसार बकाया ऋण को जमा के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।

Ques: Which bank launched the IndusInd Bank Jio-bp Mobility+ Credit Card on the RuPay network in December 2025?

दिसंबर 2025 में RuPay नेटवर्क पर IndusInd Bank Jio-bp Mobility+ क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया?

- A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C) Axis Bank / एक्सिस बैंक
- D) IndusInd Bank / इंडसइंड बैंक
- E) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- The IndusInd Bank Jio-bp Mobility+ Credit Card was launched on 10 December 2025.
- इंडसइंड बैंक जियो कार्ड क्रेडिट +मोबिलिटी बीपी-10 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया।
- The card is issued by IndusInd Bank Limited, a private sector bank.
- यह कार्ड निजी क्षेत्र के बैंक इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है।
- The card is launched in partnership with Jio-bp.
- यह कार्ड जियो है। गया किया लॉन्च में साझेदारी साथ के बीपी-
- Jio-bp is a joint venture between Reliance's Jio and bp (British Petroleum).
- जियोबीपी-, रिलायंस जियो और बीपी है। उद्यम संयुक्त का (पेट्रोलियम ब्रिटिश)
- It is the first fuel-centric credit card launched by IndusInd Bank. It is also the first co-branded credit card of Jio-bp.
- यह इंडसइंड बैंक का पहला ईंधन है। कार्ड क्रेडिट केंद्रित-यह जियो-को पहला का बीपी-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी है।

Ques: Which foreign bank has agreed to invest ₹39,618 crore in Shriram Finance Limited (SFL), marking the largest-ever FDI in India's financial services sector?

किस विदेशी बैंक ने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (SFL) में ₹39,618 करोड़ का निवेश करने पर सहमति दी है, जो भारत के वित्तीय सेवा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा FDI है?

- A) HSBC Bank / एचएसबीसी बैंक

- B) Standard Chartered Bank / स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
- C) MUFG Bank Limited / एमयूएफजी बैंक लिमिटेड
- D) DBS Bank / डीबीएस बैंक
- E) Sumitomo Mitsui Banking Corporation / सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Shriram Finance Limited (SFL) entered into a definitive agreement with MUFG Bank Limited for an investment of ₹39,618 crore (USD 4.4 billion).
- श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड ने MUFG बैंक लिमिटेड के साथ ₹39,618 करोड़)USD 4.4 बिलियन है। किया समझौता निश्चित लिए के निवेश के (
- The investment will be made through a preferential issuance of equity shares.
- यह निवेश इक्विटी शेयरों के प्रेफरेंशियल इश्यू के माध्यम से किया जाएगा।
- This transaction is the largest-ever foreign direct investment (FDI) in India's financial services sector.
- यह भारत के वित्तीय सेवा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश)FDI) है।
- After the investment, MUFG Bank will acquire a 20% stake in Shriram Finance Limited.
- निवेश के बाद MUFG बैंक को श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड में 20% हिस्सेदारी प्राप्त होगी।

About Shriram Finance Limited :

- Established : 1979
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Parag Sharma

Ques: Which ministry announced measures to strengthen and streamline the grievance redressal mechanism in the BFSI sector?

BFSI क्षेत्र में शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत और सुव्यवस्थित करने की घोषणा किस मंत्रालय ने की?

- A) Ministry of Corporate Affairs / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

- B) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- C) Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय
- D) Ministry of Consumer Affairs / उपभोक्ता कार्य मंत्रालय
- E) Ministry of Electronics and IT / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- The Ministry of Finance announced measures to strengthen grievance redressal in the BFSI sector.
 - वित्त मंत्रालय ने BFSI क्षेत्र में शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत करने की घोषणा की।
 - BFSI stands for Banking, Financial Services and Insurance.
 - BFSI का अर्थ है बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा।
 - The main objective is to strengthen and streamline grievance redressal mechanisms and enable citizens to directly raise concerns against BFSI entities.
 - इसका मुख्य उद्देश्य शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाना और नागरिकों को BFSI संस्थानों के खिलाफ सीधे शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाना है।
 - All banks have been directed to develop technology-based customer feedback systems.
 - सभी बैंकों को प्रौद्योगिकी आधारित ग्राहक फीडबैक प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया गया है।
 - Feedback collection modes include voice chat, email, QR (Quick Response) codes, and other digital tools.
 - फीडबैक संग्रह के माध्यमों में वॉइस चैट, ईमेल, क्यूआर कोड और अन्य डिजिटल टूल शामिल हैं।
 - Special focus has been placed on ensuring high-quality customer service delivery at Public Sector Bank (PSB) branches.
 - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) की शाखाओं में उच्च गुणवत्ता वाली ग्राहक सेवा पर विशेष ध्यान दिया गया है।
-

Ques: According to the Worldline India report, what was the transaction volume of India's Unified Payments Interface (UPI) in Q3 2025?

Worldline India रिपोर्ट के अनुसार, Q3 2025 में भारत के UPI लेनदेन की संख्या कितनी रही?

- A) 42.15 billion
- B) 48.90 billion
- C) 52.60 billion
- D) 59.33 billion
- E) 65.75 billion

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- India's UPI transaction volume reached 59.33 billion in Q3 2025, registering a year-on-year (YoY) growth of 33.5%, as per the Worldline India report.
 - Worldline India रिपोर्ट के अनुसार, Q3 2025 में भारत के UPI लेनदेन की संख्या 59.33 बिलियन रही, जो 33.5% की वार्षिक वृद्धि दर्शाती है।
 - The total value of UPI transactions increased by 21% YoY to ₹74.84 trillion, reflecting sustained growth in digital payments.
 - UPI लेनदेन का कुल मूल्य 21% की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹74.84 ट्रिलियन तक पहुँच गया, जो डिजिटल भुगतान में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है।
 - India recorded 709 million active UPI QR codes, marking a 21% increase since July 2024.
 - भारत में 709 मिलियन सक्रिय UPI QR कोड दर्ज किए गए, जो जुलाई 2024 से 21% की वृद्धि को दर्शाता है।
 - The Average Ticket Size (ATS) of UPI transactions declined to ₹1,262.
 - UPI लेनदेन का औसत टिकट आकार (ATS) घटकर ₹1,262 हो गया।
 - The decline in ATS indicates increased usage of UPI for low-value, everyday transactions such as tea, vegetables, and bus tickets.
 - ATS में गिरावट यह दर्शाती है कि UPI का उपयोग चाय, सब्ज़ी और बस टिकट जैसे छोटे दैनिक भुगतानों के लिए अधिक हो रहा है।
-

Ques: Which bank has launched the RuPay SIB Paytag, a contactless NFC-enabled payment sticker for tap-and-pay transactions?

किस बैंक ने टैप संपर्करहित लिए के लेनदेन पे-एंड-NFC** आधारित RuPay SIB Paytag लॉन्च किया है?**

- A) Federal Bank / फेडरल बैंक

- B) South Indian Bank / साउथ इंडियन बैंक
- C) Karnataka Bank / कर्नाटक बैंक
- D) City Union Bank / सिटी यूनियन बैंक
- E) Karur Vysya Bank / करूर वैश्य बैंक

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- South Indian Bank has launched the RuPay SIB Paytag, a contactless NFC-enabled payment sticker/device.
- साउथ इंडियन बैंक ने संपर्करहित NFC आधारित भुगतान स्टिकर डिवाइस/RuPay SIB Paytag लॉन्च किया है।
- The product allows customers to make tap-and-pay transactions at Point-of-Sale (POS) terminals without carrying a physical debit card.
- यह उत्पाद ग्राहकों को बिना भौतिक डेबिट कार्ड के POS टर्मिनलों पर टैप भुगतान पे-एंड-करनेकी सुविधा देता है।
- The Paytag uses Near Field Communication (NFC) technology for quick and secure payments.
- Paytag तेज़ और सुरक्षित भुगतान के लिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) तकनीक का उपयोग करता है।
- No PIN is required for contactless transactions up to ₹5,000.
- ₹5,000 तक के संपर्करहित लेनदेन के लिए PIN की आवश्यकता नहीं होती।
- For payments above ₹5,000 and up to ₹1,00,000 on POS terminals or online platforms, Personal Identification Number (PIN) authentication is mandatory.
- ₹5,000 से अधिक और ₹1,00,000 तक के POS या ऑनलाइन भुगतान के लिए PIN प्रमाणीकरण अनिवार्य है।

About South Indian Bank :

- Established : 1929
- HQ : Thrissur, Kerala
- MD & CEO : P R Seshadri
- Tagline : Experience Next Generation Banking

Ques: By how much did India's foreign exchange reserves increase in the latest data released by the RBI?

RBI द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी वृद्धि हुई?

- A) USD 1.03 billion
- B) USD 0.89 billion
- C) USD 0.75 billion
- D) USD 1.25 billion
- E) USD 1.50 billion

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- India's foreign exchange reserves increased by USD 1.03 billion, taking the total reserves to USD 687.26 billion. The data was released by the Reserve Bank of India (RBI).
- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 1.03 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई, जिससे कुल भंडार 687.26 अरब डॉलर हो गया। यह आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए गए।
- The increase followed a decline in the previous week, indicating a balanced recovery in forex reserves.
- यह वृद्धि पिछले सप्ताह की गिरावट के बाद दर्ज की गई, जो संतुलित सुधार को दर्शाती है।
- Foreign Currency Assets (FCA) remained the largest component of India's forex reserves.
- विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (FCA) भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा बनी रहीं।
- Changes in FCA are mainly due to valuation effects arising from movements in the Euro, Pound Sterling, and Japanese Yen against the US Dollar.
- FCA में बदलाव मुख्य रूप से यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और जापानी येन की अमेरिकी डॉलर के मुकाबले विनिमय दर में उतार हैं। होते कारण के चढ़ाव-
- The rise in reserves was primarily supported by an increase in gold reserves and gains in Special Drawing Rights (SDRs).
- भंडार में वृद्धि मुख्य रूप से स्वर्ण भंडार और विशेष आहरण अधिकार (SDR) में बढ़ोतरी के कारण हुई।
- India's forex reserves include Foreign Currency Assets (FCA), Gold Reserves, Special Drawing Rights (SDRs), and the RBI's reserve position with the International Monetary Fund (IMF).

- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (FCA), स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार (SDR) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ RBI की आरक्षित स्थिति शामिल होती है।

**Ques: Canara ai1Pe, recently in news, is launched by which bank?
हाल ही में समाचारों में रहा Canara ai1Pe किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है?**

- A) State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- C) Canara Bank / केनरा बैंक
- D) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Canara ai1Pe has been launched by Canara Bank.
- Canara ai1Pe को केनरा बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है।
- It allows users to link savings or current accounts from any bank to make and receive UPI payments.
- यह उपयोगकर्ताओं को किसी भी बैंक के बचत या चालू खाते को लिंक करके UPI भुगतान करने और प्राप्त करने की सुविधा देता है।

About Canara Bank :

- Established : 1906
- HQ : Bengaluru
- MD & CEO : K Satyanarayana Raju
- Tagline : Together We Can

Ques: Which bank launched the 'Digital Merchant Cash Advance Loans' for MSMEs in India?

भारत में MSMEs के लिए 'Digital Merchant Cash Advance Loans' किस बैंक ने लॉन्च

किया?

- A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C) Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक
- D) SBI / एसबीआई
- E) Axis Bank / एक्सिस बैंक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Axis Bank Limited, a leading private sector lender in India, launched a new digital loan product called 'Digital Merchant Cash Advance Loans' for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).
- भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक लिमिटेड ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) के लिए 'Digital Merchant Cash Advance Loans' नामक नया डिजिटल लोन उत्पाद लॉन्च किया।
- The product is designed to meet the cash flow requirements of small merchants, offering an unsecured credit facility ranging from Rs 2 lakh to Rs 20 lakh.
- यह उत्पाद छोटे व्यापारियों की नकदी प्रवाह आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो 2 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की अनसिक्योर्ड क्रेडिट सुविधा प्रदान करता है।
- The loan features an Everyday Installment (EDI) system for flexible repayment.
- इस लोन में लचीले पुनर्भुगतान के लिए Everyday Installment (EDI) सिस्टम की सुविधा है।

About Axis Bank :

- Established : 1993
- HQ : Mumbai, Maharashtra
- Chairman : Rakesh Makhija
- MD & CEO : Amitabh Chaudhary
- Tagline : Badhti Ka naam Zindagi

Ques: Who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer (MD & CEO) of Canara Bank?

कनारा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) K Satyanarayana Raju / केराजू सत्यनारायण .
- B) Brajesh Kumar Singh / ब्रजेश कुमार सिंह
- C) Bhanu Pratap Sharma / भानु प्रताप शर्मा
- D) Atanu Kumar Das / अतनु कुमार दास
- E) Rajneesh Karnatak / रजनीश कर्नाटक

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Brajesh Kumar Singh has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer (MD & CEO) of Canara Bank.
- ब्रजेश कुमार सिंह को कनारा बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- He has replaced K. Satyanarayana Raju in this position.
- उन्होंने के.स. राजू सत्यनारायण .
- Prior to this appointment, Brajesh Kumar Singh was serving as an Executive Director at the state-owned Indian Bank.
- इस नियुक्ति से पहले ब्रजेश कुमार सिंह सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे।
- The appointment was made based on the recommendation of the Financial Services Institutions Bureau (FSIB).
- यह नियुक्ति वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) की सिफारिश पर की गई है।
- The Financial Services Institutions Bureau (FSIB) is responsible for selecting the chiefs of public sector banks and insurance companies. The Chairman of FSIB is Bhanu Pratap Sharma.
- वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रमुखों का चयन करता है। FSIB के अध्यक्ष भानु प्रताप शर्मा हैं।

Ques: Which fintech company received the TPAP license from NPCI to offer UPI services through its platform?

कौन सी फिनटेक कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से UPI सेवाएँ प्रदान करने के लिए NPCI से TPAP लाइसेंस मिला?

- A) Paytm / पेटीएम
- B) PayNearby / पेनियरबाय
- C) PhonePe / फोनपे
- D) Google Pay / गूगल पे
- E) BharatPe / भारतपे

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- PayNearby, a leading Indian fintech company, secured the Third-Party Application Provider (TPAP) license from the National Payments Corporation of India (NPCI), enabling it to offer Unified Payments Interface (UPI) services directly through its own platform.
 - प्रमुख भारतीय फिनटेक कंपनी PayNearby को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) से थर्ड प्रोवाइडर एप्लिकेशन पार्टि-TPAP) लाइसेंस मिला, जिससे यह अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे UPI सेवाएँ प्रदान कर सके।
 - Following NPCI's approval, the company launched the 'PayNearby Saathi' application.
 - NPCI की मंजूरी मिलने के बाद कंपनी ने 'PayNearby Saathi' ऐप लॉन्च किया।
 - The app integrates BHASHINI, the Government of India-supported AI-driven speech technology platform, allowing users to interact in their preferred language, raise queries, and receive instant responses.
 - इस ऐप में BHASHINI को जोड़ा गया है, जो भारत सरकार द्वारा समर्थित AI-संचालित स्पीच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी पसंदीदा भाषा में संवाद कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और तुरंत उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।
-

Ques: Paytm Cloud Technologies Ltd (PCTL) has approved the incorporation of step-down wholly owned subsidiaries in which countries?

Paytm Cloud Technologies Ltd (PCTL) ने किन देशों में स्टेप वाली स्वामित्व पूर्ण डाउन-

है दी मंजूरी को गठन के कंपनियों सहायक?

- A) Singapore and UAE / सिंगापुर और यूएई
- B) Indonesia and Luxembourg / इंडोनेशिया और लक्ज़मबर्ग
- C) UK and Germany / यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी
- D) Indonesia and Singapore / इंडोनेशिया और सिंगापुर
- E) Luxembourg and France / लक्ज़मबर्ग और फ्रांस

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Paytm Cloud Technologies Ltd (PCTL), a wholly owned subsidiary of One97 Communications, has approved the incorporation of two step-down wholly owned subsidiaries in Indonesia and Luxembourg.
- वन97 कम्युनिकेशंस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Paytm Cloud Technologies Ltd (PCTL) ने इंडोनेशिया और लक्ज़मबर्ग में दो स्टेप स्वामित्व पूर्ण डाउन-है। दी मंजूरी को गठन के कंपनियों सहायक वाली
- Up to Rs 25 crore will be invested in each subsidiary, either in one or two tranches.
- प्रत्येक सहायक कंपनी में एक या दो चरणों में अधिकतम 25 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
- The transaction is expected to be completed by February 28, 2026.
- यह लेन देन-28 फरवरी 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।
- Separately, Paytm is diluting its stake in Paytm Arab Payments LLC, its UAE-based subsidiary, through a strategic investment by Abbar Global Opportunities Holdings.
- इसके अलावा, Paytm अपनी यूएई स्थित सहायक कंपनी Paytm Arab Payments LLC में हिस्सेदारी घटा रहा है, जिसमें Abbar Global Opportunities Holdings द्वारा रणनीतिक निवेश किया जा रहा है।

Ques: How much liquidity will the RBI inject into the banking system through OMOs and forex buy-sell swaps?

RBI OMOs और विदेशी मुद्रा खरीद कितनी में प्रणाली बैंकिंग से माध्यम के स्वैप बिक्री-है वाला डालने तरलता?

- A) ₹1 trillion
- B) ₹2 trillion
- C) ₹3 trillion
- D) ₹4 trillion
- E) ₹5 trillion

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) announced a fresh round of liquidity measures, including open-market operations (OMOs) and a foreign exchange buy-sell swap, to inject nearly ₹3 trillion into the banking system.
 - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ओपन (ऑपरेशंस मार्केट-OMOs) और विदेशी मुद्रा खरीद-बिक्री स्वैप सहित तरलता उपायों का नया दौर घोषित किया, जिसके तहत बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹3 ट्रिलियन डाले जाएंगे।
 - RBI will purchase Government of India securities worth ₹2 trillion through OMOs in four tranches of ₹50,000 crore each on 29 December, 5 January, 12 January, and 22 January.
 - RBI 29 दिसंबर, 5 जनवरी, 12 जनवरी और 22 जनवरी को चार ट्रैंचों में प्रत्येक ₹50,000 करोड़ के हिसाब से ₹2 ट्रिलियन के सरकारी प्रतिभूतियां OMO के माध्यम से खरीदेगा।
 - Additionally, RBI will conduct a three-year USD-INR buy-sell swap of \$10 billion on 13 January.
 - इसके अलावा, RBI 13 जनवरी को 3-वर्षीय USD-INR खरीद स्वैप बिक्री-\$10 बिलियन का कार्य करेगा।
 - Net liquidity in the banking system was in deficit by ₹54,852 crore, and RBI has infused ₹1.45 trillion of durable liquidity in December so far.
 - बैंकिंग प्रणाली में शुद्ध तरलता ₹54,852 करोड़ की कमी में थी, और दिसंबर में अब तक RBI ने ₹1.45 ट्रिलियन की स्थायी तरलता डाली है।
-

Ques: 'Pay Later with BharatPe', recently in news, is launched in partnership with which bank?

प्रश्न रहा में समाचारों में ही हाल : 'Pay Later with BharatPe' किस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया है?

- A) State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- B) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- D) YES Bank / यस बैंक
- E) Axis Bank / एक्सिस बैंक

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- BharatPe, in partnership with YES Bank, launched 'Pay Later with BharatPe', an instant Credit on UPI product powered by NPCI.
- भारतपे ने YES बैंक के सहयोग से NPCI द्वारा संचालित UPI आधारित इंस्टेंट क्रेडिट उत्पाद 'Pay Later with BharatPe' लॉन्च किया है।
- The facility offers interest-free credit for up to 45 days, with limits refreshed upon repayment, and flexible EMI options of 3–12 months.
- यह सुविधा 45 दिनों तक ब्याजहै करती प्रदान क्रेडिट मुक्त-, भुगतान के बाद लिमिट रिफ्रेश होती है और 3–12 महीनों की लचीली EMI विकल्प उपलब्ध कराती है।

About YES Bank:

- Established : 2004
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Prashant Kumar
- Tagline : Life Ko Banao Rich

Ques : What recent change did Nepal make regarding carrying Indian currency?

नेपाल ने भारतीय मुद्रा ले जाने को लेकर हाल ही में क्या बदलाव किया है?

- A) Allowed carrying ₹1,000 notes up to ₹50,000 / ₹50,000 तक ₹1,000 के नोट ले जाने की अनुमति
- B) Lifted ban and allowed ₹200 and ₹500 notes up to ₹25,000 / प्रतिबंध हटाकर ₹200 व ₹500 के नोट ₹25,000 तक की अनुमति
- C) Allowed only ₹100 notes without any limit / केवल ₹100 के नोट बिना सीमा के

D) Allowed Indian currency only for Nepali citizens / केवल नेपाली नागरिकों के लिए भारतीय मुद्रा की अनुमति

E) Continued the ban on high-denomination Indian notes / उच्च मूल्यवर्ग के भारतीय नोटों पर प्रतिबंध जारी

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Government of Nepal has lifted its decade-long ban on carrying high-denomination Indian currency.
 - नेपाल सरकार ने उच्च मूल्यवर्ग की भारतीय मुद्रा ले जाने पर लगे लगभग एक दशक पुराने प्रतिबंध को हटा दिया है।
 - Under the revised currency rules, Indian banknotes of ₹200 and ₹500 are permitted.
 - संशोधित मुद्रा नियमों के तहत ₹200 और ₹500 के भारतीय नोटों की अनुमति दी गई है।
 - The maximum limit allowed is ₹25,000 per person.
 - प्रति व्यक्ति अधिकतम सीमा ₹25,000 तय की गई है।
 - The rule applies to both Nepali and Indian citizens and is valid for carrying currency from India to Nepal and from Nepal to India.
 - यह नियम नेपाली और भारतीय दोनों नागरिकों पर लागू होता है तथा भारत से नेपाल और नेपाल से भारत मुद्रा ले जाने की अनुमति देता है।
 - The decision follows amendments made by the Reserve Bank of India to FEMA and the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) Regulations, 2015.
 - यह निर्णय RBI द्वारा FEMA और विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम (आयात एवं निर्यात), 2015 में किए गए संशोधनों के बाद लिया गया है।
 - RBI's amendment allows Indian, Nepali, and Bhutanese nationals to carry higher-denomination Indian notes while travelling to and from India.
 - RBI के संशोधन के अनुसार भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिक भारत की यात्रा के दौरान उच्च मूल्यवर्ग के भारतीय नोट ले जा सकते हैं।
-

Ques: The World Bank approved a loan of ₹9,821 crore for which organisation to refinance debt related to the Eastern Dedicated Freight Corridor (EDFC) project?

विश्व बैंक ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) परियोजना से जुड़े ऋण के पुनर्वित्तपोषण के लिए ₹9,821 करोड़ का ऋण किस संस्था को दिया है?

- A) Indian Railways / भारतीय रेल
- B) Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) / रेल विकास निगम लिमिटेड
- C) Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) / डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- D) National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL) / नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
- E) Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFC) / इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The World Bank has provided a loan of ₹9,821 crore to the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL).
- विश्व बैंक ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) को ₹9,821 करोड़ का ऋण प्रदान किया है।
- The loan is routed through the Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFC).
- यह ऋण इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRFC) के माध्यम से दिया गया है।
- The objective of the loan is to refinance DFCCIL's existing World Bank currency debt for the Eastern Dedicated Freight Corridor (EDFC) project.
- इस ऋण का उद्देश्य ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) परियोजना के लिए DFCCIL के मौजूदा विश्व बैंक मुद्रा ऋण का पुनर्वित्तपोषण करना है।
- The refinancing is expected to improve debt sustainability and support efficient freight transportation infrastructure in India.
- यह पुनर्वित्तपोषण ऋण स्थिरता में सुधार करेगा और भारत में कुशल माल परिवहन अवसंरचना को समर्थन देगा।

Ques: What recent decision did the Reserve Bank of India (RBI) take regarding Phase-II of the Continuous Clearing and Settlement on Realisation (CCSR) under the Cheque Truncation System (CTS)?

आरबीआई ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के तहत निरंतर क्लियरिंग एवं सेटलमेंट (CCSR) के फेज-II को लेकर हाल ही में क्या निर्णय लिया है?

- A) Implemented Phase-II from 3 January 2026 / 3 जनवरी 2026 से फेज-II लागू किया
- B) Cancelled the CCSR framework permanently / CCSR ढांचे को स्थायी रूप से रद्द कर दिया
- C) Postponed Phase-II implementation until further notice / फेज-II के क्रियान्वयन को अगले आदेश तक स्थगित किया
- D) Reduced cheque settlement time to T+0 immediately / चेक सेटलमेंट समय को तुरंत T+0 कर दिया
- E) Allowed banks to process cheques only after banking hours / बैंकों को केवल बैंकिंग समय के बाद चेक प्रोसेस करने की अनुमति दी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India has postponed the implementation of Phase-II of Continuous Clearing and Settlement on Realisation (CCSR) under the Cheque Truncation System, which was earlier scheduled for 3 January 2026, until further notice.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम के तहत निरंतर क्लियरिंग एवं सेटलमेंट (CCSR) के फेज-II के क्रियान्वयन को, जो पहले 3 जनवरी 2026 के लिए निर्धारित था, अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है।
- Phase-I, which was launched on 4 October 2025, will continue and enables banks to digitally process and confirm cheques on a continuous basis during working hours.
- 4 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया फेज-I जारी रहेगा, जिसके तहत बैंक कार्य घंटों के दौरान डिजिटल रूप से चेक प्रोसेस और कन्फर्म कर सकते हैं।
- RBI has revised CTS working hours: the cheque presentation session will now run from 9 AM to 3 PM instead of 10 AM to 4 PM.
- आरबीआई ने CTS के कार्य समय में बदलाव किया है, जिसके तहत अब चेक प्रस्तुतिकरण सत्र 10 बजे से 4 बजे के बजाय 9 बजे से 3 बजे तक होगा।
- Banks have been directed to confirm or reject cheques between 9 AM and 7 PM, earlier 10 AM to 7 PM.
- बैंकों को अब 10 बजे से 7 बजे के बजाय 9 बजे से 7 बजे तक चेक की पुष्टि या अस्वीकृति

करने का निर्देश दिया गया है।

- Under Phase-II, the cheque item expiry time was proposed to be reduced to T+3 hours (transaction date plus 3 hours), compared to the existing T+1 or T+2 settlement framework.
- फेज-II के तहत चेक की सेटलमेंट समयसीमा को T+1 या T+2 के बजाय T+3 घंटे देन-लेन) + तारीख की 3 घंटे प्रस्त का करने (ाव था।

Ques: The report titled “Rewiring GVCs in a Changing Global Economy” has been jointly published by which of the following institutions?

“Rewiring GVCs in a Changing Global Economy” शीर्षक वाली रिपोर्ट निम्नलिखित में से किन संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है?

- A) Asian Development Bank, World Trade Organization, World Economic Forum / एशियाई विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक मंच
- B) International Monetary Fund, World Bank, OECD / अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, OECD
- C) United Nations, World Bank, WTO / संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, WTO
- D) World Economic Forum, OECD, UNDP / विश्व आर्थिक मंच, OECD, UNDP
- E) Asian Development Bank, IMF, World Bank / एशियाई विकास बैंक, IMF, विश्व बैंक

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The report “Rewiring GVCs in a Changing Global Economy” is jointly published by the Asian Development Bank (ADB), World Trade Organization (WTO), and World Economic Forum (WEF).
- “Rewiring GVCs in a Changing Global Economy” रिपोर्ट एशियाई विकास बैंक (ADB), विश्व व्यापार संगठन (WTO) और विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है।
- GVCs refer to Global Value Chains, where different stages of production occur across multiple countries, with each stage adding value.
- GVCs का अर्थ ग्लोबल वैल्यू चेन है, जिसमें उत्पादन के विभिन्न चरण अलग-अलग देशों में अलग-अलग हैं जोड़ता मूल्य चरण प्रत्येक और हैं होते

- The report highlights that globalisation is being rewired rather than reversed, driven by technological changes, green transition, and shifting geopolitical conditions.
- रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्वीकरण उलट नहीं रहा है, बल्कि तकनीकी बदलाव, हरित संक्रमण और बदलती भूपरिस्थिति राजनीतिक-यों के कारण नए सिरे से ढल रहा है।
- GVCs account for 46.3% of global trade, slightly lower than the 2022 peak of 48%, indicating resilience despite global challenges.
- वैश्विक व्यापार में GVCs की हिस्सेदारी 46.3% है, जो 2022 के 48% के शिखर से थोड़ी कम है, फिर भी यह लचीलापन दर्शाती है।
- India has strengthened its integration into GVCs, driven mainly by strong growth in digital services exports, and is among the top 10 value-adding economies globally.
- भारत ने डिजिटल सेवा निर्यात की मजबूत वृद्धि के कारण GVCs में अपनी भागीदारी को मजबूत किया है और वह विश्व की शीर्ष 10 मूल्य है। शामिल में अर्थव्यवस्थाओं वर्धक-

Ques: What is the purpose of the centralized portal launched by the National Payments Corporation of India (NPCI)?

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा शुरू किए गए केंद्रीकृत पोर्टल का उद्देश्य क्या है?

- A) To allow international UPI payments / अंतरराष्ट्रीय UPI भुगतान की अनुमति देना
- B) To track failed UPI transactions only / केवल असफल UPI लेनदेन को ट्रैक करना
- C) To view, manage, and revoke UPI Autopay standing instructions from one platform / एक ही प्लेटफॉर्म से UPI ऑटोपे स्थायी निर्देशों को देखना, प्रबंधित करना और रद्द करना
- D) To provide loans through UPI / UPI के माध्यम से ऋण प्रदान करना
- E) To increase UPI transaction charges / UPI लेनदेन शुल्क बढ़ाना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The National Payments Corporation of India (NPCI) has launched a centralized portal (npci.org.in) to enable users to view, manage, and revoke all UPI Autopay standing instructions from a single platform.

- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने npci.org.in नामक एक केंद्रीकृत पोर्टल शुरू किया है, जिससे उपयोगकर्ता एक ही प्लेटफॉर्म से सभी UPI ऑटोपे स्थायी निर्देशों को देख, प्रबंधित और रद्द कर सकते हैं।
- All UPI ecosystem members, including banks and payment service providers, must implement these reforms by December 31, 2025, to enhance consumer protection and transparency.
- उपभोक्ता संरक्षण और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी UPI इकोसिस्टम सदस्य, जिनमें बैंक और भुगतान सेवा प्रदाता शामिल हैं, को 31 दिसंबर 2025 तक इन सुधारों को लागू करना अनिवार्य है।
- In November 2025, the top 10 banks processed 926 million UPI Autopay transactions, up from 530.5 million in November 2024, reflecting rapid growth in recurring digital payments.
- नवंबर 2025 में शीर्ष 10 बैंकों ने 926 मिलियन UPI ऑटोपे लेनदेन संसाधित किए, जो नवंबर 2024 के 530.5 मिलियन से काफी अधिक हैं, और यह आवर्ती डिजिटल भुगतानों में तेज वृद्धि को दर्शाता है।
- State Bank of India (SBI) emerged as the largest processor with 290 million UPI Autopay transactions, while Airtel Payments Bank recorded the fastest growth, rising from 25.6 million to 89.7 million transactions within a year.
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 290 मिलियन UPI ऑटोपे लेनदेन के साथ सबसे बड़ा प्रोसेसर बना, जबकि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सबसे तेज वृद्धि दर्ज की, जिसके लेनदेन एक वर्ष में 25.6 मिलियन से बढ़कर 89.7 मिलियन हो गए।

About NPCI :

- Established : 2008
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Dilip Asbe

Ques: Which bank has partnered with Fyno to deploy a unified customer communication platform?

एकीकृत ग्राहक संचार प्लेटफॉर्म को लागू करने के लिए Fyno ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है?

- A) Kerala Grameena Bank / केरल ग्रामीण बैंक
- B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- C) Canara Bank / केनरा बैंक

D) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा

E) Indian Bank / इंडियन बैंक

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Fyno has partnered with Kerala Grameena Bank (KGB) to deploy a unified customer communication platform.
- Fyno ने केरल ग्रामीण बैंक (KGB) के साथ एकीकृत ग्राहक संचार प्लेटफॉर्म को लागू करने के लिए साझेदारी की है।
- Fyno is an intelligent communications hub designed for banks and financial services institutions.
- Fyno बैंकों और वित्तीय सेवा संस्थानों के लिए डिज़ाइन किया गया एक इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन हब है।
- The platform helps manage, govern, and automate customer communications across the banking network.
- यह प्लेटफॉर्म बैंकिंग नेटवर्क में ग्राहक संचार के प्रबंधन, शासन और स्वचालन में मदद करता है।
- Key features include centralized management of all customer communications and the ability to create, manage, and update communication templates consistently.
- इसकी प्रमुख विशेषताओं में सभी ग्राहक संचार का केंद्रीकृत प्रबंधन और संचार टेम्पलेट्स को बनाने, प्रबंधित करने व अपडेट करने की सुविधा शामिल है।
- The Chief Executive Officer and Co-Founder of Fyno is Aniketh Jain.
- Fyno के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सह-संस्थापक-

Ques: Which company has launched the health insurance product “Galaxy Twin 360” for young adults?

युवा वयस्कों के लिए “Galaxy Twin 360” स्वास्थ्य बीमा उत्पाद किस कंपनी ने लॉन्च किया है?

- A) Star Health Insurance / स्टार हेल्थ इंश्योरेंस
- B) HDFC ERGO Health Insurance / एचडीएफसी एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस
- C) Care Health Insurance / केयर हेल्थ इंश्योरेंस

- D) ICICI Lombard Health Insurance / आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ इंश्योरेंस
E) Galaxy Health Insurance / गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Galaxy Health Insurance, promoted by V Jagannathan and TVS Group's Venu Srinivasan, has launched a new health insurance product named "Galaxy Twin 360".
- वी ने इंश्योरेंस हेल्थ गैलेक्सी प्रवर्तित द्वारा श्रीनिवासन वेणु के गुप टीवीएस और जगन्नाथन . "Galaxy Twin 360" नामक नया स्वास्थ्य बीमा उत्पाद लॉन्च किया है।
- The product is targeted at young adults aged between 18 and 45 years.
- यह उत्पाद 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवा वयस्कों को लक्षित करता है।
- Galaxy Twin 360 is available under three plans: Core, Max, and Ultra.
- Galaxy Twin 360 तीन योजनाओं—Core, Max और Ultra—में उपलब्ध है।
- Key features include IPD (Inpatient Department) coverage, high-value OPD (Outpatient Department) benefits, and wellness services.
- इसकी प्रमुख विशेषताओं में आईपीडी कवर (डिपार्टमेंट इनपेशेंट), उच्च ओपीडी मूल्य-हैं। शामिल सेवाएँ वेलनेस और लाभ (डिपार्टमेंट आउटपेशेंट)

Ques: What change has SEBI made regarding eligibility for a Basic Services Demat Account (BSDA)?

बेसिक सर्विसेज डिमैट अकाउंट (BSDA) की पात्रता को लेकर SEBI ने क्या बदलाव किया है?

- A) Increased the BSDA holding limit to ₹20 lakh / BSDA होल्डिंग सीमा को ₹20 लाख तक बढ़ाया
- B) Included ZCZP bonds in valuation threshold / ZCZP बॉन्ड को मूल्यांकन सीमा में शामिल किया
- C) Excluded ZCZP bonds and delisted securities from valuation threshold / ZCZP बॉन्ड और डीलिस्टेड सिक्योरिटीज को मूल्यांकन सीमा से बाहर किया
- D) Abolished BSDA accounts altogether / BSDA खातों को पूरी तरह समाप्त कर दिया
- E) Made BSDA mandatory for all investors / सभी निवेशकों के लिए BSDA अनिवार्य कर दिया

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has decided to exclude Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) bonds and delisted securities from the valuation threshold used to determine eligibility for a Basic Services Demat Account (BSDA).
 - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने BSDA की पात्रता तय करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन सीमा से ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल (ZCZP) बॉन्ड और डीलिस्टेड सिक्योरिटीज को बाहर करने का निर्णय लिया है।
 - As per the revised norms, the value of ZCZP bonds and delisted securities will not be counted while checking whether an investor's holdings are within the ₹10 lakh BSDA limit.
 - संशोधित नियमों के अनुसार, ₹10 लाख की BSDA सीमा की जांच करते समय ZCZP बॉन्ड और डीलिस्टेड सिक्योरिटीज के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा।
 - These changes will come into effect from March 31, 2026, and are aimed at supporting small investors by allowing them to continue availing BSDA benefits despite such holdings.
 - ये बदलाव 31 मार्च 2026 से लागू होंगे और छोटे निवेशकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए हैं, ताकि वे ऐसे निवेश होने के बावजूद BSDA के लाभ ले सकें।
 - A Basic Services Demat Account (BSDA) is a simplified demat account introduced by SEBI in 2012 to reduce maintenance charges for investors with relatively small portfolios.
 - बेसिक सर्विसेज डिमैट अकाउंट (BSDA) SEBI द्वारा 2012 में शुरू किया गया एक सरल डिमैट खाता है, जिसका उद्देश्य छोटे पोर्टफोलियो वाले निवेशकों के लिए रखरखाव शुल्क कम करना है।
-